Vol. I
No. 10



Monday,
8th March, 1954

HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

DEBATES

Official Report

PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTENTS

GOVERNMENT PRESS
HYDERABAD-DN.
1954

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

MONDAY, THE 8TH MARCH, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock.

[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

Questions & Answers

(*See Part I*)

Budget--General Discussion

مسٹر اسپیکر ۔ اب سوالات کا وقت ختم ہوچکا ہے ۔ اب بجٹ پر جنرل ڈسکشن شروع ہوگا ۔ ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ۸، ۹ اور ۱۰۔ مارچ ان تین دنوں میں ڈسکشن ختم ہو جانا چاہئے ۔ تیسرے دن میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل فینانس منسٹر کو جواب کے لئے ڈیڑھ گھنٹہ لگیگا ۔

मिनिस्टर फॉर फॉयनान्स, स्टॅटिसटिक्स, कस्टम्स, कामर्स अँड अिडस्ट्रीज (श्री. वि. के. कोरटकर) :—अेक डेढ घंटा तो काफी हो जायेगा ।

مسٹر اسپیکر ۔ ایک دوسری چیز میں عرض کردینا چاہتا ہوں کہ بجٹ پر ڈسکشن کے دوران میں جملہ ڈپارٹمنٹس پر تنقید ہوتی ہے اسلئے گورنمنٹ کا کم سے کم ایک ممبر یہاں حاضر رہے ۔ تاکہ حکومت ڈسکشن پر توجہ کرسکے ۔ اس لئے کہ ڈسکشن کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے علم میں یہ باتیں لائی جائیں ۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن پارٹی یا کسی اور پارٹی کی جانب سے خواہ مخواہ تو یہ سب باتیں نہیں کہی جاتیں ۔ ممکن ہے انکے انفرمیشن میں کچھ غلطی ہو لیکن گورنمنٹ کو سب باتوں سے پوری طرح واقف ہونا چاہئے ۔

श्री. रतनलाल कोटेचा (पाटोदा) :—मैं अेक अिनफरमेशन (Information) पूछना चाहता हूं कि यहां जो डिसकशन्स होते हैं क्या अुसके नोट्स कनसर्न डिपार्टमेंट के पास भेजे जाते हैं ?

مسٹر اسپیکر ۔ یہاں جو اسپیچس ہوتی ہیں انکا ہر لفظ لکھا جاتا ہے اسکی کاپیاں چھپتی ہیں اور ہر ممبر کو اسکی کاپیاں ملتی ہیں ۔

श्री. रतनलाल कोटेचा :—मेरा यह सुझाव है कि यहां जो डिसकशन होते हैं अुसके रिपोर्ट और नोट्स कनसर्न डिपार्टमेंट के पास भेजने चाहियें ।

श्री. वि. के. कोरटकर :—डिसकशन के नोट्स अुसी वक्त कनसर्न्ड मिनिस्टर्स लेते हैं और अुसके अूपर जरूरी अॅक्शन (Action) लिया जाता है। हर डिपार्टमेंट को भेजने का तरीका नहीं है।

منسٹر فار میڈیکل پبلك هلیتھ اینڈ رورل ری کنسٹرکشن (شری مہدی نواز جنگ)
اسکے علاوہ چیف منسٹر کا ایک سرکیولر ھے کہ ھر ڈپارٹمنٹ کے نمائندے یہاں موجود رہیں اور متعلقہ باتوں کا نوٹ لیکر منسٹر کو اسکی اطلاع دیں ..

श्री. व्ही. डी. देशपांडे (अिप्पागुडा) :—अध्यक्ष महोदय, असेंब्ली के पांच सालों में से तीसरे साल का बजट हमारे सामने आया है। अिस वक्त पिछले सालों के बजट हमारे सामने किस तरह से आते रहे अिसको देखें, तो वह नामुनासिब न होगा।

Mr. Speaker : Shall I fix time-limit? I generally wish to leave the matter to the discretion of the hon. Members.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—वक्त का ख्याल रखा जायगा।

राजप्रमुख के अॅड्रेस (Address) के वक्त मैंने अिस चीज को रखा था कि हिंदुस्तान में आज दो सोशल आर्डरों में अेक कश्मकश जारी है, वह अेक पुराना ढांचा और निजाम है जो हिंदुस्तान की बदतर हालत को जारी रखना चाहता है, अुसी तरह से जो जमीनदारी ढांचा है अुसको बरकरार रखना चाहता है, और हुकूमत अिन शक्तियों को अपने फायदे के लिये अिस्तेमाल करना चाहती है।

(MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR)

दूसरी वह बढती हुअी कुव्वत है जो चाहती है कि जमीनदारी सिस्टम को खतम करें, सनअतों को बढायें, बैरूनी सरमायेदारों के जरियेसे जो मुल्क मे लूट-खसोट होती है अुसको बंद करे, और यहां पर अेक अैसी हुकूमत का ढांचा तैयार करें जो सस्ता हो, अेफिशिअंट (Efficient) हो, और अव्वाम के मसायल को बहुत जल्दी से और अच्छी तरह से हल कर सके। अिस तरह से आज हिंदुस्तान में अेक टग ऑफ वार (Tug of war) अेक रस्सी खेंच, दो समाज रचनाओं में जारी है और अिसमें आज की हुकूमत दरमियान में खडी होकर क्या अव्वाम की ख्वाहिशात को पूरा कर रही है, या जो चीजें दिन ब दिन खतम होती जानी चाहिये, कमजोर होती जानी चाहियें, अुन्हे अिमदाद कर रही है या नहीं अिस लिहाज से आज की हुकूमत के कारनामों और अिस बजट की तरफ देखना पडेगा। पिछले साल से हम महसूस कर रहे हैं कि अव्वाम की जो मांगें हैं अुनको पूरा करने के बारे में दिखावे के तौर पर हुकूमत की तरफ से वादे तो किये जाते हैं लेकिन अुसके साथ साथ हुकूमत का दूसरा भी मूव्ह (Move) है जो अिस स्टेटस को (Status quo) की तरफ, अिस फ्यूडल सिस्टम (Feudal system) की तरफ मुडा हुआ है, और अुनका नुकसान कम से कम हो, और अुनके ख्वाहिशात और फायदे जहांतक होसके कायम रखसके अिसलिये हुकूमत भरसक कोशिश करती रहती है। अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि हुकूमत के दो मुंह, टू फेसेस (Two faces) हैं अेक अव्वाम की तरफ है और दूसरा जागीरदारों, बडे बडे कारखानदारों और विदेशी सरमायेदारों की तरफ है। मुझे अिसमें शक नहीं कि अिस रस्सीखेंच में आखिर अव्वाम की कुव्वतें कामयाब होंगी

वाली है, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अेक नया समाज,अेक नया स्टेट, पीपल्स डेमोक्रेटिक स्टेट (People's Democratic State) कायम करना है, क्या वह अिस पुराने ढांचे के अंदर आसानी से होगा या अुसके लिये आपरेशन करना होगा। अिस लिहाज से हुकूमत के कारनामों और अिस बजट की तरफ देखता हूं। अव्वाम की कुव्वतों ने अब तक कुछ थोडी भी कामयाबी हासिल की है, यह मैं हाअुस के सामने रखना चाहता हूं। पिछले दो साल से हम अिस चीज की मांग कर रहे थे कि सर्फेखास का जो ५० हजार रुपये का मुआवजा है जोकि आय. जी. में करीब करीब ४२ लाख होता है अुसको खतम करना चाहिये। अव्वाम की अिस मुसलसिल मांग की वजह से हम अिस वक्त अिस बजट में देख रहे है कि अिस साल हुकूमत ने मजबूर हो कर आला हजरत-जो राजप्रमुख का अुर्दू मे तर्जुमा है-वह कैसे बनाया गया है मालूम नही--लेकिन अुसमें करीब करीब २१ लाख रुपयों की कमी की गअी है। दूसरी बात कॅश ग्रांटस (Cash grants) और मनसब के तौर पर हर साल जो रक्कम दी जाती है अुनको भी खतम करना चाहिये यह भी अव्वाम की पुरजोर माग रही है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया फ्यूडल अेलीमेंटस (Feudal elements) को जिस हद तक हो सके डिफेन्ड (Defend) करने का अिस हुकूमत का अेक पेशा-सा हो गया है। अुसके लिहाज से हाला कि हुकूमत की तरफ से हाअुस के सामने वादे किये जाते है लेकिन वे पूरे नही होते। पिछले साल बजट के वक्त बताया गया था कि ये १३ लाख रुपये देना बंद किया जायगा लेकिन सप्लीमेंटरी बजट के वक्त यह कहा गया कि बहुत सी कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम अिस वादे को पूरा नहीं कर सके और यह वायदा किया गया कि आयंदा साल हम अिसको खतम करेंगे। अिस तरह से मैं हाअुस के सामने यह रख रहा था कि किस तरह की कश्मकश दो समाजरचनाओं के बीच आज चल रही है। अव्वाम की कुव्वतें फ्यूडल सिस्टम को खतम करना चाहती हैं, और आज की हुकूमत के लोग अिसको डिफेन्ड (Defend) करना चाहते हैं। अूपरी तौर पर कहा जाता है कि हम अिसको खतम करना चाहते है लेकिन अमलन अिसको सेबोटेज (Sabotage) किया जाता है। पिछले दो साल का हमारा अनुभव यही रहा है और अब तीसरा बजट हमारे सामने आया है। अिस साल में क्या बात होनेवाली है अिसका आज हमें पता नहीं है। शायद फायनान्स मिनिस्टर साहब यह कह दें कि अिस वक्त भी यह कानून न बन सका अिसलिये अिसको हम खतम नहीं कर सके। अिसके बाद जमीनदारी सिस्टम को खतम करने के बारे में जो वादा किया गया था अुसकी तरफ भी मैं हाअुस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वतनदारी सिस्टम पुराने ढांचे से वरसा के तौर पर हमारे पास आअी है। देहातों में जुल्म और सितम ढानेवाली अगर कोअी सिस्टम है तो वह यही सिस्टम है। अिस सिलसिले में कहा गया था कि अिसके लिये जरूरी कानून हाअुस के सामने लाया जायेगा। यह भी बताया गया कि वेलोडी हुकूमत के जमाने में ही अिसके कानून का ड्राफ्ट (Draft) बन चुका था। तब मेरी समझ में नहीं आता कि पिछले दो सालोंसे यह चीज हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है ? और अिस पुराने ढांचे को क्यों अिस तरह से कायम रखने की कोशिश की जा रही है ? देहातों के अंदर बडे बडे जमीनदारों की तरफ से किसानों की जो लूटखसोट होती है अुसके सिलसिले में अेक कानून हाअुस के सामने लाया गया, और पास हुआ। यह वादा किया जा रहा है कि अुससे किसानों का फायदा होगा, अुनकी हालत अच्छी होगी, अुनकी क्रय शक्ति बढेगी लेकिन दो साल से हम देख रहे हैं कि किसान की परचेसिंग पॉवर (Purchasing power) में कोअी अिजाफा नहीं हुआ। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में हाअुस के सामने

यह जरूर रखा कि जिराअतके अगराज में कुछ अिजाफा हुआ है लेकिन अुसके साथ साथ अुन्होंने यह भी बताया कि कॅश क्राप्स (Cash crops) में और टोटल प्रोडक्शन (Total Production) में कमी हुअी है। अिस साल के लिये कहा जा रहा है कि अुसमें कुछ अिजाफा होगा, लेकिन मुल्क की अगराज के लिहाज से जो पैदावार होनी चाहिये वह हो रही है या नहीं अिसके बारे में मुझे शक है। आयंदा साल हम देखेंगे कि सचमुच किसान ज्यादा पैदा कर रहे हैं या नहीं और अुसकी कुव्वत खरीद बढी है या नहीं। लेकिन अब तक के आदाद देख कर मुझे यह महसूस होता है कि जिस नुमायां तौर पर हमारी जिराअत की पैदावार बढनी चाहिये वह आज के हालात में नहीं बढ रही है। और जब तक पैदावार नहीं बढती, मैं नहीं समझता कि हमारे डेफेसिट (Deficit) बजट का सवाल हल हो सकता है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारी अेक्साअिज (Excise) की आमदनी कम हुअी। अेक्साअिज की जो आमदनी होती है अुसका ताल्लुक किसान की कुव्वत खरीद से होता है क्योंकि वे ही नशीली चीजोंको ज्यादातर अिस्तेमाल करते हैं। मैं अिस सवाल में नहीं जाअूंगा कि शराब का अिस्तेमाल करना अच्छा है या नहीं। अगर वह बुरा होता तो हुकूमत और फायनान्स मिनिस्टर साहब, सेंदी के झाड कैसे बढाये जायें, अुनसे ज्यादा शराब कैसे पैदा हो, अिस फिकर से अुसके लिये ज्यादा रक्कमा मुहैया करने की तरफ नहीं जाते। अिसीलिये मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रोहीबीशन (Prohibition) अच्छा है या नहीं, लेकिन हमें यह जरूर महसूस हो रहा है कि अगर किसान की कुव्वत खरीद बढ जाती तो अेक्साअिज की आमदनी में कमी न होती, और अिसीलिये यह जो कहा जा रहा है कि किसान की हालत अच्छी हो रही है, अुसका सुबुत हमारे सामने नहीं है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि अनअेम्प्लायमेंट (Unemployment) अुतना अेक्यूट (Accute) नहीं है, जितना कि समझा जाता है। अिसीलिये मेरे दोस्त ने कहा " जितना होना चाहिये " मै नहीं समझता कि हुकूमत चाहती है कि अनअेम्प्लायमेंट होना चाहिये लेकिन अनअेम्प्लायमेंट के सिलसिले में हुकूमत की जो काम्प्लीसंट अेटीटयूड (Compleasant Attitude) है अुससे बेरोजगारी का सवाल हल नहीं होगा। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ रही है और कारखाने बंद हो रहे हैं, यह वाक्या है। अेक या दो कारखानेही बंद हुअे हैं और जो बेरोजगारी हो रही है अुसमें डरने की कोअी बात नहीं है अैसा समझना हुकूमत के लिये ठीक नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिस मआशी बोहरान के संकट के बारे में हम बहुत दिनों से सोच रहे थे वह आज शुरू हो गया है और वह अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ रहा है। अनाज की कीमतों के बारे में सोचा जा रहा था कि ये कीमतें कायम रहेंगी, या कम होंगी। पिछले अेक दो महीनें के हालात से मालूम होता है कि अनाज की कीमतें कअी मुकामात पर ५० फीसद तक भी कम हो रहीं हैं। चूंकि यहां के व्यापारियोंने मध्य प्रदेश से अनाज मंगवाया है अिसीलिये यह आरजी तौर पर कमी हुअी है या यह अेक दायमी चीज है अिसके बारे में कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अखबारों से और दीगर मालूमात से अैसा मालूम होता है कि बाकी प्रांतों में भी ये कीमतें गिर रही हैं। अगर यह सही है तो हिंदुस्तान में स्लम्प (Slump) आ रहा है, और अुसका मुकाबला करने का सवाल हमारे सामने आ जाता है। अिन कीमतों के साथ हमारे किसानों का संबंध है, और किसानों की हालत से हमारे रेव्हिन्यू का संबंध है, अिसलिये अिसका ख्याल करना जरूरी है।

हमारी आमदनी और खर्च की हालत की तरफ हम देखें तो मैं हाअुस को बताअूंगा कि किसी भी मुल्क का मवाजना स्टेबल (stable) और ग्रोअिंग (growing) होना चाहिये। पिछले तीन साल के मवाजने की तरफ हमदेखें तो जो आदाद हमारे सामने हैं अुनसे पता चलता है कि हमारा खर्च ६३ करोड ७६ लाख है, और हमारे रिजर्व्हज् ५२ करोड ८८ लाख के बताये जाते हैं। अिससे साफ जाहिर होता है कि हमारे रिजर्व्हज और खर्च में काफी तफावत है तकरीबन ११ करोड का फर्क है। कॅश बॅलेन्सेस ५ करोड ३३ लाख के बताये गये हैं। अिसके पहले हर साल जो ओपनिंग कॅश बॅलेन्सेस (Opening cash balances) हमारे सामने बजट के जरिये आये हैं अुनकी तरफ मैं हाअुस की तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। अुनसे पता चलता है कि हमारे हुकूमत के आज के कारखाने की हालत क्या है। १९५२-५३ में ओपनिंग बॅलेन्स १४ करोड का था १९५३-५४ में १२ करोड का था, और रिवाअिज्ड बजेट में वह ११ करोड था, लेकिन अिस साल वह ५ करोड ३३ लाख का रह गया है। अिसके माने यह है कि हमारे पास १ अप्रेल से जो कारोबार शुरू होने वाला है अुस लिये सिर्फ ५ करोड ३३ लाख की रक्कम है। अिसमें फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया है कि यह रक्कम कुछ बरायेनाम है। अिससे लंदन में १ करोड ९७ लाख रुपये पडे हुअे हैं। अिस रक्कम को भी अिसमें से निकाल दिया जाय तो हमारा कॅश बॅलेन्स सिर्फ ३ करोड ३६ लाख का रह जाता है। और नोट में यह भी बताया गया है कि सव्वा तीन करोड का जो कर्जा हुकूमतने हाल ही में हासिल किया है वह अिसीमें शामिल है। यानी यह रक्कम भी अिसमें से निकाल दी जाय तो हुकूमत के पास आज कॅश बॅलेन्स के तौर पर करीब कुछ भी नही रहता। अैसी हालत में आयदा अेप्रेल से हमारी हुकूमत का कारखाना किस तरह से चलनेवाला है यह सवाल हमारे समने आ जाता है। सालहा साल हमारे कॅश बॅलेन्सेस की हालत बदतर होती जा रही है। १४ करोड से ११ करोड और ११ करोड से ५ करोड तक हम पहुंच गये हैं। कॅश बॅलेन्स की यह हालत है। कर्जे के लिहाज से देखें तो हमारी हुकूमत पर ५५ करोड ६१ लाख रुपये का कर्जा है। अिस साल वह ६३ करोड से भी ज्यादा हो गया है, और आयंदा के लिये हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि हुकूमते हिंद की तरफ से ५ करोड से ज्यादा कर्जा वह हासिल करनेवाली है। यानी आयंदा साल के बजट में ६८ करोड का कर्जा हमारे अूपर होगा। दरमियान में कोअी मॅच्यूअर (Mature) खर्च हो जाय तो अेकाध करोड की कमी हो जायगी। लेकिन आम तौर से यह अंदाजा किया जा सकता है कि ६३ करोड से ७० करोड तक हमारा कर्जा बढनेवाला है। दरमियान में अिसमें और भी अिजाफा नहीं होगा अैसी भी बात नहीं है। हमारे जो रिजर्व्हज् हैं वे भी किस तरह के हैं वह मैं बताना चाहता हूं। २५ करोड सिक्यूरिटीज (Securities) के तौर पर, और २२ करोड शेअर्स के तौर पर कारखानों में लगाये गये हैं। अिसमें से चंद तो अैसे हैं जिनको व्यापारी लिहाज से अच्छा अिनव्हेस्टमेंट नहीं समझा जायगा। सिव्हिल सप्लाय को ६ करोड ४६ लाख की रक्कम दी गअी है। अुसमें से कितनी रक्कम वापस आ सकती है अिसके बारे में फायनान्स मिनिस्टर स्पष्टीकरण कर दें तो मुनासिब होगा। लोकल अिंडस्ट्रीज को लोन के तौर पर ४ करोड ८४ लाख रुपये दिये गये हैं। अिनमें से कितनी अिंडस्ट्रीज ठीक तरीके पर काम कर रही हैं। और कितनी ओव्हर कपिटलाअिज्ड (Over-Capitalized) हैं कितनी लिक्विडेशन (Liquidation) में जाने के अिमकानात हैं, कितनों को लिक्विडेशन में निकाल ने के बारे में सोचा जा रहा है, और अगर वह सचमुच लिक्विडेशन में चली जावें तो हुकूमत पर अुसका क्या असर होगा, ये सारी बातें फायनान्स मिनिस्टर वाजे कर दें तो जो कॅश बॅलन्सेस बताये जा रहे हैं, अुनमें से कितने असल में हासिल

होने के अिमकानात है जिसका हमे कुछ अंदाजा लग सकता है। कैश बैलन्स के तौर पर कराची मे २ करोड ३५ लाख रुपये पडे है, अैसा बताया जा रहा है। लंदन मे जो रुपये पडे है वे और कराची मे पडे हुअे अेक ही है या अलग अलग है ? और अगर अलग अलग है तो कराची मे पडे हुअे यहा सिर्फ हिसाब के लिये बताये गये है, या सचमुच वे हासिल होनेवाले है ? यह मालूम करने मे हाअुस को सचमुच दिलचस्पी होगी। अिन तमाम चीजों को देखा जाय तो मैने जैसे किसी मुल्क का मवाजना टेस्ट पर लगाने के बारे मे कहा था कि वह स्टेबल और ग्रोअिंग होना चाहिये, अुस टेस्ट पर हमरा आज का बजट नही अुतरता। पिछले साल का बजट पेश करते हुअे अुस वक्त के फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया था कि हैंड टु माअुथ (Hand to Mouth) हमारा बजट है। आज अैसा मालूम हो रहा है कि अिस साल का बजट दिवालिया है, और आयंदा दो साल के बाद जब अिस हुकूमत की बागडोर अिलेक्शन के जरिये बदलवाने का शायद मौका आ जाय तो न मालूम कितना बडा कर्जा अव्वाम के सर पर रख कर यह हुकूमत चली जायगी। यह खौफ हमारे दिल में पैदा हुआ क्योकि गये तीन साल के हुकूमत के कारनामे हमारे सामने है, और मालूम नही आयदा दो साल मे क्या होनेवाला है। अिस तरफ मै हाअुस का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहुंगा। बजट में रिसीटस के मदो को देखने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि रिव्हाअिज्ड अेस्टीमेट १९५२-५३ में २७ करोड ९१ लाख रुपये जमा हो सके। आम तौर पर समझा जाता है कि रिव्हाअिज्ड बजट सेशन के आखरी महीने मे आ जाता है। पिछले साल रिव्हाअिज्ड बजट हमारे सामने मार्च के आखिर में रखा गया था। और हम समझते थे कि स्टेट का खर्च कितना होता है, और आमदनी कितनी होती है, अिसके बारे में हुकूमत का अंदाजा ठीक ठीक होगा। हम यह अुम्मीद नही करते थे कि अिसमें अेक करोड की कमी हो जायेगी। लेकिन हमारे सामने कुछ अेक्चूअल्स २८ करोड २७ लाख के बताये जा रहे हैं, यानी अिसमें अेक करोड से भी ज्यादा कमी वाकये हो रही है। अैसी हालत मे जो रिव्हाअिज्ड अेस्टीमेटस (Revised estimates) के आदाद हमारे रखे जाते है अुन पर हम किस हद तक भरोसा करें यह भी सवाल है। मै समझता हूं कि हमारा फायनान्स डिपार्टमेंट तजुर्बेकार है। अगर अुसके अंदाज मे अिस तरह से करोडों का फर्क पड सकता है तो शायद अुसे वही समझ सकेगा, लेकिन मामूली आदमी अुसको नहीं समझ सकता कि हुकूमत की हालत किस तरह की है, और यह कमी और ज्यादती क्यों हो रही है। अिसके लिये हमारे सामने जो वजूहात पेश किये गये हैं अुनमें कहा गया है कि हमारे लॅंड रेव्हिन्यू मे तकरीबन ५७ लाख की कमी वाकये हुअी है। अेक्साअिज में ८५ लाख की कमी हुअी है। कस्टम्स में कुछ हजार की कमी हुअी है। अिस तरह से जो करोडों की कमी या ज्यादती होती है वह किस वजह से हुअी ? अिसके लिये अगर यह माना जाय कि यहां से जो चीजे बाहर जाती है अुसमे स्मगलिंग (Smuggling) हो रहा है तो अिसके लिये कौन जिम्मेदार है ? और वह स्मगलिंग कितना है, जिससे कि हमारी आमदनी में कमी हुअी है ? अिसके लिये हुकूमत की तरफ से क्या स्टेप्स लिये गये है ? अिन चीजोंको भी फायनान्स मिनिस्टर को हाअुस के सामने रखना चाहिये, क्योंकि यह लाखों रुपयों का मामला है। आमदनी कम होने की अेक वजह यह बताअी गअी है कि लोगों की हालत अच्छी नही है। मेरी समझ में नहीं आता कि अेक वक्त मे हम दो चीजें कैसे कह सकते हैं ? या तो हमें कहना पड़ेगा कि लोगों की हालत खराब है अिसलिये आमदनी कम हो रही है, या यह कहना पडेगा कि लोगों की हालत अच्छी है। लेकिन हमारे अेडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुसूर है, अिसलिये आमदनी कम हो रही है। अेक [illegible] कहना कि लोगों की हालत अच्छी है और दूसरी दफा यह कहना कि खराब है, यह दोनों

कैसे सही हो सकते हैं ? अिस साल अेक्साअिज में ३४ लाख रुपये ज्यादा आने के अिमकानात बताये गये हैं और गये साल में ८५ लाख की कमी बताअी गअी है। जो साल चल रहा है अुसकी क्या हालत है ? अेस्टीमेटस् में बताया गया था कि ५८ करोड की आमदनी हासिल होगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि रिव्हाअिज्ड अेस्टीमेटस् में ५५ करोड ९.२ लाख वसूल होनेवाले हैं। अिसके माने यह है कि दो करोड से ज्यादा रुपये कम वसूल होनेवाले हैं, और अिसमें बताया गया कि अेक्साअिज के तहत ९३ लाख रुपये अिस साल कम होंगे। यह हमारा सब से बडा रेव्हिन्यू का आयटम (Item) है। अिसमें १९५२-५३ में ९५ लाख और अिस साल ९३ लाख की कमी हुअी, और आयंद यह अुम्मीद की जा रही है कि अिस मद में ३८ लाख रुपये बढेंगे। यह अुम्मीद किस बिना पर की जा रही है यह समझ में नहीं आता। आयंदा साल रिव्हाअिज्ड बजट आयेगा तो अुसमें अेक्साअिज की आमदनी में कमी या ज्यादती कितनी होती है अुसका पता चलेगा। लेकिन कागज के हिसाब से हुकूमत गलत अंदाजा करेगी तो जो अंदाजा रखा गया है अुसमें से किस तरह से डेवलपमेंटस् स्कीम्स और दीगर नेशन बिल्डिंग के काम पूरे होंगे और अुन पर क्या असर होगा अिसका पता नहीं लग सकता। दो साल से हमने देखा कि जो अेस्टीमेटेड बजट होता है अुसमें कमी वाकये हुअी है। अिसका असर आखीर कहां पडता है ? वह सिक्यूरिटी सर्व्हिसेस पर या अेडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस पर नहीं पडता बल्कि नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंटस् पर पडता है। अुसके अेस्टीमेटस् में कटौती होती है। सिव्हिल वर्क्स के काम ठीक समय में नही हुअे तो अुसके लिये बडे अच्छे अल्फाज हमारे मिनिस्टर साहब को मिल गये है। ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क (Due to slow progress of work) के माने क्या हैं ? अिस स्लो प्रोग्रेस् के लिये कौन जिम्मेदार है, कौन गुन्हागार है, किसने स्लो प्रोग्रेस किया है, किसीके वक्त पर हुक्म न देने की वजह से यह स्लो प्रोग्रेस हुआ है या और किसी वजह से हुआ है अिसका हमें अंदाजा नहीं लग सकता। अिसीलिये हुकूमत पर मेरा यह चार्ज है कि यह स्लो प्रोग्रेस सिर्फ बताने के लिये है। पहले गलत अंदाजा किया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंटस् का खर्च ज्यादा हो जाता है, अुसको पूरा करने के लिये बादमें डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग के कामों का पैसा लिया जाता है, और आखीर में ये काम अधूरे छोड दिये जाते हैं।

दूसरे जो आमदनी के जरीये हैं अुसमें भी हुकूमत की तरफ से जो तवज्जेह होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है। मैंने पिछले बार कहा था कि अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स अुन तमाम लोगों पर लगाना चाहिये जिनके पास सीलिंग (Ceiling) से ज्यादा जमीन है। ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर, जो अुस वक्त थे, अुन्होंने वादा किया था कि अिस बारे में हुकूमत सोच रही है और बाद में कुछ फैसला करेगी। आयंदा दो साल में हुकूमत कौनसे कदम अुठायेगी अिसपर यह बात मुनहसर रहेगी कि मैं अपनी खुशी जाहिर करूं या अफसोस जाहिर करूं।

हुकूमत ने यह तायुन किया है कि ३६०० रुपये से ज्यादा आमदनी की जमीन जिनके पास है अुनसे वह ज्यादा जमीन हुकूमत वापस अपने कब्जेमें ले सकती है, अपने मॅनेजमेंट में ले सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अैसी हालत में हुकूमत अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स (Agricultural Income Tax) अैसी जमीन से क्यों नहीं ले सकती ? यह कहा जाता है कि अव्वाम को टॅक्स देने के लिये तैयार करना चाहिये। अगर हमारा बजेट डिफिसिट है तो जरूर टॅक्स लेना चाहिये। लेकिन मैं हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि आपने अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स, जिसकी आमदनी १० हजार रुपयोंसे ज्यादा है अैसे लोगों पर रखा है, अुसे पांच हजार आमदनी वाले लोगों

पर क्यो नही लगाया जाता ? सिर्फ ५ लाख रुपये अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स से वसूल हुअे है। हमारे यहा लाखो अेकड जमीन के मालीक है, और अुनसे जो अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स वसूल हुअा बताया जा रहा है वह सिर्फ ५ लाख रुपये का हे। अगर अितनाही वसूल किया जा रहा हू तो अिसमे ज्यादा क्यो नही वसूल किया जाता ? मै हुकूमत से यह अपील करना चाहता हू कि हमारा रेव्हेन्यू बढाने के लिये जो अिस तरह से सरप्लस अिनकम (Surplus income) रखनेवाले लोग है अुनसे ज्यादा टॅक्स वसूल किया जाना चाहिये, जिससे कि हमारी आमदनी मे अिजाफा हो सके।

दूसरी चीज जो मै रखना चाहता हू वह अिनकम टॅक्स के सिलसिले मे है। मैने पहले ही बताया है कि आज कल स्लप (Slump) आ रहा है, और हमे हमारे डेव्हलपमेट प्लॅन्स (Development Plans) पूरे करने है, तो हमे यह देखना होगा कि कौन लोग ज्यादा टॅक्स दे सकते है। मै यह जानता हू कि अिनकम टॅक्स का महकमा हुकूमत हिंद से तालुक रखता है। लेकिन मै बताना चाहता हू कि हुकूमते हिंद के अिमदाद से हमारे जो पचसाला प्लॅन्स है वह पूरे नही होनेवाले है। जरूरत अिस बात की है कि हम ज्यादा रकम मोहिया करे। अिसलिये आज का जो अिनकम टॅक्स है वह हमारे अखराजात पूरे नही कर सकता अिस लिये जरूरत अिस बात की है कि हमारी गव्हर्नमेंट को हुकूमते हिंद के पास यह माग करनी चाहिये कि अिनकम टॅक्स के रेट में अिजाफा होना चाहिये। अगर अैसा न किया गया तो मै बताना चाहता हू कि दिन ब दिन हमारे रेव्हिन्यु के सोर्सेस (Sources) कम होगे, और हमे हर साल खसारे का बजेट रखना नामुमकिन होगा।

अेक चीज मै हाअुस के सामने रखना चाहता हू कि आज की जो हमारी टॅक्स पॉलिसी है अुसमे तरमीम करने की जरूरत है। हुकूमते हिंद ने हाल ही मे अेक टॅक्स अिनक्वायरी कमीटी (Tax Enquiry Committee) बिठाअी है। अुस टॅक्स अेनक्वायरी कमिटी की जो शिफारिसे होगी वह तो हमारे सामने आयेगी। हुकूमते हिंद का बजेट हम देखते है तो मालूम होता है कि अव्वाम की जरूरियात की चीजो पर भी अुन्होने अपने बजेट मे टॅक्स आयद किये है। हुकूमते हिंद ने अिनकम टॅक्स अिनक्वायरी के सिफारिशात तक रूकने की जरूरत नही समझी। अैसे हालात मे हमे भी यहा पर अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स बढाने के लिये रोकने की जरूरत नही है।

दुनिया के जिन जिन देशोमे डेव्हलमेंटप प्लॅन अमल मे लाये जा रहे है, वहा पर पब्लिक सेक्टर (Public sector) से ज्यादा पैसा हासिल करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर मै चीन का बजेट संक्षिप्त मे आपके सामने रखना चाहता हू। चीन के अदर जो टॅक्स वसूल होता है वह किस तरह से किया जाता है वह मै आपको बताना चाहता हू। यह जो बजेट है चीन का अुसमे टॅक्स से जो आमदनी बतायी गअी है वह करीब ५० फीसद की है। अिसमे स्टेट मॅनेजड् जो अिडस्ट्रीज है अुनसे ३० परसेट, अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स से १० परसेट, अिटरेस्ट से ५ परसेट, रिसर्व्ह से १६ परसेंट से और बाकी दूसरे टॅक्ससे आते है।

पिछले तीन सालोसे वहा के पब्लिक सेक्टर से जो आमदनी हो रही है अुसमे अिजाफा होता जा रहा है। चीन का जो बजेट मेरे पास है अुसे हाअुस के सामने रखकर मै यह बताना चाहता [illegible] किस तरह से पब्लिक सेक्टर की आमदनी बढाअी जा रही है।

Percentage of State Revenue derived from tax payment and profits made from State enterprise, and tax payment of State Co-operatives.

पब्लिक सेक्टर में जो आमदनी बढ रही है अुसके आंकडे अिस तरह से हैं। १९५० में ३० परसेंट, १९५१ में ४९ परसेंट, १९५२ में ५० परसेंट और १९५३ में ६० परसेंट।

अिसे देखें तो मालूम होता है कि ३४ करोड से ६० करोड तक की आमदनी पब्लिक सेक्टर से बढी है।

Percentage of State Revenue derived from taxes paid by peasants.

किसानों की तरफ से जो टॅक्स लिया जा रहा है अुसमें अिस प्रकार कमी की जा रही है। १९५० में [illegible] करोड १९५१ में १८ करोड, १९५२ में १७ करोड और १९५३ में १४ करोड, अिस तरह से कमी जा रही है।

Percentage of State Revenue derived from taxtion paid by private industrial and commercial enterprise.

१९५० में ३२. ९२ करोड, १९५१ में २८. ६६ करोड, १९५२ में २४ करोड, और १९५३ में २२ करोड। यह मैंने अिस लिये रखा कि अिस तरह किसानोंपर टॅक्स बढाने से आप वेल फेअर स्टेट (Welfare state) कायम नहीं कर सकते। अिस तरह वेल फेअर स्टेट कायम करने का आपका तसव्वूर गलत है।

हुकूमत जो सनअतें चला सकती है वह अुसे जरूर चलानी चाहिये। मैं अैसा नहीं कहता कि सभी सनअतें हुकूमत को चलानी ही चाहिये। अगर कुछ सनअतों को हुकूमत नहीं चला सकती है तो अुसे न चलाये। जो सनअतें हुकूमत की तरफ से चलाअी जायेंगी वह बराबर चल सकती हैं या नहीं यह देखना चाहिये। मैं मजबूर नहीं करता कि सरकार की जानिबसे सभी सनअतें चलाअी जायें। हैदराबाद ट्रेड युनियन कॉंग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि हमारे स्टेट में जो ओव्हर कॅपिटलाअिज्ड अिंडस्ट्रीज (Over-capitalised Industries) हैं अुन्हे लिक्विडट करना चाहिये।

अब सेल्स टॅक्स के सिलसिलेमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां मलटी पॉंअिट सेल्स टॅक्स (Multi-point Sales Tax) रखा गया है। मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि अिससे हमारी आमदनी बढनेवाली नहीं है। अिस तरह सेल्स टॅक्स कअी जगहों पर जमा किया जाता है। अिसलिये अुसके जमा करने में ज्यादा खर्चा आता है और टॅक्स कम जमा होता है। हमारा सन ५४-५५ वर्ष का जो बजेट है अुसमें सेल्स टॅक्स की आमदनी ४ करोड की बताअी है। मेरा ख्याल है कि अगर यह सेल्स टॅक्स सिंगल पॉंअिट (Single Point) कर दिया जाय तो हमारी आमदनी कम नहीं होगी बल्कि बढेगी। बंबअी में जो तरीका है अुस तरीके से सेल्स टॅक्स रखा जाय तो आमदनी बढेगी। मल्टि पॉंअिट सेल्स टॅक्स सिस्टम(Mul i point Sales Tax system) में ज्यादा लूप होल्स(Loop holes) रहने का डर है। ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर जो,अुस समय थे अुन्होंने वादा किया था कि हम सेल्स टॅक्स सिस्टम अैसी रखेंगे की कि आसान हो। हमारी आमदनी के लिहाज से आज सेल्स टॅक्स को बढाने की जरूरत है तो

आज के सेल्स टॅक्स अॅक्ट में तरमीम करनी चाहिये और मलटि पॉअिंट के बजाय सिंगल पाअिंट टॅक्स वसूल किया जाना चाहिये। अिस बारे मे मैंने अपने ख्यालात पिछली मर्तबा हाअुस में रखें थे और अिसकी जो टेस्ट मेंने पिछले बजेट के वक्त रखी थी अुसे लगते हुअे यदि हमें रेविन्यु बढाना हे तो अुनके लिये जो ज्यादा टॅक्सेस् दे सकते है अुनके टॅक्स बढाने की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है यह सोचना चाहिये। अमीरों पर सेल्स टॅक्स बढा कर गरीबों का टॅक्स कम करना चाहिये, अुसी सुरतमें हम वेल फेयर स्टेट (Welfare state) का नारा पूरा कर सकेंगे। अगर अैसा नही किया जाना है तो अिसका मतलब यह होगा कि चंद लोगों के लिये तो वेल फेयर स्टेट होजायेगा लेकिन अिससे हम आम आवाम का सवाल हल नही कर सकेंगे।

और अेक चीज मैं हाअुस के सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि हमें हमारी सनअतें बढानी चाहिये, तो यह पूछा जाता है कि अिसके लिये पैसा कहां से लाया जाय। मै कहना चाहता हूं कि हमारे पास पैसा काफी है लेकिन अुसे सनअतों में लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, और कहते हैं कि सनअतों को अुठाने के लिये कॅपिटल (Capital) कहा से खडा करेंगे? मैं यह सुझाना चाहता हूं कि जो बडे बडे लोग हैं जिनके पास अेक लाख से ज्यादा रक्कम है अुन्हे कंपलसरीली अिंडस्ट्रीज में कॅपिटल अिनव्हेस्ट करना चाहिये। अिस तरह का कानून बनाया जाय तो जो पैसा आज पडा हुवा है वह काम में आयेगा। अिस तरह यदि कोशिश करनी है तो अुसके लिये जो पैसा हैदराबाद स्टेट के अंदर अनयुज्ड (Unused) है अुसे टॅप (Tap) करने की जरूरत है। मेरा कहना यह नहीं है कि बडे लोगों का पैसा कॉनफिस्केट (Confiscate) किया जाय लेकिन अुनसे कंपलसरी तौर पर जो रक्कम ली जायेंगी अुसके लिये अुन्हे ढाअी परसेंट अिंटरेस्ट दिया जा सकता है। तुगभंद्रा प्रॉजेक्ट के लिये आप निजाम से ४० लाख रुपया लेसकते हैं तो सनअतों के लिये भी दूसरे लोगों से कानून बनाकर भी क्यों न हो, पैसा क्यों नहीं ले सकतें। आपको शायद अिस तरह बार बार निजाम साहब का नाम दोहराया जाना ठीक नहीं मालूम हो रहा होगा। दूसरा रास्ता क्या है, मेरी नजर में तो नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके से हमें हमारी सनअतों को तो फरोग देना होगा। अुसके बिना हमारा सवाल हल नहीं हो सकता। हमारा यह जो अेक सरमायेदारों का और जागीरदारों का चौखट है अुसे हमें तोडनाही पडेगा तभी हमारा यह सवाल हल होगा। यह काम हुकूमते हिंद और हैदराबाद सरकार दोनों का है, वरना यह डेमॉक्रसी कैसे चलेगी? हमारे पास काफी रुपये जेवरात आदि में रखे जाते हैं और अिस लिये मुल्क की सनअतों के लिये कॅपिटिल नहीं मिलता। बडे बड़े लोग अपना पैसा जेवरात में डिपॉझिट कर देते हैं, अुसे जरूर बाहर निकालना चाहिये, और सनअतों के लिये अिस्तेमाल किया जाना चाहिये। मुल्क की तरक्की के लिये अिसे जरूर अिस्तेमाल किया जाना चाहिये। यही हमारा नजरिया है। आप चाहे यह पैसा कॉनफिस्केट (Confiscate) न करें लेकिन यह पैसा अिस्तेमाल तो जरूर होना चाहिये। चाहे तो आप जिनसे अिस तरह पैसा लेंगे अुन्हे ढाअी परसेंट अिंटरेस्ट दे; सनअतों की तरक्की के लिये अिस तरह कुछ न कुछ कदम जरूर अुठाना पडेगा तभी आपकी आमदनी बढ सकती है।

अबतक मैंने आमदनी के बारें में कहा, अब खर्च के बारें में कहना चाहता हूं। आज भी हमारे यहां राजकाज के खर्च का जो तरीका है वह वही अंग्रेजों के तरीके जैसा है। हमारा बजेट भी आज अुसी ढांचे में ढाला जाता है, जैसा पहले रहा करता था। हमने आज तक भी कोअी नया तरीका

नहीं निकाला। पहले जिस तरह अंग्रेज लोग यहां पांच सात हजार मील से आकर बडे पगार लेकर राज्य करते थे, और अुस जमानें में चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, गव्हर्नर्स, व्हाअिसराय, आदि बडे बडे लोगों को जिस तरह तनख्वाहें दी जाती थी अुसी तरह आज भी बडी बडी तनख्वाहें ली जाती है। अिसके कारण हमारा आज का अॅडमिनिस्ट्रेशन (Administration) बहुत टॉप हेवी (Top-heavy) होगया है। जहां पर डेमॉक्रेटिक हुकूमतें बनी हैं वहां यह टॉप हेवी (Top-heavy) अॅडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम करने के लिये पहले कदम अुठांये गये। कल मुझे अेक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब मिले थे, कहते थे कि अगर आप लोग हुकूमत पर आये तो हमारे आज की सॅलरिज है अुसे तो आप कम ही कर देंगे। मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूं मुल्क के फायदे के लिये अगर जरूरी है तो अिस तरह का जो टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन आज है अुसे रोकने के लिये बडी बडी तनख्वाह पाने वालें लोगों की तनख्वाह मे जरूर कमी की जानी चाहिये, कॉमरेड स्टॉलिन सिर्फ ६०० रुपये पगार लिया करता था। चीन का मॉत्सेतुंग को सिर्फ ६०० या ७०० रुपये पगार है। वहां आठ या दस गुना से ज्यादा फरक किसी के भी आमदनी में नही रहता। यह ख्याल आज किया जाता है कि अिस तरह के जो बडे बडे पगार है वह अॅडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये जरूरी हैं। अुसके विना अॅडमिनिस्ट्रेशन नही चलाया जा सकता, लेकिन हम में यह जो गलत ख्याल है अुसे छोडना चाहिये। पहले तो यह ख्याल कॉंग्रेस के लोगों मे भी नहीं था, लेकिन आज कल यह ख्याल कहां से आया मालूम नही। आज का यह जो टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन है अुसे कम करनाही चाहिये। जो बडे अफसर हैं अुनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज देश को आपकी कुरबानी की जरूरत है, आपके जो बडे बडे पगार हैं अुसे आपको खुद हो कर कम करना चाहिये, और छोटे छोटे मुलाजमीन के पगार बढाने चाहियें। अुसके बिना सच्ची डेमॉक्रेटिक हुकूमत नहीं बन सकती। अिसके लिये हमें पहले दिमागी तब्दीली की जरूरत है। अगर पहले दिमागी तबदीली नही आअी तो यह चौखटा जो हम बदलना चाहते हैं वह नही बदल सकते, लेकिन आज अिस बात को मानने के लिये हम लोग तैयार नहीं हैं। आज अिस तरह बडी बडी तनख्वाहें देकर जो टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है अुसे कम करने की जरूरत है, और हम यह तनख्वाहें कम कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि हमारे पुराने कॉन्ट्रक्टस है हमें अुनकी तनख्वाहें तो देनी ही पडेंगे। मै कहता हूं कि अगर कुछ पुराने आय. सी. अेस. लोग रखने की जरूरत है तो अुन्हे अुसी पगार पर रखा जा सकता है। लेकिन अब जो आय. पी. अेस. और आय. अे. अेस. कॅडर के लिये जो नये लोग रिक्रूट (Recruit) किये जाते है अुन्हें भी वही पगार क्यों दिया जा रहा है? अुनके पगार कम क्यों नहीं कर सकते? मुझे अिस बात का बडा ताजुब होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू जैसे लोग होते हुअे भी वह अिसे क्यों नहीं कम कर सकते? अुनके भी ख्यालात कैसे बदल गये? मैं आपके सामने अिस बात को रखना चाहता हूं कि यह चीज तो होगी और होकर ही रहेगी। यह टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन जरूर कम होना चाहिये। चीन में अॅडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस पर बजेट के खर्चे के २० गुना से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता लेकिन हमारे यहां अॅडमिनिस्ट्रेशन पर बजेट के खर्चे के ३० गुना खर्चा होता है।

अब मैं आपके सामने अिस बजेट का अनॅलिसिस (Analysis) रख कर यह बताना चाहता हूं कि अिस बजेट में किस तरह खर्चा रखा गया है।

डायरेक्ट डिमांड रेव्हिन्यु के लिये ३ करोड ३१ लाख रुपये रखे हैं।

डेट सर्विसेस के लिये ३ करोड २२ लाख रुपये रखे हैं।

अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस, जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जेल के लिये ५ करोड के करीब खर्चा रखे हैं।

सोशल सर्विस, सोशल वर्क्स पर ७ करोड ९९ लाख रुपये रखे गये हैं। अिस तरह यदि हम अेक्स्पेंडिचर का अनलेसिस करें तो मालूम होगा कि अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह और सिक्युरिटि सर्विसेस पर १८ परसेंट खर्चा हो रहा है और टॅक्स कलेक्शन पर १२ परसेंट का खर्चा हो रहा है। अिस तरह से अॅडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस और टॅक्स कलेक्शन पर आमदनी का ३० परसेंट का खर्चा हो रहा है। डेट्स अॅन्ड अिंटरेस्ट पर साडेतीन करोड से ज्यादा रक्कम है जो १३ परसेंट होती है। फ्यूडल अॅमिनिटिज पर ६ परसेंट और मिसलेनियस (Miscellaneous) पर ८ परसेंट खर्चा होता है। अिस तरह से आमदनी का ६० परसेंट खर्चा अॅडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात में या निजाम के देने के अखराजात में खर्च होता है और बाकी बचा ४० परसेंट का खर्चा नेशन बिल्डिंग अॅक्टिविटिज (Nation building Activities) पर किया जाता है।

चीन के बजेट को हम देखें तो मालूम होगा कि वहां पर अॅडमिनिस्ट्रेशन पर १० परसेंट का खर्चा होता है। रिझर्व्हज ७ परसेंट रखे जाते हैं। चीन में नेशन बिल्डिंग के काम पर ६० परसेंट का खर्चा होता है और बाकी पैसा मुल्क के डिफेन्स पर खर्च किया जाता है। यह करीब करीब २२ परसेंट तक आता है। हमारे देश से चीन कोअी बहुत बडा देश नहीं है। हमारी आबादी ३२ करोड के करीब है और चीन की आबादी ३५ करोड के करीब है। वहां डिफेन्स पर २२ परसेंट से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता है लेकिन हमारे यहां ५० परसेंट खर्चा किया जा रहा है। वहां पर नेशन बिल्डिंग पर ६० परसेंट खर्चा किया जाता है तो हमारे यहां यह खर्चा ३१ से लेकर ४१ परसेंट तक बढा है। आज हम साढेग्यारह करोड रुपया खर्च कर रहे हैं। मुझे बडा अफसोस होता है कि नेशन बिल्डिंग अॅक्टिविटिज पर हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। आपका आज का जो टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन है अुसमें आपको दुरूस्ती करनी होगी। आज पुलिस पर जो खर्चा किया जाता है वह पहले से तो कम हो गया है लेकिन अुससे भी ज्यादा कमी अिसमें हो सकती है और वह करनी चाहिये, जिससे हमारा अॅडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम होगा। आज आप पुलिस पर सव्वातीन करोड रुपयोंसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। यह बहुत काफी है। अिसमें कमी होनी चाहिये।

आपको जमीनदार और जागीरदार तबके की हिफाजत तो नहीं करनी है। अवाम की भलाअी के जो काम हैं अुसमें ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये। अगर हम पिपुल्स मिलिशिया (People's militia) करें तो हमारा डिफेन्स का खर्चा कम हो सकता है।

हुकूमते बर्तानिया हिंदुस्तान पर जब राज करती थी तब अुनको ज्यादा खर्च करने की क्यों जरूरत पडती थी और हमको खर्च क्यों कम करना चाहिये अिसकी तरफ मैं हाअुस की तवज्जह दिलाअुंगा ताकि जो चीज मैं हाअुस के सामने रखना चाह रहा हूं वह साफ हो जाय। बर्तानिया का राज अेक आक्यूपेशन (Occupation) के तौर पर था अिसलिये अुनको मिलीटरी और पुलिस की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आज के हालात में जब कि हम जमहूरी हुकूमत करने का और अव्वाम के मसायल सहल करने का दावा कर के हुकूमत में या अिस असेंब्ली में आये हैं तो

हमको अिन्ट्रास्पेक्टिव्ह (Introspective) हो कर देखना पडेगा। जब यहां बेरूनी हुकूमत काम करती थी तो अुसका जितना खर्च था अुतना ही आज भी हमको सिक्यूरिटी सर्व्हिसेस पर करना पड रहा है, अिसलिये यह सोंचना जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारी हुकूमत करने के तरीके में कुछ न कुछ नुक्स जरूर है, और अव्वाम के मसायल हल करने के अप्रोच में (Approach) कुछ खामियां हैं, हमारे पास पैसा कम है लेकिन फिर भी सिक्यूरिटी सर्व्हिसेस पर ज्यादा खर्च करना पड रहा है। जिस मुल्क में सिक्यूरिटी सर्व्हिसेस पर कम खर्च किया जाता है अुसी के बारे में कहा जाता है कि वह मुल्क अव्वाम की भलाअी और बहबूदी करने की तरफ बढ रहा है, अिसलिये हमको सिक्यूरिटी सर्व्हिसेस का खर्च कम करना चाहिये और आयंदा दो साल में नेशन बिल्डिंग के कामों पर जो ४० परसेंट खर्च किया जा रहा है अुसको बढाकर ६० फीसद करना चाहिये और सिक्यूरिटी सर्व्हिसेस का खर्च २० परसेंट से कम करना चाहिये, अुसी वक्त हमारे सामने जो बजट के खसारे का सवाल दूर हो सकता है।

दूसरी चीज पंच साला प्रोग्राम के बारे में मैं हाअुस के सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह से हिंदुस्तान में अेक पुनर्रचना करने का सवाल हमारे सामने आया है, अुसी तरह से हमारा बिरादर पडोसी देश चीन में भी यही सवाल है। जिस तरह से हम पंचसाला प्रोग्राम से हमारे राष्ट्र की पुनर्निर्मिती करना चाहते है अुसी तरह से चीन भी कोशिश कर रहा है। अुनकी जो तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है, अुसके मुकाबले में हमारी रफ्तार को देखें तो अेक बडी चीज जो नुमायां तौर पर हमारे सामने आती है, वह यह है कि वहां अव्वाम का कोआपरेशन हुकूमत को हासिल है बजट स्पीच में कहा गया कि जहां जहां अव्वाम का कोआपरेशन होगा वहां वहां तरक्की पैदा हो सकेगी। कम्युनिटी प्रोजेक्ट (Community Project) आफिसर्स और नॅशनल अेक्सटेन्शन सर्व्हिसेस (Natoinal extension services) के लोगों से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। अुन्होंने जो यहां का किस्सा सुनाया अुसको सुनने के बाद अगर चीफ मिनिस्टर साहब यह फरमायें कि अव्वाम की ताअिद हुकूमत को हासिल हो रही है तो मै अुस पर भरोसा नहीं कर सकता। अुन्होंने कहा कि अेक गांव में कलेक्टर साहब आकर सफाअी का काम शुरू कर दिये। गांव के चंद लोग बाजू में खडे होकर कहने लगे कि अितना बडा अफसर है लेकिन झाडू मारता है, अच्छा काम किया। फिर कहने लगे कि फलां जगह आपने अच्छी तरह से सफाअी नहीं की वहां अच्छी तरह कीजिये। यह किस्सा कहने में मुझे खुशी नहीं होती लेकिन अेक आब्जेक्टिव्ह (Objective) तरीके पर मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ देखने का लोगों का यह जो अेटीटयूड (Attitude) है वह क्यों है? अुन लोगों से पूछा गया कि आप अिस तरह बाजू खडे होकर सिर्फ बातें क्यों करते हैं, तो अुन्होंने कहा कि यह सब दिखावे की चीजें हैं, क्लेक्टर साहेब आये, अुन्होंने झाडू लगाया, बाद में कुछ होने जानेवाला नहीं है, यह हम जानते हैं। कलेक्टर साहब यह जो काम कर रहे हैं वह अुनमें लोगों की खिदमत के जजबात हैं अिसलिये कर रहे हैं, अैसी बात नहीं है। यह आज लोगों की भावना है। अव्वाम में, जो अिस तरह का ख्याल है अुसको जब तक हम दुरूस्त नहीं करते तब तक यह कहना कि हम पंचसाला प्रोग्राम को पूरा करेंगे बिल्कुल गलत होगा। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि कैपिटलायजेशन आफ मॅन पावर (Capitalization of manpower) होना चाहिये। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की तरक्की अिसके बगैर नहीं होगी। मै नहीं मानता कि अमेरिका

से या किसी बाहरी मुल्क से अिमदाद आने मे हमारे यह सवाल हल होंगें। हिंदुस्तान के ३५ करोड लोगो की मेहनत करने की कूवत का अिस्तेमाल करके ही हम पचसाला प्रोग्राम पूरा कर सकते है, यह हमारा विश्वास है, लेकिन मैं हुकूमत से पूछुगा कि अव्वाम मे काम करने का अिन्सपिरेशन (Inspiration) यहां क्यों नही पाया जाता, जिसका आपने कभी अंदाजा किया है, और अिसके लिये आपने अब तक क्या कदम अुठाये है ? अेक ओव्हर सिअर से मिलने का मुझे मौका मिला। अुन्होने बताया कि अेक गांव में पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर या और कोओी मिनिस्टर साहब आनेवाले थे और अुनको यह बताना था कि वहा पर अेक रोड अव्वाम ने अपनी मेहनत मे बनाया। अेक दिन लोगों को बुलाया गया। लोग आये, कुछ काम किया और चले गये। फिर लोग नही आये। अफसरों ने कहा कि रोड तो पूरा होना चाहिये क्योंकि मिनिस्टर साहब को हमने बताया है कि लोग रोड बनानेवाले है, डेवलपमेंट प्लान्स (Development plans) के तहत अव्वाम का रास्त कोआपरेशन हमको मिल रहा है। लोग तो आने के लिये तैयार नही थे तब सवाल आया कि अब क्या करना चाहिये ? फिर अेक कांन्ट्रेक्टर को बुलाया गया और अुन्होंने अपना लेबर लाकर रास्ता पूरा कर दिया, लेकिन कान्ट्रेक्टर साहब को यह हिदायत दी गअी कि जिस दिन मिनिस्टर साहब आयेंगे अुस दिन आपको या आपके लोगों को यहां नहीं रहना चाहिये नही तो आप बता देंगे कि यह काम अव्वाम ने नही किया है बल्कि मैंने किया है। आखर मिनिस्टर साहब वहां गये, रोड देखा सब कुछ हुआ। अुनको बताया गया कि अव्वाम ने रोड बनाया है और अुन्होंने भी सोंचा होगा कि अव्वाम ने ही बनाया होगा। अगर आप चाहें तो यह रोड कौनसा है कहां का है, सारे तफसीलात मै दे सकता हूं। अफसोस के साथ मुझे यह सब कहना पड रहा है लेकिन मै अिसीलिये बता रहा हूं कि हुकूमत अिससे कुछ सीखे, कि आपके पंचसाला प्रोग्राम से लोगों में अिन्सपिरेशन पैदा नहीं हो रहा है। जब तक पुराने चौखटे को बदलने की आप कोशिश नहीं करते तब तक यही होनेवाला है। पुराने चौखटे में यह ताकत नही है कि वह मुल्क में मेन पावर (Manpower) कॅपिटलाअिज (Capitalise) करने का अिन्सपिरेशन (Inspiration) पैदा कर सके। अिस तरह के डेफिसिट बजट से और बिना अव्वाम के कोआपरेशन के हम अपना पंचसाला प्रोग्राम पूरा करना चाहें तो वह कभी पूरा नहीं हो सकता फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच के आखिर में कहा है कि जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बढता जायगा हमारी आमदनी बढती जायगी और आपको ग्लूमी पिक्चर(Gloomy picture)रखने की कोअी जरूरत नहीं है। पिछले साल बजट के वक्त अुस वक्त के फायनान्स मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा था, लेकिन तमाम ख्वाहिशात के बावजूद हम देख रहे है कि हमारा रेवीन्यू कम होते जा रहा है और डेफिसिट बढता जारहा है अेकानॉमिक स्लम्प(Economic slump) आ रहा है जिसके बारे में हम बहुत दिनों से सोंचते थे, पंचसाला प्रोग्राम के तहत हम जो अुम्मीद कर रहे थे कि अव्वाम की मेहनत को कॅपिटलाअिज कर के हम जिन सवालों को हल करेंगे, वह नहीं हो रहा है। यह क्यों नहीं हो रहा है अिसको तय करने के लिये कोअी अेक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने से यह सवाल हल होनेवाला नही है। यह सब अिसलिये नहीं हो रहा कि पुराने चौखटे को तबदिल किये बगैर ही हम अिन चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक चौखटा तबदिल नहीं होता तब तक लोगों में अिन्सपिरेशन पैदा नहीं होता और अिन्स्पिरेशन पैदा नहीं होता तो काम नहीं होता। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि यह जो रस्सी खेंच औट गोअिंग फोर्सेस (Outgoing forces) और अव्वाम की ग्रोअिंग फोर्सेस (Growing forces) में चल रही है अुसमें पुरानी चौखट टूट के ही रहेगी जिसके बारे में मुझे शक नहीं है।

लेकिन मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि मामूली तरीके से यह चौखट टूटनेवाली है या अिसके लये अव्वाम को अिन्कलाब का अेकदाम करना पडेगा यही सवाल हमारे सामने है। मैं और मेरी पार्टी चाहती है कि हुकूमत अिस पर संजीदगी से सोंचे और हमारे कौमी जिदोजहद के वक्त हमारा जो रवैया था अुसको अव्वाम के सामने रखकर अुसमें अिन्सपीरेशन पैदा करने के लिये कदम अुठाये। अैसा किया गया तो ही मामूली तरीके से हमारे सवाल हल होंगे। अैसा नहीं हुआ तो चौखट तो टूटेगी ही लेकिन अुसमें तकलिफ होगी, अिन्किलाब होगा, कअी लोगों को कुरबानियां करनी पडेगी। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की कार्रवाअी के खिलाफ जो आवाज अुठाअी तो लोगों में अेक तरह की अिन्सपिरेशन पैदा हुअी और सारा मुल्क अुनके पीछे आज खडा हुआ है। अुनकी होम पालिसी के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी या दीगर पार्टियों में डिफरन्स आफ अेपिनियन (Difference of opinion) जरूर है, लेकिन जब मुल्क की आजादी का सवाल हमारे सामने आ रहा है, मुल्क को धोखा पैदा होने के अिमकानात हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर पार्टियां अमेरिका की तरफ से जो सोशिजें हो रही हैं अुनका मकाबला करने के लिये पंडित नेहरू के कंधे से कंधा लगाकर लडने के लिये तैयार हो गअी हैं। यह क्यों हो रहा है ? लेकिन मुल्क के अंदर मामुली मेहनत के काम करने के लिये अव्वाम में यह अिन्सपिरेशन क्यों पैदा नहीं हो सकता ? कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हिंदी के बारे में हम सब अेक जगह आ सकते है तो दूसरे सवालों के बारे में क्यों नहीं आ सकते ? मैं भी यही सवाल करूंगा कि दूसरे सवालों के बारे में हम क्यों नही अेक जगह आ सकते ? पंडित नेहरू की आटोबायग्राफी देखिये, फैजपूर और कराची कांग्रेस के रेजोल्यूशन्स देखिये, और निजामाबाद कांग्रेस के रेजोल्यूशन्स को देखिये। अुस वक्त क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, अिसका अिम्तियाज किजीये अुनमें किये गये वायदों को लेकर आप चलेंगे तो सारी पार्टियों की अिमदाद आप हासिल कर सकते है किसानों को रिलीफ (Relief) देने का सवाल आता है तो पब्लिक का कोआपरेशन हासिल हो सकता है ; लेकिन कौमी सवालों को बालायेताक रखते हुअे कुछ व्हेस्टेड अिंटरेस्ट (Vested interest) को कायम रखने के लिहाज से आगे बढते है तो अिसा से भी अिमदाद हासिल नहीं हो सकती। आप वायदा करते हैं कि अव्वाम से अिमदाद हासिल हो रही है, पांचसाला प्रोग्राम पूरा करेंगे, अव्वाम की परचेजिंग पावर (Purchasing power)बढेगी, रोजगारी बढेगी और मुल्क की तरक्की होगी लेकिन पिछले दो साल के अनुभव के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि अैसा नहीं हो रहा है। आपकी अुम्मीद पूरी नहीं हो रही है और जो पुराना ढांचा बरकरार रखा गया है अुसका बोझ दिन ब दिन अव्वाम पर बढता चला जा रहा है। यह जो बोझ बढता जा रहा है अुसी की वजह से कहीं न कहीं यह पुराना चौखूट, टूट जायगा। त्रावनकोर-कोचीन में हम यही चीज देख रहें हैं। वहां हम कामयाब हुअे हैं या नहीं यह सवाल अलग है, लेकिन पुराना चौखुटा वहां टूट रहा है यह साफ बात है। आज वहा टूटा, कल हैदराबाद में टूटेगा या आंध्र में टूट जाय लेकिन पुराना चौखटा अब रहनेवाला नहीं है। अिसलिये दूरंदेशी और अक्लमंदी की बात होगी कि आज जो पार्टी बरसरे अेक्तदार है वह अपना रूख वक्त पर ही तबदील करे मै जानता हूं कि मेरी अपील अैसे कानों पर पडे जो अिस तरह की बातें सुनने की आदी हो गअी है और अपने रवैये को तबदील न करना चाहे, लेकिन मुझे मालूम है कि चंद अैसे भी कान हैं जो मेरी अपील को सुने सकते हैं और अुन्हीं से मेरी यह अपील है और वे ही अिस चौखटे को तबदील कर सकते हैं। मैं कोअी नअी चीज सामने नहीं रख रहा हूं। हमारी

पुरानी मांगे आज भी मौजूद है। अुनको लेकर ही हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते है जमाने का जो तकाजा है अुसको सामने रखते हुअे हम आगे बढे तो हम आज की पॉलिसी मे तबदिली कर सकते है, डेफिसिट बजट की तरफ जो हमारे कदम जा रहे है, अुनको रोक कर सरप्लस बजट की तरफ हम जा सकते है।

पंच साला योजना को देखते हुअे हमको अिस बात का ख्याल करना पडेगा कि कही हम ओव्हर कैपिटलायजेशन तो नही कर रहे है ? हमारी चद स्कीमे अैसी है कि जिनसे रेवेन्यू बढाने की दृष्टी से फायदा हो सकता है लेकिन अुनकी तरफ ज्यादा तवज्जह नही दी जा रही है। अेक अेक्सपर्ट के तौर पर मैं अिनके बारे मे ज्यादा नही कह सकता लेकिन कुछ चीजो को देखकर अैसा मालूम होता है कि दिन ब दिन हमारा खर्च बढता जायगा, आमदनी के जराये कम होते जायेंगे और खर्च और आमदनी के बीच की जो गॅप (Gap) पूरी होनी चाहिये वह पूरी नही होगी। अिन प्रोजेक्टस के सिलसिले मे क्या हो रहा है, अिसके लिये जो अेस्टीमेटेड बजट (Estimated budget) था वह अेक या दो करोड मे बढाना पडा है। मसलन तुगभद्रा प्रोजेक्ट या किसी और के बारे में पिछले अेस्टिमेटेड बजट के अेक या दो करोड रुपये हमें ज्यादा देने पडे। अिसकी क्या वजह है ? क्या हुकूमत की तरफ से यह देखा जाता है कि वहां जितना माल चाहिये अुतना ही जा रहा है या अुससे ज्यादा जा रहा है, वहां जो माल पडा है वह सही तौर से अिस्तेमाल किया जा रहा है या नही ? यह मामूली चीजें है लेकिन हमारा करोडो रुपया कैपीटल की तरह अिनमें लगाया गया है अिसलिये अुनकी तरफ देखना भी जरूरी है।

आखिर में अेंटी करप्शन की तरफ मै हाअुस को तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अिसके लिय हुकूमत ने अेक लाख की गुजाअिश रखी है। मैने अिस चीज को आज तक कअी बार हाअुस के सामन रखा है, राजप्रमुख के अेड्रेस के वक्त भी मैंने अिसको रखा था लेकिन अुस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हाजिर नहीं थे। मैने कहा था कि 'सीजर्स वाअिफ शुड बी बियांड ससपिशन' (Caeser's wife should be beyond suspicion) अगर करप्शन दूर करना है तो हायेस्टक्वार्टर्स से अिसके बारे में आज ही से शुरू होना जरूरी है। हुकूमतकी जो स्ट्रेटेजिक मशीनरी (Strategic machinery) है वह बियांड डाअुट (Beyond doubt) होनी चाहिये। अूपर से यह चीज शुरू होती है तो करप्शन हम दूर कर सकते है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो लोग चायना जाकर आये है कम्युनिष्ट ही जाकर आये है अैसी बात नही नानकम्युनिस्ट और कॅांग्रेस लोग भी जाकर आये हैं अुन्होनें बताया है कि वहां करप्शन को दूर करने के लिये नेशनल मूव्हमेंटस (National movements)की तरह वहां दो मूव्हमेंटस चलाअी जा रही है। लोगों में जो करप्शन और ब्लॅक मार्केटिंग होता है अुसको और गव्हर्नमेंट मशीनरी में चलनेवाले करप्शन को दूर करने के लिये और गव्हर्नमेंट के टॅक्सेस टालने की जो कोशिश की जाती है अुसके लिये अेक अिस तरह दो मूव्हमेंटस वहां चलाअी गअीं और नतीजतन छः महीने के अदर देखा गया कि अेक जमाने से जो अेक बहुत बडा करप्शन वहां था वह दूर हो सका है। वहां से आये हुअे लोग बताते है कि हॉटेल के किसी वेटर (Waiter) को आप टिप देंगे तो कहता है कि यह गुनाह है, मै अिसको नही लूगा। हिंदुस्तान में आज हमारे आमदनी के जराये बहुत महदूद हैं और मुल्क की तरक्की करने के कअी सवाल हमारे सामने है। अैसी हालत में हमको भी अेक नेशनल मूव्हमेंट अुसी तरह से चलानी पडेगी जिस तरह से आज चायना में चलायी जा रही है। चायना में

जो अेंटी करप्शन मूव्हमेंट चलाअी जा रही हैं अुसमें पब्लिक का करप्शन दूर करनेवाली मूव्हमेंट को मैनफैन कहा जाता है और गव्हनमेंट के टॅक्सेस को टालना ब्लॅकमार्केट करना, गव्हर्नमेंट के कारखानों में कम पैदावार करने की कोशिश करना अिनको दूर करने के लिये जो मूव्हमेंट चलाअी जा रही है अुनको अुफैन कहा जाता है। चायना में ये जो अेंटी करप्शन और अेंटी टॅक्स अिव्हेजन मूव्हमेंटम (Anti-tax evasion movements) चालू की गअी हैं वहीं हमारे यहां भी चालू करना जरूरी है। क्योंकि जो पुराना चौखटा अंग्रेजों ने और यहां के निजाम ने हमको दिया है अुसकी खामियां हमको दूर हों। यह जो अेक पुरानी रस्टेड मशीनरी (Rusted machinery) है अुसको अच्छा बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिये। अेंटी करप्शन कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने आअी है। मै यह नहीं समझ सकता कि हुकूमत अव्वाम को कान्फिडन्स में लेने के लिये अिस रिपोर्ट को सामने क्यों नही लाती ताकि अव्वाम यह सोंचे कि अुसमें क्या मवाद है और किस तरह से अुसको करप्शन दूर करने के लिये हुकूमत की मदद करनी चाहिये। कोअी भी गव्हनमेंट अव्वाम के राम्त ताव्वून के बगैर, अुसकी अेक अेखलाखी ताकत अपने पीछे खडी किये बगैर कामयाब नहीं हो सकती। करप्शन की जो मशीनरी आज मुल्क में काम कर रही है अुसको तोडना है तो अव्वाम की ताकत हमको हासिल करनी होगी। अव्वाम की ख्वाहिश है कि करप्शन को दूर किया जाय। हाल ही में अुमरगा में कम्युनिस्ट पार्टी के अेक श्री. श्रीनिवासराव अहंकारी नामी कार्यकर्ता ने वहां के लोहारी के अेक सब-अिन्स्पेक्टर के जुल्म और करप्शन के खिलाफ कदम अुठाया और अुसकी कार्रवाअियां पब्लिक की जानकारी के लिये अेक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। जिस दुकान पर वह बोर्ड लगाया जाता था अुस दूकान के मालिक को डी. अेस. पी. की तरफ से धमकाया गया कि अगर फिर से बोर्ड लगाया जायगा तो तुम्हें गिरफ्तार किया जायगा, जेल में डाला जायगा, और मुकदमा चलाया जायगा। श्री अहंकारी को भी धमकाया गया। डी. अेस. पी. ने वह बोर्ड भी जब्त कर लिया है और कहते है कि हम श्री अहंकारी पर मुकदमा चलायेंगे। मैंने अिस सवाल को अिसलिये हाअुस के सामने रखा है कि मैं जानना चाहता हूं कि आया हुकूमत अुस सब-अिन्स्पेक्टर के खिलाफ और वहां के डी. अेस. पी. के खिलाफ क्या कदम अुठाना चाहती है? मैं यह जानना चाहता हूं कि अिस तरह से अव्वाम करप्शन को दूर करने के लिये जो कोशिश कर रही है अुसकी हुकूमत ताअीद करती है या अुस सब-अिन्स्पेक्टर या डी. अेस. पी. की ताअीद करती है? अगर हुकूमत अव्वाम की ताअीद करेगी तो सारा करप्शन बगैर कोअी अेंटी करप्शन कमेटी कायम किये और अितना खर्च किये रोका जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब और दीगर मिनिस्टर साहब जो यहां बैठे हुअे हैं वे अेक जमाने के वकला हैं। अव्वाम की तहरीकों में काम करनेवाले हैं। देहातों के होनेपर भी शहरों में रहनेवाले हैं और करप्शन कौन और किस तरह से करता है अिसकी सारी जानकारी है। निजाम के जमाने में जब यही लोग कहा करते थे कि फलां डिपार्टमेंट में करप्शन है। वह कैसे होता है वह अुन्हें मालूम नहीं अैसी बात नहीं है। अिसके लिये अेंटी करप्शन कमेटी मुकर करके तय करने की जरूरत नहीं है। दो सवाल हमारे सामने हैं। अेक यह कि करप्शन सचमुच दूर करना है या नहीं और दूसरा यह कि अुसके लिये अव्वाम का ताव्वून हमें हासिल करना है या नहीं। चायना में जो मुमकिन हो सका वह हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अुसके लिये पब्लिक को कान्फिडन्स में लेने की जरूरत है। अिसलिये में हुकूमत से अर्ज करूंगा कि वह अेंटी करप्शन कमेटी की रीपोर्ट शाया करें और अव्वाम का ताव्वून हासिल करने की कोशिश करें, और जहां जहां अव्वाम की तरफ से करप्शन को दूर करने की कोशिश की जाती है वहां वहां अुसको अव्वाम की ताअीद करनी चाहिये। आखिर में जैसा मैंने

कहा कि 'सीजर्स वाअिफ शुड बी बियांड समपिशन' अुस लिहाज से हुकूमत को सोंचना चाहिये। मुझे अुम्मीद है कि हुकूमत अिन चीजों की तरफ तवज्जह देगी।

अेक और चीज हाअुस के सामने रखकर मैं अपनी तकरीर खतम करूंगा। राजप्रमुख के अेड्रेस के वक्त मैंने और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों ने अिस चीज को हाअुस के सामने रखा था कि दो साल होने के बावजूद सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया गया है, शायद आप अुनको सियासी कैदी नहीं समझते, लेकिन अेक नजरिये के तहत जद्दोजहद जारी था। अपनी जान हथेली पर रखकर अुन्होंने कुर्बानियां की हैं। मुमकिन है अुनके नजरिये को आप न मानें। मतभेद हो सकता हैं, लेकिन जिन्होंने अेक सियासी नजरिये के लिये कुर्बानियां कीं और अुन तमाम जदोजहद के बाद आज जो अेक अिलेक्टेड मशीनरी यहां कायम हुअी है तो हुकमत के लिये जरूरी है कि तमाम सियासी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा आजादी अिस डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करने का मौका दे और अिसलिये अुन तमाम सियासी कैदियों को छोडना जरूरी हो जाता है। मैंने खुद और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब से कअी मर्तबा अिनके लिये नुमाअिंदगी की गअी ह, हुकूमत ने वादा भी किया था कि अिस सिलसिले में वह सोंचेंगी लेकिन अिसके बारे में जिस तरह से अमली जामा पहनाया जाना चाहिये अुस तरह से पहनाया नहीं जा रहा है। मैं कहूंगा कि हुकूमत अब अिसके बारे में जल्द से जल्द सोंचे और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें। अुनके खिलाफ जो केसेस चलाअी जा रही हैं अुनको विद्ड्रा (Withdraw) कर लें और अेक अैसा अेटमोस्फिअर (Atmosphere) पैदा करें कि जहां जो जुल्म और सितम हो रहे हैं वे सब खतम हो जायें। कअी शिकायतें अिसके बारे मे अब तक हाअुस के सामने आअी हैं मैं अुनकी तफसील में जाकर अुनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कॉंग्रेस को छोडकर बाकी सब सियासी पार्टियों में यह अेक आम ख्याल पैदा हो गया है कि हुकूमत की तरफ से तमाम पार्टीयों के काम में रूकावट पैदा करने की पुलिस के जरिये से कोशिश की जाती है अुनके कार्यकर्ताओं पर फॉल्स केसेस (False cases) चलाअी जाती हैं, झूटे मुकदमात में अुनको फंसाने की कोशिश की जाती है, और अैसे कअी केसेस हुकूमत के सामने लाये गये हैं और आयंदा भी लायें जायेंगे। हम अपनी सर्व्हिसेस के लिये यह मोटो (Motto) रखना चाहते हैं कि हम अव्वाम के खिदमतगार हैं मोटो अेट युवर सर्व्हिस (Motto at your service) अगर अुसको सचमुच अमल में लाना है तो करप्शन को और रिप्रेशन (Repression) को दूर करना पडेगा और मुल्क के अंदर अैसे हालात पैदा करने पडेंगे जिससे हम तमाम लोग तमाम पार्टियां मुल्क की बहबूदी के लिये आगे कदम अुठा सकें। मैं अुम्मीद करता हूं के मैंने जो चीजें हाअुस के सामने रखी हैं अुनके अूपर हुकूमत संजीदगी से सोंचेगी और जो टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन सक्यूरिटी सर्व्हिसेस पर हो रहा है अुसको दुरूस्त करेगी, नेशन बिल्डिंग के लिये जो अब ४० फीसद रखा गया है अुसमें अिजाफा करके अुसको ६० फीसद करेगी। हुकूमत की टॅक्सेशन पालिसी अैसी हो कि जिससे अुसका अिन्सीडन्स सरमायेदार तबके पर ज्यादा पडे चूंकि वे अुसको बर्दाश्त कर सकते हैं और आम लोगों को टॅक्सेशन से रिलीफ मिले और अिसके साथ साथ फ्यूडल सेटअप म भी तबदीली करने की तरफ कोशिश की जायेगी।

شری جی - راجہ رام (آرمور) مسٹر اسپیکر سر - پچھلے دو سال کے بجٹس کو اور اب اس تیسرے سال کے بجٹ کو دیکھنے کے بعد عام لوگوں کے دلوں میں نہیں تو کم ازکم میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کانگریس پارٹی کی گورنمنٹ جو اس وقت

اقتدار میں ہے اسکے سامنے کوئی واضح نقشہ آئندہ سماج کو بنانے کے سلسلہ میں قوم اور ملک کو ترقی کے راستہ پر لیجانے کے لئے نہیں ہے ۔ کوئی واضح پلان ہے ایسا ہم نے محسوس نہیں کیا ہے بلکہ ایک بھٹکے ہوئے راھی کی طرح اندھیرے میں ادھر کچھ راہ ملی ، پھسلا پھر اودھر ٹکرا کر واپس آیا ایسا ھی آج کی حکومت کا حال ہے ۔ بالکل اندھیرے میں ایک بھٹکے ہوئے راھی کی طرح ہماری آج کی حکومت چل رھی ہے ۔ کانگریس نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو نقشہ عوام کے سامنے رکھا اور ۶۰ سال کی آزادی کی لڑائی کے دوران میں آئندہ بننے والے ہندوستانی سماج کا جو خاکہ پیش کیا تھا اسکو اس بجٹ کے مختلف پہلووں کو سامنے رکھکر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرونگا کہ وہ اوس راستہ پر نہیں جارھی ہے جو کہ اوسکی منزل ہے ۔ وہ ترقی کی منزل کی طرف گامزن نہیں ہے ۔

چنانچہ سب سے پہلے میں یہ کہونگا کہ ہمارا اورگورنمنٹ کا یہ آدیش تھا کہ ملک میں ایک ایسی سماج کی رچنا کی جائے جہاں اکسپلائٹیشن (Exploitation) نہو ۔ جہاں طبقات نہوں ۔ کلاس لس سوسائٹی (Classless society) ہو ۔ وہ تفرق ختم کردیا جائے جو برسہا برس سے پچھڑے ہوئے طبقات پر برتا جاتا یا کسی نہ کسی وجہ سے اقتدار میں آکر پچھلی گورنمنٹ نے روا رکھا تھا اور ان بست طبقات کو غلامانہ حیثیت دی تھی ۔ انکی انتی کرکے ہم فرق مٹانا چاہتے تھے اور کرنا یہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آدمی نیچ ہے اور وہ آدمی اونچ ہے اگرچیکہ معیشت کے اعتبار سے سوسائٹی میں کچھ فرق ہوسکتا ہے ۔ انکے رہنے سہنے اور کھانے پینے میں کچھ فرق ضرور ہوسکتا ہے مگر دوسرے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرکے بلند طبقات جو شوشن کرتے ہیں اسکو ختم کردیا جائے اور جو طبقہ غلامانہ حالت میں ہے اسکی انتی (उन्नति) کی جائے۔چنانچہ آزادی حاصل ہونے کے بعد الکشنس سے پہلے کانگریس نے نظام آباد کے ادھیویشن (अधिवेशन) میں اور پھر اپنے مینیفسٹو (Manifesto) میں کھلم کھلا یہ کہا تھا کہ اگر کانگریس پارٹی اقتدار میں آجائے تو اسکے یہ ٹارگٹس (Targets) ہونگے ۔

اب اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد اور پچھلے دو سال کے بجٹس کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اسطرف قدم نہیں بڑھا رہے ہیں ۔ کیا ہم اسطرف قدم بڑھا رہے ہیں اور کیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف معاشی پستی کو دور کرینگے بلکہ ڈی سنٹرلائزیشن آف اڈمنسٹریشن (Decentralisation of administration) کی طرف قوم کو لیجائینگے یہ بتلانے کی کوشش کرینگے کہ صحیح طور پر جنتا (जनता) کو یہ محسوس ہو کہ جنتا اپنے آپ پر راج کررھی ہے ۔ آج تیسرا سال گزر رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ڈی سنٹرلائزیشن تو کجا کم سے کم جو پولیٹیکل اتھاریٹی (Political authority) ہے اس میں کہاں کہاں ڈی سنٹرلائزیشن کی طرف لے جارہے ہیں یا بالکل ویسا ھی جیسا کہ فارنرس (Foreigners) انگریز جیسی حکومت کرتے تھے ؟ ویسی ھی حکومت آج کر رہے ہیں وہ اپنے اقتدار

اور اپنی شان و شوکت کو قائم رکھنے جن جن ایجنسیوں کو جیسے شطرنج پر مہروں کو بٹھاتے ہیں ، بٹھائے تھے ویسے ہی بٹھانا چاہتے ہیں ۔ انکو وہاں سے ہٹانے کا ارادہ آج اس تیسرے سال کے بجٹ میں بھی نہیں ہے ۔ چنانچہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو سیاسی طاقت ہے وہ دلی میں اور حیدرآباد میں سمٹ کر رہ جائیگی ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ کنفشنس (Confessions) کرنا کہ عوام کی مدد نہیں ملتی ۔ فائیو ایر پلان میں بھی یہ کہا گیا کہ راستہ میں پارٹیاں ایسی حائل ہیں کہ کوآپریشن نہیں ملتا تو ہم کیا کریں ۔ تو میں یہ کہونگا کہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا کچھ سیاسی پارٹیوں کے یہ کہنے سے کہ حکومت کا ساتھ نہ دو عوام ساتھ دینے سے باز نہیں رہتے ۔ میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں ۔ بلکہ اگر یہی حالت رہے تو سیول ڈس اوبیڈینس (Civil disobedience) کی طرح پھر ایک مہم کی جائیگی ۔ جو سپنے آپ نے انکو دکھائے تھے اور جو پروگرام انکے سامنے رکھا تھا اگر وہ پورا نہ کریں تو یہ ہوگا ۔ جب تک ایسا نہ ہو کہ ہمارے دیش کی جو سیاسی شکتی ہے اسکو چار کھمبوں پر جسکو کہ میں فور پلر اسٹیٹ (Four Pillar State) کہتا ہوں اس نقطہ نظر سے ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ ہندوستان میں قائم کرنے کے لئے نہ بڑھیگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکا یہ دعوی کہ وہ کلاس لس سوسائیٹی (Classless society) یا کاسٹ لس سوسائیٹی (Casteless Society) یا طاقت کی مساویانہ تقسیم کا دعوی صحیح نہیں ہوسکتا ۔

چار کھمبوں والے راج کی طرف میں کہونگا کہ وہ ڈس ہارٹڈلی آر ہاف ہارٹڈلی (Disheartedly or Halfheartedly) قدم اٹھایا گیا اور پنچائت کے سلسلہ میں اسٹیٹ میں کام شروع ہوا ۔ لوگوں نے دلچسپی لی اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیہاتوں میں جہاں جہاں بھی کمیٹیاں قائم ہوئیں وہ آگے بڑھیں ۔ لیکن ایک سال گزرنے پر حکومت نے سوچا کہ اگر انکو سیاسی طاقت استعمال کرنے کا موقع دینگے تو انکا اندھیرے میں رکھکر حکومت کرنے کا جو خیال ہے وہ پورا نہوگا ۔ یہ سمجھکر حکومت نے مالی امداد کو گھٹانا شروع کردیا اور مالی امداد پندرہ فیصد سے ساڑھے سات فیصد کردیگئی ۔ ورنہ اس بجٹ میں نئے پنچائت کمیٹیاں بنانے اور جو کچھ بھی کمیٹیاں ہیں انکو زیادہ مالی امداد دینے کے لئے گنجائش ہوتی لیکن گورنمنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے تاکہ سیاسی ستہ (सत्ता) عوام کے ہاتھوں میں منتقل نہ ہو جائے ۔ چنانچہ انکا یہ دانستہ پلان ہے ۔ انہوں نے سوچ سمجھکر یہ کیا ہے کہ کمیٹیوں کو ناکام بنائیں تاکہ یہ طاقت حیدرآباد کی حکومت اور حیدرآباد کے اڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے ۔

اسکے علاوہ ڈی سنٹرلائزیشن کے سلسلہ میں حکومت نے ان کمیٹیوں کو الکٹیڈ (Elected) بنانے کے لئے کونسا قدم اٹھایا میری یہ ہر بات گورنمنٹ پر ایک چارج ہے کہ جو گورنمنٹ حیدرآباد میں ہے اسنے شوشن کرنے والے غیر ذمہ دار سیٹھ ساھوکار لوگوں کو نامینیٹ (Nominate) کیا ہے اور ساتھ ہی

جو بھی دھرا راج چلا ہے اسکی آڑ لیکر شکار کھیلنے کی کوشش کی ہے ۔ یہ کہا جاتا ہے
کہ پولیس ایکشن سے پہلے یہ تھا اور وہ تھا ۔ اسکے بعد ڈویل اڈمنسٹریشن
(Dual Administration) تھا تو وہ بھی اب ختم ہوگیا ۔ لیکن آج ڈسٹرکٹ
بورڈ پر واقعی طور پر کن لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے ۔ پہلے جو لوگ
تھے اون ہی کو موقع دیا جا رہا ہے ۔ اب اگر پروگریسیو لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں
تو انہیں کلکٹر جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اسکے پاس جانا پڑتا ہے ۔ اگر
کلکٹر کی رائے کے خلاف کوئی مسئلہ ہوتو انکو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر ۔ اب ہم ۵ ۔ ۳۰ تک اڈجرن ہوتے ہیں ۔

The House then adjourned for recess till Half Past Five of the Clock.

The House reassembled after recess at Half Past Five of the Clock.

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

Business-of the House

مسٹر ڈپٹی اسپیکر ۔ قبل اس کے کہ ہم ڈسکشن شروع کریں میں یہ اناونس
(Announce) کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کے ڈیمانڈس
(۱۱ و ۱۲) مارچ سنہ ۱۹۵۴ع کو لئے جائینگے ۔ اون پر موشنس فار رڈکشن کل یعنی
۹ ۔ مارچ کو پانچ بجے تک دیدئے جائیں ۔

Budget–General Discussion

شری جی ۔ راجہ رام ۔ مسٹر اسپیکرسر ۔ میں یہ عرض کررہا تھا کہ آج کی
حکومت جس کے ذمہ بجٹ پیش کرنے کا کام ہے وہ کوئی صحیح راستہ پر نہیں جا رہی
ہے ۔ چنانچہ گورنمنٹ نے ویلیج پنچایتس اور ڈسٹرکٹ لوکل بورڈس کو ڈیموکرٹائز
(Democratise) کرنے کے سلسلہ میں بجٹ میں کوئی پراویژن نہیں
رکھا ہے ۔ بلکہ ان کو ناکام بنانے کے لئے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ (Deliberate attempt)
حکومت نے کیا ہے ۔ کیونکہ اوس نے پنچایت کمیٹیوں کو اپنا کام کرنے کے لئے کوئی
سرمایہ یا فیناس پرووائڈ (Provide) نہیں کیا ۔ ہمارے پاس ۲۲ ہزار
دیہات ہیں ۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہر اوس دیہات میں جسکی آبادی ہزار پندرہ سو ہو
پنچایت کمیٹی قائم کی جائیگی اور اون کے لئے پندرہ پرسنٹ ریوینیو انیشیل اسٹیجس
(Initial stages) پر پرووائڈ کریگی لیکن دو سال گزرگئے اب تک
اون مواضعات میں پنچایت کمیٹیوں کا اعلان نہیں ہوا ۔ یہی نہیں بلکہ جن مواضعات
کو شمار کرلیا گیا تھا اون کو بھی مالی نقطہ نظر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے
دوسری چیز یہ کہ نامزدگیوں کا طریقہ رکھکر سارے پٹیل پٹواریوں کو جو برسہا برس

سے گاؤں کی تباهی کے ذمه دار هیں چور دروازے سے گھسایا - اور اسطرح اون کمیٹیوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی - هماری بیورو کریٹک مشنری (Bureaucratic machinery) کو جو ورثه میں چلی آرهی هے هر موقع پر ان کمیٹیوں میں مداخلت کرنے کا اختیار دیا گیا - میں نے پہلے کہا تھا که کس طرح ڈپٹی کلکٹرس اور تحصیلدار پنچایت کمیٹیوں کے فرائض کی انجام دهی میں حائل هو رهے هیں - وہ لوگ هر مرتبه ان کمیٹیوں کے ممبروں سے بے عزتی کا سلوک کرتے هیں - جب اون کے هاتھ میں کمیٹیاں رهینگی تو صحیح طریقه پر پرجا تنتر راج کیسے قائم هوسکتا هے - اون کو مالی نقطه نظر سے کمزور کرکے اور کئی مشکلات پیدا کرکے اون کمیٹیوں کو ناکام بنایا جارها هے - ڈسٹرکٹ لوکل بورڈس میں بھی نامینیشن هوتا هے اور کلکٹر کو اس میں دخل دینے کے اختیارات هیں - فنڈ بھی کمزور هے اور جو فرائض متعین کئے گئے هیں وہ بھی اتنے محدود هیں که اون کا رهنا نه رهنا برابر هے - کلکٹر دو تین مہینوں میں ایک مرتبه یا اون کا من خوش رها مہینه میں ایک مرتبه ممبروں کو اپنے گھر پر بلالیتے هیں اور چائے وغیرہ پلا کر اون کو واپس کردیتے هیں - کیا یہی طریقه ڈیمو کریسی اور ڈی سنٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاورس کی طرف ایک قدم هے - حکومت ایک بھٹکے هوئے راهی کی طرح جا رهی هے - کوئی نقشه گورنمنٹ کے سامنے نہیں هے - حکومت نے یه دیکھنے کی کوشش نہیں کی عوام کی کیا ضروریات هیں اون کو کسطرح پورا کیا جاسکتا هے - اون کو تکمیل کرنے کے لئے فنڈس اور فینانس کسطرح جمع کئے جاسکتے هیں - برسوں سے وهی مدات هماری آمدنی کے هیں - کبھی کبھی ایک آدھ ٹیکس کا اضافه کرکے آمدنی بڑھا لی جاتی هے اور اوس کا بٹوارہ اور خرچه وهی پرانے ڈھنگ سے کیا جاتا هے - آج کی حکومت عوام کے احساسات اور اونکی ضروریات کا اندازہ نہیں لگا سکتی - هم یه کیسے اندازہ کریں که آخر حکومت کس سمت جا رهی هے - موجودہ زمانے کا نقشه سامنے رکھکر عوام کی ضروریات کو اسس (Assess) کرنے اور اون کو انالائز (Analyse) کرنے اور کن ضروریات کو پرائرٹی (Priority) دیجانی چاهئے اور اون ضروریات کے لئے فنڈ کہاں سے حاصل کرنے چاهئیں ان تمام امور پر غور کرنا ایک سویلائزڈ (Civilised) گورنمنٹ کا فرض هوتا هے جو ایک ویل فیر اسٹیٹ (Welfare state) قائم کرنا چاهتی هے - لیکن اوس کی بجائے بنئے کی طرح سے جو پیسه چند مدات کے تحت برسوں سے چلا آرها هے اوسکو پچھلے طریقوں پر هی خرچ کیا جارها هے - کیا آج اس طرح کے بجٹس بنا کر هماری حکومت ویل فیر اسٹیٹ بنانے کے راستے پر جاسکتی هے - میں اس سلسله میں هماری آمدنی کے تھوڑے بہت جو ذرائع هیں اون کا ذکر کرونگا که کسطرح وہ ساکت هیں - هماری حکومت کے موازنه میں لینڈ ریوینیو کا درجه دوسرے نمبر پر آتا هے - سب سے پہلے تو آبکاری کی آمدنی هے - اوس کے بعد لینڈ ریوینیو - لینڈ ریوینیو کے اسٹیٹسٹکس (Statistics) کو هم دیکھیں تو معلوم هوگا که وہ کبھی پانچ ساڑھے پانچ کروڑ سے آگے نہیں بڑھی - اس کی کیا وجه هے - کیا هم [illegible]

کو اسی طرح ساکت رکھنا چاہتے ہیں ۔ ہم سوسائیٹی میں جو مساوات قائم کرناچاہتے ہیں سوسائیٹی سے طبقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا اس کے لئے لینڈ ریوینیو کے یہ اسٹیٹسٹکس کافی ہوسکتے ہیں ؟ لینڈ ریوینیو کے طریقے میں بنیادی تبدیلی کرنا چاہئے۔ ورنہ یہ آمدنی ایسی ہی ساکت رہیگی اور غریبوں پر اس کا بار پڑتا رہیگا ۔ بچھلی گورنمنٹ نے پہلے کے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اوس کو قائم کیا تھا کہ کسطرح عہدہ داروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ ڈسکریشن (Discretion) استعمال کرنے دیا جائے ۔ اور کسطرح اون کو اپنے لئے زیادہ سے زیادہ رشوت اور ناجائز آمدنی پیدا کرنے کے مواقع دئے جائیں ۔ کیا اوس زمانے کا مطمع نظر اس گورنمنٹ کا بھی ہے ۔ اس لحاظ سے اس زمانے کی جو لینڈ ریوینیو کے وصول کرنے کا اسٹرکچر (Structure) ہے اسکی ڈوری ڈھیلی چھوڑی گئی ہے ۔ لیکن آج کی گورنمنٹ جو ڈیمو کریسی کی بنیادوں پر قائم ہوئی ہے اور جو یہ دعوی کرتی ہے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لئے کام کرتی ہے وہی سسٹم برقرار نہیں رکھ سکتی تلنگانے کی کاشت کا طریقہ ایک پیچیدہ طریقہ ہے ۔ پٹیل پٹواریوں کو اسکا موقع دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانہ کا خیال رکھے بغیر صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کا خیال کریں اور اسکے مواقع انکو فراہم کئے جاتے ہیں ۔ جیسا کہ چند معزز ارکان نے اس طرف ہاؤز کی توجہ مبذول کی تھی کہ تلف مال کی رپورٹیں کرکے گورنمنٹ کا لاکھوں روپیہ کا نقصان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ اگر تلف مال کی رپورٹیں نہ ہوں جو جھوٹ موٹ لکھی جاتی ہیں تو لاکھوں روپیہ گورنمنٹ کی ٹریژری میں جمع ہوسکتا ہے۔ لیکن جو ڈھانچہ بن گیا ہے اوسکی وجہ سے گورنمنٹ کے عہدہ‌دار اپنے جیب بھرنے کی کوششیں کرتے ہیں ۔ تلف مال کا جو طریقہ ہے اسکو تبدیل کرنا ضروری ہے ۔ تاکہ پٹیل پٹواریوں اور گورنمنٹ کے عہدہ‌داروں کو اپنی جیب بھرنے کا موقع نہ رہے ۔ نظام‌آباد اور دوسرے اضلاع میں لاکھوں روپیہ تلف مال کے سلسلہ میں لکھا جاتا ہے۔ تلف مال کے جھوٹے تختہ جات بنائے جاتے ہیں ۔ وہ سارا روپیہ انکی جیبوں میں جاتا ہے۔ جو دھارے قائم کئے گئے ہیں وہ ڈرائی لینڈ کا لحاظ رکھتے ہوئے قائم کئے گئے ہیں ۔ عہدہ‌داروں کے ڈسکریشن پر تلف مال کے عملیات ہوتے ہیں ۔ جب تک اس طریقے کو تبدیل نہیں کیا جائیگا یہ بدنظمی باقی رہیگی ۔ تہبندی میں پٹیل پٹواری سازش کرکے پانی سپلائی کرتے ہیں ۔ تہبندی کے کاغذات میں اسکا اندراج نہیں ہوتا ۔ ہرگاؤں میں جہاں تہبندی ہوتی ہے یہ عمل ہوتا ہے ۔ جب تک ہم ان امور کی جانب توجہ نہیں کرینگے کوئی علاج نہیں ہوسکتا ۔ گرداور اور پٹیل و پٹواری ان تینوں میں سازش ہوتی ہے اور غلط تختہ جات داخل کرتے ہیں ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو مزید پیسہ وصول ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے ۔ اس سازش کو ختم کرنا چاہئے ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک واٹر ریٹ سسٹم (Water rate system) نافذ نہ کیا جائے یہ خرابیاں باقی رہینگی ۔ اگر واٹر ریٹ سسٹم جاری کیا جائے تو ہمارے اسٹیٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا ۔ تہبندی کا اختیار ولیج پنچایت بنا کر اسکے

تفویض کرنا چاھئے - ان کو اختیار دینا چاھئے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں - ایسا انتظام کیا جائے تو لاکھوں روپیہ کا جو نقصان ھورھا ھے وہ بند ھوسکتا ھے - گورنمنٹ کے اکسچکر (Ex-chequer) میں آمدنی آئیگی - لینڈ ریوینیو کا یہ فرسودہ نظام عوام کو اکسپلائیٹ (Exploit) کرنے کیلئے نافذ کیا گیا تھا تاکہ اوس سے جو آمدنی ھو اپنے عیش و آرام پر صرف کی جاسکے - ھمارے ھاں لینڈ ریوینیو کا سسٹم ایسا ھے کہ دس ایکڑ زمین رکھنے والے سے بھی اوسی ریٹ سے لیا جاتا ھے اور سو ایکڑ رکھنے والے سے بھی اوسی ریٹ سے لیا جاتا ھے اور ایک ھزار ایکڑ والے سے بھی وھی ریٹ لیا جاتا ھے .. نتیجہ یہ ھوتا ھے کہ جس کی زمین زیادہ ھے وہ تو آسانی سے ریوینیو داخل کرسکتا ھے اوس پر کوئی بار نہیں ھوتا - وہ زمین کو افتادہ بھی چھوڑ دیتا ھے کیونکہ تین چار سو روپیہ جو قلیل مالگزاری ھوتی ھے وہ برداشت کرسکتا ھے - لیکن اس کو گریڈیڈ سسٹم (Graded system) پر قائم کیا جائے تو اچھا ھوگا - ھمارے لینڈ ریفارمس کا حال یہ ھے کہ جس نوعیت کے وہ ھونے چاھئیں تھے نہیں ھوئے - اگر گورنمنٹ گریڈیڈ سسٹم اختیار کرے تو میں سمجھتا ھوں کہ ھماری اس وقت جو پانچ کروڑ کی آمدنی ھے اس میں اور اضافہ ھوسکتا ھے - میرا خیال ھیکہ اس میں کم از کم دوگنا اضافہ ھوسکتا ھے - آج اگر ھم مینیمم مارجن (Minimum margin) رکھکر پچاس ایکڑ والوں کے لئے جو ریٹ ھے اس کو سائینٹیفک (Scientific) بنیادوں پر ۵۰ فیصد اضافہ کے لحاظ سے تعین کریں اور سو ایکڑ والوں کے لئے اوس سے دوگنا ھو اور ایک ھزار اور دو ھزار والوں کے لئے ۱۰ اور ۱۵ گنا ھو تو ایسی صورت میں وہ مجبور ھو جائینگے کہ یا تو وہ اپنی زمینات کی سائیزس (Sizes) کو گھٹائیں یا اوس زمین پر محنت کر کے اوس زمین پر جو مالگزاری عائد ھو رھی ھے اوس کو ادا کریں - ان دونوں طریقوں سے وہ زمین کی طرف مائل ھونے پر مجبور ھونگے .. ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی آمدنی میں بھی اضافہ ھوگا - لیکن افسوس کہ ھم نے ایسے طریقے اختیار نہیں کئے بلکہ ایک ایکڑ والے اور ایک ھزار ایکڑ والے دونوں کو ایک ھی لکڑی سے ھانک رھے ھیں - اگر یہ طریقہ کار درست نہیں ھے تو پھر ایک طریقہ جو اختیا کیا جاسکتا ھے وہ اگریکلچرل انکم ٹکس کا طریقہ ھے اوس سے زیادہ میں اس کو پریفر (Prefer) کرونگا - اس میں شک نہیں اگریکلچرل انکم ٹکس سے بچنے کے لئے ھر شخص کوشش کریگا کہ جھوٹا ریکارڈ فراھم کرے تاکہ وہ آپ کے ضابطہ کے اندر نہ آسکے - اور اگر ریوینیو گریڈڈ سسٹم پر رکھا جائے تو وہ دینے پر مجبور ھوگا - بجائے کوئی مناسب طریقے کو اختیار کرنے کے ھم دیکھتے ھیں کہ وھی فیوڈل سسٹم (Feudal system) کو مینٹین (Maintain) کرنے کی کوشش کی جاتی ھے - میں ایسے ھی اشارے ھمارے بجٹ میں پاتا ھوں - ھمارے لینڈ ریوینیو کی کلکٹنگ ایجنسیز (Collecting agencies) پر کتنا صرفہ ھورھا ھے - دوسرے ممالک کے بجٹ کو ھم دیکھیں تو معلوم ھوگا کہ دس فیصدی کلکٹنگ ایجنسی پر خرچ کیا جاتا ھے

چھ روپیہ ٹکس وصول کرنے کیلئے اگر ہم چار روپیہ خرچ کردیں تو یہ کوئی صحیح طریقہ کار نہ ہوگا ۔ یہ بہت بیکار سی بات ہے ۔ اتنا ٹاپ ہیوی اڈمنسٹریشن (Top-heavy administration) مناسب نہیں ہے۔پانچ کروڑکی آمدنی وصول کرنے کے لئے اگرہم ریوینیوکلکٹنگ ایجنسی (Revenue Collecting Agency) پرتین کروڑ روپیہ خرچ کردیں تو کیا یہ مناسب بات ہوگی ۔ ہمیں غور کرنا چاہئے کہ کیا یہ ضروری ہے ۔ آخر اس ہیوی اکسپنڈیچر (Heavy expenditure) کی کیا وجہ ہے ۔ وجہ ایک ہی ہے کہ یہی سسٹم پہلے سے چلا آرہا ہے ۔ پہلے جس طرح عہدوں پر اعلی خاندان کے لوگوں کو لیا جاتا تھا اور وہ ملک کے مفادکا خیال رکھے بغیر صرف اپنے فائدےکا خیال رکھا کرتے تھے ۔ وہی طریقہ اب بھی چلا آرہا ہے لیکن اس کو عوام اب ہرگز برداشت نہیں کرسکتے ۔ عوام کا یہ خیال تھا کہ جب عوامی راج شروع ہوگا توزیادہ سےزیادہ کوالیفیکیشنس (Qualifications) رکھنے والے اور زیادہ قابل لوگوں کو ملک کی خدمت کےمواقع ملیں گے لیکن آج بھی وہی رنگ ڈھنگ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا کافی روپیہ خرچ ہورہا ہے۔ اس کے باوجود جو فائدہ حاصل ہونا چاہئے تھا نہیں ہو رہا ہے ۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرونگا کہ آبکاری جو ہماری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ کانگریس راج کے آتے ہی ملک سے ساری برائیاں دور ہو جائینگی لوگ سمجھ رہے تھے کہ عوامی گورنمنٹ ان برائیوں کو دور کرنے کے لئے پہلا قدم اٹھائےگی اور وہ اپنی آمدنی کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کو گرائیجوول (Gradual) طور پر دور کریگی ۔ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو دس روپیہ تنخواہ دیں اور اوس سے آٹھ روپیہ کسی نہ کسی طرح پھر حاصل کرلئے جائیں ۔ اس طرح سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ۔ حیدر آباد کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ایک ڈھانچے سے دوسرے ڈھانچے میں ڈھالنےکی کوشش کرنی چاہئے ۔ اگر یہاں کے حالات کو یکلخت ٹھیک نہیں کرسکتے تو آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے ٹھیک کرنا چاہئے ۔ مدراس اور سی ۔ پی کی گورنمنٹ اس کو ختم کرنےکی کوشش کر رہی ہے ۔ اگر ہم آٹھ منسٹرس اور آٹھ ڈپٹی منسٹرس رکھکر اپنے اخراجات کو بڑھاتے رہیں تو آمدنی کے مختلف ذرائع اسی طرح تلاش کرنے پڑینگے اگر ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ تو کیا ایک منسٹر کی تنخواہ نکلنا بھی مشکل ہو جائیگا ۔ اس آمدنی پر زیادہ آدھار کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے ۔ بلکہ ہمیں دوسرے ذرائع تلاش کرنے چاہئیں ۔ ہم جاھلوں کی جیب سے کچھ لیکر فخر محسوس کررہے ہیں ۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا جب کبھی ہم ٹکس لگاتے ہیں یا کوئی آمدنی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں تو اوس کو کلکٹ (Collect) کرنے کے لئے اتنے لوگوں کو لگاتے ہیں اور اس میں اتنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سےکافی روپیہ اس کے وصول میں خرچ ہو جاتا ہے۔ آبکاری کی آمدنی کا پہلے تو گورنمنٹ کے کارندے نقصان کررہے ہیں ۔ رشوت خواری کے وجہ سے جو آمدنی اسکی ہونی چاہئے نہیں ہو رہی ہے ۔

یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جھاڑوں کی کمی کی وجہ سے یا تراشنے والوں کی وجہ سے آمدنی میں کمی واقع ہوتی ہے بلکہ گورنمنٹ کی عدم توجہ اور عہدہداروں کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہورہا ہے - جھاڑ تو زیادہ تراشے جارہے ہیں لیکن اس کا فائدہ گورنمنٹ کو نہیں ہورہا ہے - گورنمنٹ ان لوگوں پر تکیہ کئے بیٹھی ہے جن پر اسٹیٹ اور مرکز کی طرف سے نگرانی کا دعوی کیا جاتا ہے - منسٹر صاحب ایک رات کے لئے دورے پر جاتے ہیں اور دوسرے دن ان کا واپس آنا ضروری ہوتا ہے - وہ دعوی کرتے ہیں کہ میں نگرانی کرتا ہوں - اگر آج ہمارے ڈسٹرکٹ بورڈس (District Boards) کا کنٹرول ہو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات بڑی حد تک دور ہوسکتی ہے لیکن افسوس کہ یہاں یہ سسٹم بھی نہیں ہے -

ٹیکسس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے - میں پوچھتا ہوں ٹیکسس کن سے لینا چاہیئے یہ درست ہے کہ گورنمنٹ ٹیکسس کے بغیر اپنے لائحہ عمل کو عمل میں نہیں لاسکتی - ٹیکس ضروری ہیں - لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکسس کن سے لئے جائیں - ایک معمولی اکنامکس (Economics) کے پرنسپلس (Principles) پڑھے ہوئے آدمی سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہیگا کہ ٹیکسس ان لوگوں پر عائد کئے جائیں جو اس کی ادائی کی سکت رکھتے ہیں - لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیکسس ان لوگوں پر عائد کئے جاتے ہیں جو غریب ہیں جن کا خود اپنا جینا مشکل ہے ان سے ٹیکسس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے - آپ مکسڈ اکا نمی (Mixed economy) کا دعوی ایک طرف کرتے ہیں دوسری طرف پرائیویٹ انٹرپرائیز (Private enterprise) اور گور نمنٹ سیکٹر (Government sector) کے درمیان بیالنسڈ اکا نمی (Balanced economy) کا دعوی آج کے ہمارے حالات کے لحاظ سے بیروزگاری کو دور کرنے کے لئے کاٹیج انڈسٹریز (Cottage industries) کو فروغ دینا ضروری ہے - لیکن دیکھیے کہ عمل کیا ہورہا ہے - ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ولیج انڈسٹریز (Village industries) یکے بعد دیگرے ختم ہوتی چلی جارہی ہیں - اس کی وجہ محض یہی نہیں ہے کہ انہیں بڑے بڑے انڈسٹریز یا مشینوں کے بنے ہوئے آرٹیکلس (Articles) سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے - یہی ایک وجہ نہیں ہے - اگر یہی ایک وجہ ہوتی تو یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز مشینوں کے نکلتے ہی ختم ہو چکی ہوتیں - لیکن وہ آج مررہی ہیں - اس کی وجہ کا مپٹیشن وتھ دی مشین پراڈکٹس (Competition with the machine products) ہی نہیں ہے - بلکہ ان صنعتوں کے ختم ہونے کی اصل وجہ گورنمنٹ کا وہ رجحان ہے جو ان کے فروغ کی جانب نہیں - آج ہمارے دیہاتوں میں ویورس ہیں - تیلی کے گھانے ہیں - ان میں جو ڈپریشن (Depression) آئے تو اس موقع پر لاکھوں لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے - اس کی بجائے ان کے پراڈکٹس پر سیلس ٹیکس لگایا جاتا

ہے - آج ہمارے ہر دیہات میں کئی تیل کے گھانے ہیں - میں پوچھتا ہوں ان پر سیلس ٹیکس کا سسٹم کیوں ہے - کیا وہ کاٹیج انڈسٹری نہیں ہے - کیا بمبئی اور مدارس میں ایسی چیزوں پر سیلس ٹیکس ہے ؟ نہیں ہے - اس بارے میں گورنمنٹ کی کوئی نیتی (नीति) ہی نہیں ہے - وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کو کس طرح بچایا جائے - کہاں ڈسکریمینیٹ (Discriminate) کیا جائے - جیسے ہی سیلس ٹیکس کا قانون بنا ہر دس ہزار سے زیادہ کا بیوپار کرنے والے پر سیلس ٹیکس عائد کردیا گیا - یہ ایک ہی لکڑی آنریبل فینانس منسٹر کے ہاتھ میں ہے جس سے وہ سب کو ہانکنا چاہتے ہیں - اور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کن کو فروغ دینا ہے کن کو بچانا ہے - ہم نے بنایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے تیل کے گھانے بھی اپنا بزنس (Business) کرتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں - لیکن اب انپر ایک ایک ہزار دو دو ہزار سیلس ٹیکس عائد کیا جارہا ہے - یہی ہے آپ کی بیالنسڈ اکانمی آج ہمارے پاس ایسی کئی صنعتیں ہیں جنہیں کی انڈسٹریز ، (Key industries) بنانا ہے - اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنے دیش میں صرف کاٹیج انڈسٹریز ہی کو رکھکر بیکورڈ (Backward) بنایا جائے - لیکن کاٹیج انڈسٹریز کے فروغ اور اس کے تحفظ کا سوال آج بہت اہم ہے - مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے سیلس کے لئے کوئی سیلس امپوریم (Sales emporium) نہ بناسکی - اس کے لئے آج سیلس آرگنائیزیشن (Sales organisation) کی سخت ضرورت ہے - ان کا ڈیمانڈ کافی ہے - لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اس کے لئے کوئی پراویژن نہیں ہے - ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی صنعتوں کو بچانے کی خاطر انہیں سیلس ٹیکس سے اکزمپشن (Exemption) ملنا ضروری ہے - ساتھ ہی ساتھ کاٹیج انڈسٹریز کے لئے حکومت کو کچھ ریشنالائیزیشن (Rationalisation) کرنا پڑیگا - آج جب اس کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے کہ چیپ پاور (Cheap power) اور ہائیڈرو الکٹرک پاور (Hydro-electric power) ضروری ہیں تو بجٹ میں ان کے لئے گنجائش رکھکر انہیں فروغ دینا چاہیئے اور ہائیڈروالکٹرک پاور اور چیپ پاور اسکیم تیزی کے ساتھ عمل میں لائی جانی چاہیئے اور اس کی سپلائی کا انتظام کیا جانا چاہیئے - گورنمنٹ مکسڈ اکانمی (Mixed economy) پرائیویٹ انٹرپرائیز (Private entrprise) گورنمنٹ انٹرپرائیز (Government enterprise) کہتی ہے - یہ کہتی ہے کہ مکسڈ اکانمی ہماری پالسی ہے - میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے - دو چار دیوالیے کے یا نقصان سے چلنے والی انڈسٹریز کو اپنے ہاتھوں میں لیکر اگر مکسڈ اکانمی کہا جائے تو یہ درست نہیں ہوسکتا - جو منافعہ سے چلنے والے ہیں وہ تو پرائیویٹ ہاتھوں میں دیدیئے جاتے ہیں - کیا مکسڈ اکانمی کی یہی پالسی ہے - جو کارخانے ملک کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے انکی پیداوار تو چند لوگوں کی حد تک محدود ہے - انہیں پرائیویٹ ہاتھوں میں فروخت کردیا جاتا ہے - ایسی صنعتوں

کو جن کے پیداوار کی سارے جنتا کو ضرورت ہے اور جس پر گورنمنٹ کا کنٹرول ضروری ہے گورنمنٹ ان صنعتوں کو تو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتی حالانکہ ایسے کارخانے منافعہ میں چل رہے ہیں۔ میں پچھلے تین سال سے برابر اس کی مانگ کرتا چلا آیا ہوں کہ شوگر فیاکٹری کیوں نیشنلائیز (Nationalise) نہیں کی جاتی ہے۔ آج مکسڈ اکانمی میں چلنے کا دعوی تو ہے لیکن ہماری گورنمنٹ میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کو چلا ئیں۔ اس لئے پرائیویٹ ہاتھوں میں دیا جارہا ہے۔ ان کے مینجنگ ایجنٹس ایسے اسپیشلسٹس (Specialists) ہیں کہ اس کارخانے کو چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سالانہ ۸ - ۱۰ لاکھ روپیئے کماتے ہیں - اس میں وہ ۱۰-۱۵ ہزار روپیئے لگاکر اتنا منافعہ پاتے ہیں - آخر اس کا کیا مطلب ہے - ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس سے گورنمنٹ کا منشا کچھ اور ہے - یعنی یہ کہ وہ بھی اس طرح لوٹ کھسوٹ میں برابر کے حصہ دار ہیں - اور اسی وجہ سے دانستہ یا نادانستہ طور پرانجان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو صرف ۱۵-۲۰ ہزار روپئے لگاتا ہے کروڑوں روپئے کماتا ہے جس کی نہ تو ٹیکنیکل صلاحیت ہے اور نہ وہ کوالیفائیڈ (Qualified) ہے - کس طرح انہیں یہ منافع ملتا ہے - پریمیر کارپوریشن (Premier Corporation) کو اس طرح اجازت دیجاتی ہے - شوگر فیکٹری میں آج اتنا عملہ ہے کیا گورنمنٹ اس کو اپنے ہاتھ میں لیکر اپنے طور پر نہیں چلا سکتی - اس میں ٹکنیکل ہینڈس ہیں مینیجرس ہیں۔ اس کو چلانے والے ہیں مزدور ہیں - جس طرح اڈمنسٹریشن میں آئی - اے - یس - اور یچ - اے - یس ہیں اسی طرح آپ ٹیکنیکل کیڈر - کمرشیل کیڈر بناسکتے ہیں اور ان کے ذریعہ چلاسکتے ہیں۔ لیکن نہیں چلاتے - اور ان لوگوں کو دانستہ طورپر فائدہ اٹھانے اور لوٹنے کا موقع دیتے ہیں - کیونکہ اس لوٹ میں آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ آپ کی انڈسٹریز کا یہ حال ہے۔ وہی نظام شاہی یا لائق علی کی پالیسی کہ بس پیسہ لگا دئے اور خانگی لوگوں کے ہاتھ میں دیدئے - یہ مکسڈ اکانمی بیا لنسڈ اکانمی کا کوئی اصول نہیں۔ اس میں کوئی پلان نہیں۔ اس میں عوام کی ضروریات پیش نظر نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کی جاتی - وہی بالکل پرانی شان چلی آرہی ہے -

آر-ٹی-ڈی-کے بارے میں ہمارے فینانس منسٹر نے کہا کہ آر-ٹی-ڈی-کی آمدنی کم ہونے کی وجہ اسٹرائک ہے۔ غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ اس طرح کہکر آنریبل فینانس منسٹر نے دانستہ طور پر حقیقت کو چھپایا ہے۔ آر-ٹی-ڈی-کی آمدنی میں کمی کی وجہ صرف اسٹرائک نہیں۔ اور نہ وہاں کے مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ نقصان کی وجہ ہے - بلکہ میں کہونگا کہ نقصان کی اصل وجہ وہاں کے اڈمنسٹریشن کی خرابی ہے - اورساتھ ہی ساتھ ہمارے عوام کا ہمارے سماج کا آج کا ڈپریشن (Depression) ہے - عوام کی صلاحیتیں پر چیزنگ پاور اور اسٹانڈرڈ آف لیونگ کم ہورہا ہے ان میں صرف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے - اس کا تو آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا - یہ کہتے ہیں کہ عوام کا

معیار زندگی گھٹ رہا ہے۔ عوام کی پستی کی وجہ سے ٹراولنگ(Travelling)
کم ہوا ہے۔ اور پھر جو کچھ بھی ٹراولنگ ہوا ہے اس کا بھی انتظام برابر نہ ہوسکا۔ اسٹیٹ
اکزیکٹیو اتھارٹی (State Executive authority) سول ایجنٹ آف اڈمنسٹریشن
(Sole agent of administration) بن کر کام نہیں کرسکتی
اس لئے ہمنے بار ہا کہا ہے کہ ڈی سنٹرالائیزیشن(Decentralisation)
کرنا پڑیگا۔ میں پوچھتا ہوں آر۔ ٹی۔ ڈی۔ بسس کا ایک ایک کنڈکٹر کتنی رشوت
لیتا ہے۔ کیا اس کو معلوم کرنے کی کوشش حکومت نے کبھی برقعہ اوڑھ کر بھیس بدل
کر کی ہے۔ آپ کسی ڈسٹرکٹ پر نائیٹ اوٹ (Night out) چلے جائیے
ٹراول (Travel) کرکے دیکھئیے آپ کو معلوم ہوگا کہ
آخر کس وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کو بھی درست کرنے کی ہمت نہیں کرتے
اس کو تو تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن کہا جاتا ہے کہ مزدوروں نے ۲۰ دن ہڑتال کی تھی
جس کی وجہ سے آمدنی میں گھاٹا آگیا۔ ایک طرف تو ریٹس (Rates) وہی ہیں
جو حیدرآباد میں ناکہ بندی کے زمانے میں قائم کئے گئے تھے جبکہ آئیل کی سپلائی
مشکل تھی۔ ایک گیا لن کے لئے ۵۔۶ روپئے صرف کرنا پڑاتاتھا یہ ان دنوں کے قائم
کئے ہوئے ریٹس ہیں۔ انہیں اب تک برقرار رکھکر عوام کو لوٹا جارہا ہے میں کہوں گا کہ
ریٹس کو روائز (Revise) کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا کہ
اگر اڈمنسٹریشن اچھا ہو جائے تو ریٹس کم کرنے کے باوجود بھی آپ کو بہت زیادہ
آمدنی ہوگی۔ آپ اس پر تو غور نہیں کرتے۔

[SHRI B. D. DESHMUKH (CHAIRMAN) IN THE CHAIR]

یہ آمدنی کے چند مدات تھے جن کے بارے میں میں نے توجہ دلائی۔ اب میں خرچ
کے مدات کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ پلانس ہیں۔ نیشن بلڈنگ
(Nation-building) کے لئے انہیں تیزی سے فروغ دینے کی ضرورت
ہے۔ یہاں پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے لئے پیسہ ہونا چاہئیے۔ مجھے کبھی
کبھی افسوس ہوتا ہے جب ہماری گورنمنٹ فارن کیپیٹل (Foreign capital)
کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی اسٹرنگس (Strings)
نہیں ہیں۔ اس لئے اس کے فلو(Flow) ہونے کی اجازت دیجاتی ہے ۔اور یہ
کنسیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا جو منافعہ ہوگا وہ لیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ
یہ کوشش نہیں کرتی کہ جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور جنہیں اسٹیٹ بجٹ میں سے آج
بھی کروڑوں روپیہ دیا جارہا ہے ان سے اپیل کی جائے کہ دیش کو اس وقت پیسہ کی
ضرورت ہے دیش کی ترقی کے لئے پیسہ کی ضرورت ہے بیروزگاری دور کرنے کے لئے
ضرورت ہے ہوگا یہ کہ اس ملک میں وہ پیسہ رہیگا۔ یہیں کے لوگوں کا ہوگا۔ سود کی شکل
میں ہو یا منافع کی شکل میں ہم انہی کو دینگے۔ اس سے لوگوں کی خریدنے کی صلاحیت
بڑھیگی۔ لیکن یہ نہیں کرینگے بلکہ فارن کیپیٹل (Foreign Capital)
کی طرف بھاگینگے۔ یہاں تو فارن کیپیٹل کی ضرورت ہے۔ آئیے دیش خالی پڑا ہوا ہے۔

یہ کہینگے کہ جتنا پیسہ آپ لاسکتے ھیں لائیے اس کو انوسٹ(Invest)
کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو رکھئیے جو ان کے اپنے ھیں - اور پھر سود اور منافع کا
پیسہ آپ ھی لے لیجئیے - اس کے لئے کیا ھم پر کوئی اسٹرانگ پریشر
(Strong pressure) ھے - کوئی دباؤ ھے ؟

ھمارے پاس جو جاگیردارخاندان ھیں ان سے ربط رکھنے والے کہتے ھیں کہ جاگیرداروں
کے پاس کوئی دو-دو کروڑ روپیہ کے زیورات کی شکل میں ھے - آپ کہتے ھیں کہ ان کے
کھانے کے لئے ھی نہیں ھے اس لئے ھم معاوضہ دیتے ھیں نظام صاحب ھیں کیوں نہیں ان کو
مجبور کیا جاتا ؟ اگر ھمیں فائیو ایر پلان پورا کرنا ھے تو کیا ان سے یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ جو منافع ھم باھر کے ممالک کو دے رھے ھیں وہ ان ھی کو دینگے - یہ کیوں
نہیں کیا جاتا - اگر ھمیں ھمارا فائیو ایر پلان کمپلیٹ (Complete) کرنا ھے
تو یہاں کے پبلک کوآپریشن (Public Co-operation) جسمانی شکل
میں ھی نہیں بلکہ جو سیونگس کی شکل میں سرمایہ بند پڑا ھوا ھے اس کو ڈھونڈھ کر نکالنا
پڑیگا - اس وقت اور صرف اسی وقت ھمارا فائیو ایر پلان کا ٹارگٹ پورا ھوگا - صرف یہ
کہنے سے کہ دیڑھ دولاکھ ایکر زمین زیر کاشت لائی جائیگی اور کارخانے کھولے
جائینگے کام نہیں ھوسکتا - نئی نئی انڈسٹریز کھولنا تو کجا جو کارخانے تھے وہ آج بند
ھو رھے ھیں - گورنمنٹ آف انڈیا سے لڑکر جیسا کہ دوسرے گرانٹ کررھے ھیں
نئے انڈسٹریز قائم کرنیکی صلاحیت نہیں ھے - اگر گورنمنٹ آف انڈیا سے دو ایک
انڈسٹریز قائم کی جائیں تو ھم بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے جیسا کہ فینانشیل سبونشن
(Financial subvention) کے مسئلہ میں ھم نے آپ کا ساتھ دیا تھا - چنانچہ
ریلوے سنٹرل گورنمنٹ کے تحت جاتے وقت ٦ - ٧ کروڑ کا سرمایہ تھا - اس وقت ھمارے پاس
کے کچھ لائینس ڈالنے کے لئے سروے کیا گیا تھا لیکن انٹگریشن (Integration)
ھوکر ٥ سال ھوگئے اور اب تک ایک بھی لائن ڈالنے کی کوشش گورنمنٹ آف انڈیا کی
طرف سے نہیں کی گئی تو اس خاموشی کے کیا معنی ھیں - کیا ھمیں اپنی آمدنی بڑھانا نہیں
ھے - کیا یہاں کے لوگوں کو روزگاری پروائیڈ (Provide) کرنا
نہیں ھے - کیا ھمارے پاس جو ڈولپمنٹ پلانسس (Development plans)
ھیں ان کو پورا کرنے کا مقصد نہیں ھے - ھر بات کے لئے یہ ھمارے سامنے کہا جاتا ھے کہ
ھمارے پاس پیسہ نہیں ھے - پیسہ نہیں ھے - بس یہ ھی رٹ لگائی جاتی ھے - ھمارے پاس
پیسہ نہیں ھے - تو گورنمنٹ کی بد دیانتی ھے اور میں سمجھتا ھوں کہ آپ کو یہ نہیں کہنا
چاھئیے - جب بھی ولیج پنچایت کا مطالبہ کیا گیا تو یہ کہا جاتا ھے کہ لوگوں میں ابھی
صلاحیت نہیں ھے - ان کو اتنے زیادہ حقوق اور اختیار دینا بالکل بے معنی سی بات ھے
پھر ھم جب کہتے تھے کہ وہ لوگ نادانی اور جہالت سے آپ لوگوں کو ووٹ دئے
تھے - آپ کو یعنی کانگریس کو ووٹ دئے تھے تو اس وقت بھی یہی کہنا تھا کہ
ھمارے عوام انپڑھ ھیں جاھل ھیں اس وجہ سے آپ بیل اور ناگر رکھکر الکشن جیتتے
ھیں - آج واقعی جنتا کی یہ حالت ھے کہ وہ محض ایک عقیدہ ھونے کی وجہ سے " بیل "

کو ووٹ دئے ھیں اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ایک بار کوشش تو کیجئیے کہ بائی الکشن میں اس علامت کو نکالیں۔ اس سے آپ پر کیا اثر پڑنے والا ھے اور کیا فرق ھونے والا ھے وہ آپ کو معلوم ھو جائیگا۔ اس لئے اب یہ کہنا کہ کوآپریشن نہیں ملتا مناسب نہیں ھے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ھوسکتی ھیں۔ اگر ھمیں ملک کو ترقی دینا ھے تو ہمارے جو ڈولپمنٹ پلانس ھیں یا ترقی کی اسکیمیں ھیں ان پر زیادہ توجہ دیناضروری ھے۔

آخر میں میں صرف ایک بات اور کہنا چاھتا ھوں اور اسے دیکھکر مجھے بڑا تعجب ھوا۔ آج تقریباً ۳۰-۳۵ فیصد پست طبقات ھیں جنکو ھم ھریجن یا کسی اور نام سے پکارتے ھیں۔ انکی بھلائی۔ سماجی اور معاشی بھلائی کے لئے صرف ۲۰ لاکھ روپیے رکھے گئے ھیں۔ یہ ۴۰-۵۰ لاکھ لوگوں کے لئے رکھے گئے ھیں تو میں سمجھتا ھوںکہ اس سے ہماری نیتی (नीति) پوری نہیں ھوتی۔ ھم سماج سے نیچ۔ اچھوت اور ان ٹیچ ایبلٹی (Untouchability) کو دور کرنا چاھتے ھیں۔ انکو بہتر پوزیشن دینا چاھتے ھیں تو اس مد میں ھمیں اور کچھ اضافہ کرنا پڑیگا۔ اسطرف ھمیں تیزی سے قدم اٹھانے کی ضرورت ھے اسلئے میں سمجھتا ھوںکہ یہ رقم ناکافی ھے اور اس میں اضافہ ضروری ھے۔

اسکے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنا ھے کہ جو دو ڈپارٹمنٹس قوم کے معمار سمجھے جاتے ھیں۔ سنٹر میں بھی اور یہاں بھی۔ وہ تعلیمات اور قوم کی صحت برقرار رکھنے والا مڈیکل ڈپارٹمنٹ ھے۔ لیکن پچھلے سالوں میں اور آج بھی ان میں کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں پاتا ھم نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ حیدرآباد میں کمپلسری ایجوکیشن ھو۔ یہ دعوی کیا گیا تھا کہ تین چار سال میں ھم اسکو نافذ کرینگے لیکن ریورٹ میں یہ کہا گیا ھے کہ ڈیڑھ دو سال میں ۲۰ کمپلسری ایجوکیشن سنٹرس قائم کرسکے ھیں۔ اگر یہی رفتار ھو تو میں کہتا ھوں کہ اسکو نافذ کرکے سارے لوگوں کو لٹریٹ (Literate) بنانے کے لئے کتنے سال درکار ھونگے اور کتنی صدیاں گزرینگی ھم اندازہ نہیں کرسکتے۔

مڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سلسلہ میں پچھلے سالوں کا تجربہ ھونے کے باوجود بھی ہمارے حیدرآباد میں کچھ ایسی حالت ھے کہ جنکی بناء پر کئی ایک امراض پھوٹ پڑتے ھیں۔ ہماری ریاست کے لوگوں کو اس سے بچانا ضروری ھے تو امراض کا حملہ ھونے کے بعد انکو بچانے کی کوشش کریں اور یہ بتلانے کی کوشش کی جائے کہ ھم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اتنا پیسہ صرف کیا تو میں سمجھتا ھوںکہ یہ ٹھیک بات نہ ھوگی۔ اس کےلئے تو ھمیں پہلے سے زیادہ سے زیادہ پریونٹیو میژرس (Preventive measures) لینا پڑیگا۔ اسکے علاوہ حیدرآباد میں انٹیریرس (Interiors) میں مہلک امراض کے دواخانے ایسی جگہ کھولے گئے ھیں جہاں نہ بس سرویس ھے اور نہ اچھے پکے روڈس ھیں۔ اسی طرح آیورویدک دوا خانے کھولنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں ھے تو یہ کام کسطرح چلسکتا ھے۔

آخر میں میں ایک اور چیز کی طرف حکومت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ۔ مجھے افسوس ہے کہ گورنمنٹ اور خاص کر چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ تصفیہ کرلیا تھا کہ پٹیل پٹواریوں کے سسٹم کو ختم کیا جائیگا ۔ انکی جگہ گروپنگ کی جائیگی اور اسٹیپنڈری پٹواریز (Stipendiary patwaries) رکھے جائینگے ۔ لیکن ایسا تیقن دلانے کے باوجود بھی آج کے بجٹ میں اس کے لئے کوئی پراویژن نہیں ہے ۔۔

میں ایک بار پھر گورنمنٹ سے یہ کہونگا کہ دھندلکے میں بھٹکے بھٹکے اپنے سامنے کوئی واضح پلان نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش اور قوم کی ترقی کے لئے کوئی صحیح راستہ نہیں ہوسکتا ۔۔ ہمیں سوچ سمجھکر اور ایک واضح پلان بنا کر ۔۔کیا ضروریات ہیں انکو اچھی طرح جاننے کے بعد انکو میٹ (Meet) کرنے کے لئے کیا ذرائع ہوسکتے ہیں ۔ موجودہ حالات میں ہماری آمدنی بڑھانے کے لئے اور خرچہ کم کرنے کے لئے کیا طریقے ہوسکتے ہیں ان پر غور کرنا چاہئے ۔ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر کافی دھیان دیگی ۔

شری کے ۔ وینکٹ رام راؤ ۔(چنا کونڈور) اسپیکر سر ۔ جو بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے وہ تیسرا بجٹ ہے ۔

مسٹر چیرمن ۔ وقت کا خیال رکھا جائے ۔۔۔

شری کے ۔ وینکٹ رام راؤ ۔ بجٹ کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے اور اسکا یہ تصور ہوتا ہے کہ بجٹ ایک پلان ہو منصوبہ ہو ۔ عوام اپنے جیب سے اپنی کمائی سے بچا کر زبردستی ہی سہی یا والنٹری طور پر جو پیسہ دیتے ہیں وہ ایک ٹرسٹ کے طور پر دیتے ہیں ۔ اب اس میں سے کسطرح اکسپنڈیچر ہو ۔ اسکو کسطرح خرچ کیا جائے ۔ آیا اسکو عوام کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ کیا جائے یا من مانے طور پر حکومت خرچ کرے ان تمام پرنسپلس (Principles) اور اصولوں کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے ۔ گو کہ بجٹ میں ہندسے رہتے ہیں لیکن ان ہندسوں کے پیچھے حکومت کی پالیسیز اور پلانس مضمر رہتے ہیں ۔ آئندہ کیا پلانس کرنے والے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے ۔۔ اس نقطہ نظر سے ہم اس بجٹ پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے ہمارے سامنے سنہ ۱۹۴۹ع سے لیکر آج تک کے بجٹس کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے ۔ جب سے یہ اسمبلی بنی ہے اس وقت سے لیکر آج تین سال تک ڈیفسٹ بجٹس (Deficit budgets) گھاٹے کے بجٹس ہمارے ہاتھ میں دئے جاتے ہیں ۔۔ پولیس ایکشن سے پہلے جو بجٹ ہوا کرتے تھے اس میں ریوینیو اکونٹ سے بچا کر کیونکہ ہمیشہ سرپلس بجٹ ہوا کرتے تھے اور وہ کیپیٹل اکسپنڈیچر کے لئے استعمال کیا کرتے تھے ۔ لیکن پولیس ایکشن کے بعد سے ایک پرمننٹ فیچر (Permanent feature) کے طور پر ڈیفیسٹ بجٹس ہمارے سامنے آرہے ہیں ۔ فینانس منسٹر صاحب نے جو

اپنی اسپیچ میں اسکا اقبال کیا ھے ۔ لیکن اب دیکھنا یہ ھے کہ اس سے کیا اثرات مترتب ھونے والے ھیں ۔ ایک مسئلہ یہ ھے کہ اس ڈیفیسٹ فینانسنگ کے بارے میں مختلف آرا ھیں ۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ھے کہ ڈیفیسٹ فینانسنگ ھوسکتی ھے کیونکہ آج کے حالات کا جو تقاضہ ھے اسکو پورا کیا جائے ۔ لیکن دوسرے لوگوں کا یہ خیال ھے کہ ھم خسارے کی پالیسی اڈاپٹ (Adopt) نہیں کرسکتے ۔ آج حیدرآباد ھی میں نہیں بلکہ ھندوستان بھر میں یہ رویہ ھے ۔ بہ استثنائے بمبئی جہاں چند لاکھ کا سرپلس بجٹ بنا ھے ۔ کہ بجٹ میں خسارہ ھے ۔ سنٹر میں تو ۲۰۰ کروڑ روپیہ کی کمی ھے ۔ معاشی زندگی میں افراط زر انفلیشن (Inflation) کے جو اثرات ھیں اسکی نسبت ریزرو بنک آف انڈیا کے جو اعداد ھمارے سامنے ھیں وہ یہ ھیں کہ ڈسمبر سنہ ۱۹۵۳ ع تک جو کرنسی نوٹس جاری کئے گئے اس میں ۳۸ کروڑ کا گھاٹا ھوا اور ۱۵ ۔ جنوری سنہ ۱۹۵۴ ع میں مزید ۳۸ کروڑ کا اضافہ کیا گیا ھے ۔

اس طریقہ سے اگر ھم افراط زر کا مطالعہ کریں تو معلوم ھوگا کہ ۱۸ ۔ ڈسمبر سنہ ۵۳ ع تک (۱۱۳۰،۲۱) روپیہ کے نوٹس کی شکل میں جاری کئے گئے ۔ اگر ۱۵ ۔ جنوری سنہ ۵۴ ع کے اعداد دیکھیں تو معلوم ھوگا کہ (۱۱۵۸،۴۴) کروڑ روپے کے نوٹس جاری کئے گئے ھیں ۔ فینانس منسٹر صاحب نے گو بجٹ اسپیچ میں فرمایا ھے کہ ھمارے فینانس ساؤنڈ (Sound) ھیں لیکن یہ محض ادھر اودھر کے الفاظ ھیں ۔ مسلمہ طور پر تو یہ محسوس کیا جارھا ھے کہ ھم افراط زر کے حالات سے دو چار ھیں ۔ ایسی صورت میں ھماری معاشی پالیسی کیا رھنی چاھیئے ۔ عموماً ماھرین معاشیات کی یہ رائے اور اصول رھا ھے کہ جہاں کہیں افراط زر کے حالات ھوں سرپلس بجٹ بنانا چاھیئے ڈیفیسٹ بجٹ نہیں بنا یا جاسکتا ۔ میں ادھر اودھر کا کوٹیشن دینے کی بجائے گوروالا کمیٹی کا انٹرا ڈکٹری چیپٹر (Introductory Chapter) فینانشیل سچویشن (Financial situation) کے سلسلہ میں ھے اسکو میں ایوان کے ملاحظہ میں لانا چاھتا ھوں ۔ اس سے واضح ھوگا کہ جہاں کہیں افراط زر کے حالات ھوتے ھیں سرپلس بجٹ بنانا چاھیئے ۔ لیکن یہاں تو گنگالٹی ھے سنہ ۵۲ ۔ ۵۳ ع کا بجٹ اکسیڈنٹلی (Accidentally) سرپلس بجٹ رھا ۔ اوس میں ریلوے کے کچھ ایک کروڑ روپیہ ھمارے اکاؤنٹ (Account) میں آگئے تھے ۔ اور اسی لئے وہ خسارہ کا بجٹ نہ بن سکا ۔ لیکن سنہ ۵۳ ۔ ۵۴ ع اور آئندہ بننے والے بجٹ کو دیکھیں تو معلوم ھوگا کہ اوس میں (۲،۴۷) کا گھاٹا ھورھا ھے ۔ آج ھندوستان کی ھر ریاست کا بجٹ گھاٹے کا بجٹ ھے ۔ اور خود سنٹر کا بجٹ گھاٹے کا ھے ۔ ان گھاٹے کے بجٹس کو کس طرح میٹ آوٹ (Meet out) کیا جائیگا ۔ گو حیدرآباد کی حکومت کے ھاتھ میں کچھ نہیں فقط ھاتھ کی لکیریں ھیں میں اس کے اعداد بھی بعد میں دونگا ۔ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس منٹ ھے وھاں سے نوٹ بنتے جاتے ھیں ۔ کب تک اس طرح کی منی منٹنگ (Money minting) جاری رھیگی ؟ یہ ایک صاف اصول ھے کہ اس طرح جب زیادہ روپیہ بازار میں آجاتا ھے

تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اشیاء کی قیمتیں بڑھجاتی ہیں تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی تھیوری اپلائی ہو جاتی ہے ۔ اس طرح

حکومت ڈیفیسٹ فینانشیل پالیسی (Deficit financial policy) اور انفلیشنری پالیسی (Inflationary policy) کواڈاپٹ کر کے عوام کی زندگی پر حملہ کر رہی ہے کیونکہ ڈیفیسٹ فینانشیل پالیسی کے برے اثرات ہونے والے ہیں ۔ میں یہ چیز بھی ایوان کے سامنے لاؤں گا کہ آئندہ کیا ڈیفیسٹ بجٹ بنانا ضروری ہے یا اس کو اس طرح اڈجسٹ (Adjust) کیا جاسکتا ہے کہ وہ سرپلس بجٹ بن سکے ۔ ہمارے جو سورسس آف انکم ہیں وہ ٹیپ کئے گئے ہیں یا نہیں ۔ ہماری آمدنی کے جو ذرائع ہیں کیا وہ برابر استفادہ میں آرہے ہیں یا نہیں ۔ ڈیفیسٹ فینانشیل پالیسی کے سلسلہ میں یہ ڈفنس (Defence) کیا جاتا ہے کہ ہم تو ڈولپمنٹ پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں ۔ اس وجہ سے ڈیفیسٹ بجٹ بنا نا ضروری ہے۔ یہ ایک بے اصولی چیز ہے۔ جہاں کہیں کیپٹل اکسپنڈ یچر پر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں ریوینیو سے بچا کر اس طرح کے پلان بنا نا چاہیئے۔ اس اصول کو ہماری حکومت نے ترک کیا ہے ۔ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ میں عرض کر چکا ہوں ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرنگا کہ ڈیفیسٹ فینانشیل پالیسی جہاں کہیں بھی اختیار کی جاتی ہے وہ عموماً جنگ کے حالات میں اڈاپٹ کی جاتی ہے ۔ لیکن یہاں ڈولپمنٹ کے نام اکسپنڈیچر (Expenditure) کئے ہیں ۔ چنانچہ میں اس کو ایوان کے سامنے لانا چاھتاھوں ۔ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا ہم آئندہ سال کے لئے (۲۹) کروڑ کا اسٹیمیٹ (Estimate) پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سے ۱۸ کروڑ سے زائد محض اڈمنسٹریشن پر خرچ ہورہا ہے ۔ میرے ہاتھ میں فینانس سکریٹری کا میمورنڈم ہے ۔ اس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ (۵۹) پرسنٹ اڈمنسٹریشن پر خرچ ہورہا ہے اور (۱۳) پرسنٹ نیشن بلڈنگ پرپزس کے لئے خرچ ہو رہے ہیں ۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت ضرور صرف کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔ میڈیکل اور ایجوکیشن پر صرف ہورہا ہے لیکن جو خرچ ہورہا ہے اس کو جائز طور پر ایک پلان کے تحت اچھی طریقہ سے خرچ کیا جارہا ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے ۔ اس سے بھی زیادہ خرچ کرنے کا امکان اور گنجایش ہے یا نہیں اس کا بھی سوال ہوسکتا ہے ۔ ہمارے نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ (Nation-building Department) کے جو اکسپنڈیچرس ہیں اس کو فی کس تقسیم کریں یعنی ایک کروڑ (۸٦) لاکھ کی آبادی پر ہم تقسیم کریں توفی کس دو روپیہ پڑتے ہیں ۔ اس میں پرائمری ایجوکیشن ۔ سکنڈری ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن بھی شامل ہے ۔ اسطرح میڈیکل اور پبلک ہیلتھ پر فی کس ایک روپیہ خرچ ہورہا ہے۔ کیا یہ کافی ہوسکتے ہیں۔ یہ تو بہت کم خرچ کئے جا رہے ہیں ۔ اگر ہر شخص پر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم جو کچھ خرچ کررہے ہیں وہ ہمارے لئے کوئی فخر کی بات نہیں ۔ اس کے لئے ہم اپنے مونچھوں پر تاؤ نہیں دے سکتے ۔

اسی طرح اگریکلچر اور اریگیشن (Irrigation) پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی بہت کم ہے - ہمارے پاس ایک کروڑ ۲۷ لاکھ کسان ہیں اون پر اگر آپ کی رقم تقسیم کی جائے تو فی کسان ایک ایک روپیہ پڑتا ہے اس میں آپ کا پیڈی مکسچر ''پیٹر'' اور'' کرلوسکر'' وغیرہ کے آئیل انجنوں کا خرچہ بھی شامل ہے - اس کسان کے لئے آپ ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں جو لینڈ ریوینیو اور آبکاری کے سلسلہ میں آپ کو سات روپیہ دیتا ہے -

ڈاکٹر چنا ریڈی - اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے متعلق بیڈی مکسچر اور تقاوی وغیرہ کے فیگرس جو آپ بیان کررہے ہیں وہ کہاں سے لئے گئے ہیں -

شری کے - وینکٹ رام راؤ - یہ فینانس سکریٹری کے میمورنڈم میں ہیں - میں اگریکلچر اور ارریگیشن دونوں کے فیگرس کو ملا کر کہہ رہا ہوں - میمورنڈم میں اس سے متعلق ایک چارٹ دیا گیا ہے -

ڈاکٹر چنا ریڈی - آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں - اس میں تقاوی وغیرہ شامل نہیں ہے -

شری کے - وینکٹ رام راؤ - اگریکلچر کے مد کے تحت (۵۷) لاکھ (۴۲) ہزار ہیں اور اریگیشن پر جو خرچ ہورہا ہے وہ ایک کروڑ چھ لاکھ چھیا نوے ہزار ہیں - ان دونوں کو میں نے جمع کیا -

ڈاکٹر چنا ریڈی - میں معافی چاہتا ہوں - اس میں تقاوی - فرٹیلائزر پیڈی مکسچر اور پیٹر اور کرلوسکر (جیسا کہ آپ نے کہا) کے آئیل انجنس کی رقم شریک نہیں ہے -

شری کے - وینکٹ رام راؤ - مجھے اس پر خاص طور پر انسسٹ کرنا نہیں ہے لینڈ ریوینیو اور آبکاری کے نام پر جو کسان آپ کو سات روپیہ دیتا ہے اس میں صرف چار روپیہ آپ اس کے لئے خرچ کریں تو بھی اس کی ضروریات کے لئے کم ہیں - اس طرح اگر حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو خرچ کررہا ہے وہ بہت کم اور ناقابل لحاظ ہے - ایک اور چیز بھی مجھے عرض کرنا ہے - اس وقت ساڑھے چھ کروڑ ایکر زمین ایسی موجود ہے جس کو دوسرے ذرائع سے سیراب کرنے کی ضرورت ہے - میں نے یہ اسٹیٹسٹکس (Statistics) فینانس ڈپارٹمنٹ کے '' اکنا مک افیربلیٹن '' سے لئے ہیں کہیں اور سے کلکٹ نہیں کئے ہیں - اس سے معلوم ہوگا کہ نان پراڈکٹیو (Non-productive) پر اکسپنڈیچر زیادہ کیا جارہا ہے - میں نے راج پرمکھ کے اڈریس (Address) کے وقت اس سلسلہ میں کہا تھا کہ دو میل پر ایک پولیس کا جوان رکھا گیا ہے - ہرموضع میں ایک سیندھی اور شراب کی دوکان رکھی جاسکتی ہے - لیکن ہرموضع میں ایک مدرس کیوں نہیں رکھا جاسکتا - ایجوکیشن منسٹر صاحب نلگنڈہ کی تقریر میں فرمایا کہ ہردو گاؤں کے لئے ایک مدرس کا تقرر کیا گیا ہے - ان اعداد کو ویریفائی (Verify) کرنے کی ضرورت ہے - اگر ایسا ہورہا ہے تو خوشی کی

بات ہے ۔ ایجوکیشن کے سلسلہ میں بجٹ اسپیچ میں اور راج پرمکھ کے اڈریس میں بیسک ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس پر ایجوکیشن کے اکسپرٹس (Experts) کی کیا رائے ہے غور کرنے کی ضرورت ہے محض فیناٹیکلی (Fanatically) بیسک ایجوکیشن (Basic education) کو انٹراڈیوس (Introduce) نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک کنٹروورشیل (Controversial) مسئلہ ہے بیسک ایجوکیشن کو انٹرا ڈیوس کرنے کے سلسلہ میں بہت سی رائے ہیں۔ ہندوستان کے اکسپرٹس اس کے خلاف ہیں ۔ لیکن چونکہ کانگریسی حکومت بر سراقتدار ہے فینیٹیسیزم (Fanaticism) کے طور پر اس کو انٹراڈیوس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے عوام اس کی مخالفت کریں گے ۔ بیسک ایجوکیشن کیا چیز ہے ۔ اس کے سلسلہ میں سی ۔ آر ۔ ریڈی نے کہا ہے ۔ بیسک ایجوکیشن واردھا اسکیم کے تحت ہوگی ۔ جسے راجہ جی اسکیم یا موڈیفائیڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن اسکیم(Modified elementary education scheme) کا نام دیا گیا ہے ۔ اس بیسک ایجوکیشن کے اصول یہ ہیں کہ ہر طالب علم صبح کے دو تین گھنٹے تعلیم حاصل کرے اور پھر اوس کے بعد اپنے ماتا پتا کو کاروبار میں مدد دے ۔ اگر کوئی ہریجن چپل سیتا ہے تو وہ چپل سیا کرے ۔ کوئی دھوبی ہے تو دھوبی کا کام کرے کوئی بڑھئی ہے تو وہ بڑھئی کا کام کرے ۔ اسی طرح حجام لوہار وغیرہ اپنے اپنے کام کریں ۔ بیسک ایجوکیشن کے یہ پرنسپلس ہیں ۔ حیدرآباد کی حکومت کے بیسک ایجوکیشن کے پرنسپلس کیا ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہیں ۔ لیکن بیسک ایجوکیشن کے معنی پورے ہندوستان میں یہی لئے جارہے ہیں ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن کا اسٹانڈرڈ دن بہ دن گرتا جارہا ہے ۔ یہ شکایت اوس طرف اور اس طرف دونوں طرف سے بھی ہے ۔ صبح سے شام تک رگڑ رگڑ کر کام لیا جاتا ہے لیکن تعلیم کا اسٹینڈرڈ تو دن بہ دن گرتا جارہا ہے ۔ صبح میں اگر کوئی پڑھا کرے اور دن بھر چپل سیتا رہے تو وہ کیا تعلیم حاصل کرے گا ۔ ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے سامراج کے ہندوستان میں آنے سے ایک دھکے کے ساتھ زمین پر آرہا تھا لیکن اس پرانے ڈھانچے کی جگہ نئے ڈھانچہ نے نہیں لی ہمارے پرانے دن چلے گئے ۔ لیکن ان دنوں بھی کیا ہورہا ہے بیسک ایجوکیشن کے سلسلہ میں اگر صبح کے وقت کوئی ہریجن پڑھے اور دن بھر چپل سئیے ۔ بڑھئی بڑھئی کا کام کرے حجام حجام کا کام کرے تو پھر آپ سیکولر اسٹیٹ (Secular state) کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بیکار ہوجاتا ہے ۔ کاسٹ ازم (Casteism) کو فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو آپ چور دروازے سے انٹراڈیوس کررہے ہیں ۔ بیسک ایجوکیشن کے جو اثرات ہماری معاشی ۔ معاشرتی زندگی پر اور سماج پر بہت برے اثرات پڑنے والے ہیں ۔ اس سلسلہ میں یہ بحث کی جاسکتی ہے کہ بہت سے لوگ بی ۔ اے ۔ ہیں یم ۔ اے ہیں ان کو بھی روزگار نہیں ملتا اسلئے تعلیم کو صنعتی بنیادوں پر نرمان کرنا ہے لیکن جتنے بھی بنکر اور دستی صنعتوں کے کام کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی مزدور ہیں ان کی حالت کیا ہے ۔ ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

مارکٹ نہیں ہے۔ جوکچھ بھی اسٹاک ہےوہ ڈسپوز آف (Dispose of) نہیں ہوتا ۔ اب آپ جو مزیدبنکروں ۔ حجاموں اور بڑھائیوں کو پیدا کرنے والے ہیں اوس سے دیہی نظام کا ڈھانچہ بننے والا ہےیا بگڑنے والا ہے ۔ اس سے کوئی پرابلم (Problem) سالو (Solve)نہیں ہو سکتا ۔ اس سلسلہ میں اور بھی چیزیں ہیں جن کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر بحث کرتے وقت تفصیل سے کہونگا ۔ لیکن اس وقت بیسک ایجوکیشن کےسلسلہ میں جو فینیٹک آئیڈیا (Fanatic idea)ہے اس کے متعلق حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس پر مکرر غور کرے ۔

سرویسس کے سلسلہ میں بھی مجھے ایک چیز کہنا ہے ۔ پورے حیدرآباد اسٹیٹ میں جہاں کہیں مختلف پارٹیوں کی جانب سے کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اون کے سر پر کونسی ٹوپی ہے ۔ شکایت کیا ہے ۔ وہ غلط ہے یا صحیح یہ نہیں دیکھا جاتا ۔ اس قسم کا جو تصور اور ذہنیت پیدا ہو رہی ہے بجا طور پر حکومت کو ہی میں ذمہ دارگردانتا ہوں ۔ آئے دن میری کانسٹی ٹیونسی (Constituency) میں ہمارے ضلع میں ہمارے تعلقہ میں اس قسم کی شکایتیں آر ہی ہیں ۔ مجھے انکے گنانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ سرویسس (Services) کی یہ حالت ہے ۔ ان حالات کا بدلنا ضروری ہے جب پولیس کے بارے میں شکایت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پی ۔ ڈی ۔ ایف کی جانب سے شکایت ہے سمجھکر اسکو بیس لس (Baseless) قرار دیا جاتا ہے ۔ میں اب دوسرے موضوع پر آؤنگا ۔ وہ یہ کہ حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے کمرشیل کنسرنس (Commercial concerns) جو ہیں انکے بارےمیں سنہ ۱۹۵۲ ع سے جو فینانشیل پالیسی ہم دیکھتے آرہے ہیں اور ہمیں جو سابقہ تجربہ ہوا ہے اسکی روشنی میں اس مسئلہ پر غورکرنا چاہئے ۔ ہمارا سابقہ تجربہ یہ ہےکہ ہمارے سابقہ اندازے غلط ثابت ہوئے ۔ ایک خاص بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان میں برابرکمی ہوتی آرہی ہے ۔ لینڈ ریوینیو میں کمی ہو رہی ہے اکسائیز میں کمی ہو رہی ہے ۔ سیل ٹیکس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ کسٹم کی جگہ لےگا اوسکی بھی آمدنی گر رہی ہے ۔ آبکاری کے بارے میں جواب یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ سیندھی اور تاڑی کے جھاڑ چوری سے تراشے جا رہے ہیں اسکی وجہ سے آمدنی میں کمی ہوئی ہے ۔ لیکن اصلی وجوہات کو ہم جواب میں مفقود پا رہے ہیں ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید گر گئی ہے ۔ اسلئے آمدنی کے مدات گھٹ رہے ہیں ۔

اسکے بعد گورنمنٹ پریس اور اسٹیشنری ڈپو کی طرف توجہ دلاؤنگا ۔ اسکی آمدنی ۳۲ لاکھ ۹۸ ہزار ہے اور خرچ ۳۳ لاکھ سات ہزار ہے ۔ اس طرح اس میں بھی گھاٹا ہے ۔ یہی نہیں بلکہ حکومت کے ھاتھ میں جو بھی کنسرنس (Concerns) ہیں اسی طرح گھاٹے سے چلائے جا رہے ہیں ۔ ان کنسرنس کو نفع بخش طریقے پر چلانے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی ۔ اسکے ساتھ ساتھ الکٹرک ڈپارٹمنٹ کو بھی

دیکھیں تو پتہ چلیگا کہ وہ بھی نقصان سے چل رہا ہے بجٹ کے صفحہ ۱۶ پر تین کنسرنس ہیں - حیدرآباد سکندرآباد اور کھمم - کھمم میں گذشتہ سال گھاٹا آیا ہے - اس سال دو ہزار روپیہ کی آمدنی ہوگی - یہ اعداد دئے گئے ہیں - لیکن معلوم نہیں کہ یہ اندازہ صحیح ہوگا یا نہیں یا وہ بھی پانی کی لکیر ثابت ہوگا - یہی نہیں بلکہ اورنگ آباد رائیچور اور نارائن بیٹھ وغیرہ کے بارے میں غور کریں کہ گذشتہ سال کے مقابلہ میں اس سال نقصان ہورہا ہے - اگر حکومت الکٹرک سٹی کا کسی کو کنٹراکٹ (Contract) دیدیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ دو دو ہزار روپیہ آسکتے تھے - اس طرح ان امور پر کیوں توجہ نہیں کی جاتی -

اوسی طرح آر- ٹی - ڈی کے بارے میں میں کہونگا کہ خوش قسمتی سے یہاں کافی روڈس ہیں جہاں ہم آر- ٹی - ڈی کی بسس چلاسکتے ہیں - آر- ٹی - ڈی کے بجٹ کو سنٹرل گورنمنٹ کے ریلوے بجٹ کا درجہ حاصل ہے - ہمارے سامنے سورسس موجود ہیں آر- ٹی - ڈی کے بسس کے جال کو وسیع کیا جاسکتا ہے - اسبارے میں فینانس منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کوئی ذکر نہیں کیا - اسلئے ہم اسبارے میں مایوس ہیں - اسی طرح جتنے کمرشیل کنسرن ہیں وہ گھاٹے پر چل رہے ہیں - اگر نفع بخش طریقے پر کاروبار کئے جائیں تو دو کروڑ کا جو گھاٹا بجٹ میں آیا ہے وہ نہ آتا - اور ہم حالات کا مقابلہ کرسکتے -

اسکے بعد ایک رنگین تصویر یہ پیش کی گئی ہے کہ اگریکلچر کے حالات اچھے ہیں - انڈسٹریز کے حالات اچھے ہیں - لیکن حالات در اصل اسکے خلاف ہیں - اگریکلچر کی حالت دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کسانوں کی آمدنی کا ذریعہ کیاش کراپس (Cash crops) ہے - مثال کے طور پر کیاسٹر سیڈس (Castor seeds) کی پیدا وار پورے ہندوستان کی پیدوار کا حیدرآباد کی پیداوار ۵۰ فیصد سے کچھ زیادہ ہے اور میجر اکسپورٹنگ (Major exporting) کی چیز ہے - گذشتہ سال ۱۴۰ روپیہ فی پلہ اسکی قیمت تھی لیکن آج ۳۳ روپیہ تک اسکا بھاؤ گر گیا ہے - وہی حالت ولائتی مونگ کی ہے - اسی طرح چاول جوار اور دھان کی قیمتوں کا حال ہے انکی قیمتیں بھی گررہی ہیں - آج کسانوں کا مطالبہ ہے کہ فکسڈ پرائس (Fixed price) کی گیارنٹی حکومت دے - آج جو رنگین تصویر دکھائی جا رہی ہے اور جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچے خواب نہیں نظر آتے - انڈسٹریز کے سلسلہ میں جیسا کہ کارپوریشن قائم کیا گیا ہے اسی طرح اگریکلچر کے لئے بھی اگریکلچرل فینانس کارپوریشن قائم کرنا چاہئے - لیکن اگریکلچرل فینانس کارپوریشن ابتک قائم نہیں کیا گیا ہے - معلوم نہیں کہ اس سلسلہ میں حکومت کیا سوچ رہی ہے -

پبلک ڈیٹس (Public debts) کے جو قرضہ جات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں - گوروالا کمیٹی نے ۲۲ کروڑ کے لگ بھگ ان قرضہ جات کی مقدار بتائی تھی لیکن اب وہ ۶۳ کروڑ تک پہنچ گئے ہیں - حیدرآباد کمرشیل کارپوریشن کو جو قرضہ دیا گیا

تھا اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے - ٹاکاز اور حیدرآباد کمرشیل کارپوریشن کا ناطہ ہے - وہ خود بھی ڈوبےگا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبےگا - وہ رقم آنے والی ہے یا ڈوب جانے والی ہے معلوم نہیں - نام کے لئے کتابیں بھرکر رکھنے میں میں کوئی مصلحت نہیں پاتا - ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمدنی کے تمام مدات گرتے جا رہے ہیں - سنہ ۱۹۵۲ - ۵۱ع سے برابر یہی حال ہے خسارہ بڑھتا جارہا ہے - رزروس (Reserves) ختم ہوتے جا رہے ہیں - اب جوزسورسس بچ گئے ہیں وہ ناقابل استعال ہیں صرف اپنے پاس لکڑی کا آم رہگیا ہے - اس کا جواب اوس طرف کے آنریبل ممبرس دیں - عام فہم آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری فینانشیل پوزیشن (Financial position) ساؤنڈ (Sound) ہے - فائیوایر پلان (Five Year Plan) کے بارے میں میں اسلئے نہیں کہونگا کہ وقت نہیں ہے - پبلک فینانس جو ٹریژری بنچس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اوس سے متعلق میں کہونگا کہ پبلک فینانس آپ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے - حکومت اسکے تحفظ کے لئے کوئی فکر نہیں کر رہی ہے - اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں -

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अध्यक्ष महोदय, बजेट के जनरल डिसकशन में अभी तक अिसके पहले तीन वक्ताओं ने अपने विचार हाअुस के सामने रखे हैं। यु. पी. पी. के नेता श्री जी. राजाराम ने अपने भाषण में कहा कि बजेट फार्म करते वक्त गव्हर्नमेंट के सामने कोअी खास नकशा नहीं था। मुझे बडा आश्चर्य होता है कि अिस तरह कैसे बोला जासकता है। जब यहां पर अेक पार्टि की हुकूमत कायम है, अुसी तरह तमाम रियासतों में और सेंटर में भी अेक ही पार्टि की हुकूमत कायम है। वह पार्टि जब बजेट पेश करती है तब अधांधुंद बजेट कैसे पेश कर सकती है। हमारा अेक पंच वर्षिय प्लॅन है और प्लॅन को पूरा करने के लिये बजेट बनाया जा रहा है। हमारी संस्था की तरफ से भी हमें पूछनेवालें लोग होते हैं। अुनकी अेक कमिटी है, अिस पार्टि का पार्लमेंट्री बोर्ड भी है। वह सभी बातों पर निग्रानी रखता है और पार्टि के आदेशानुसार स्टेट की सरकारें काम कर रही हैं या नहीं सब देखा जाता है, और अुन्ही की सलाह व मश्वरे से सारी चीजें की जाती हैं। मुझे अिस बजेट में कोअी मायुसी नजर नही आ रही है। मैं अिसके बारे में बाद विचार रखुंगा।

दूसरे जो वक्ता लिडर ऑफ दी अपोजिशन हैं, अुन्होंने भी अपना भाषण दिया अिसके पहले बजेट पर अुनके तीन भाषण हुअे। अुन भाषणों को सुनने के बाद मुझे अैसा मालूम हुवा कि वे तमाम भाषण काफी फायरी (Fiery) थे, लेकिन आज के अुनके भाषण में मैं काफी माअिल्डनेस (Mildness) पाता हूं। मालूम नहीं अैसा क्यों हुवा। क्या यह कोअी स्टॅटेजी (Strategy) तो नही है? पिछले दो सालों में अैसे लब्ज अिस्तेमाल किये गये कि यह जागिरदाराना बजेट है जमीनदाराना और फ्युडल बजेट है और भी बहुत कुछ कहा जाता रहा था। पहले जो अेपिथेट्स (Epithets) दिये जाते थे वह आज के अुनके भाषण में कहीं नजर नहीं आते है। यह कैसे हुवा क्या यह कोअी स्टॅटेजी (Strategy) है कि आज हिंद पर संकट आ रहा है अिस लिये अुसको मदद करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अैसे संकट के समय सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट को कोअी तकलीफ न हो। अैसी तो कोअी स्टॅटेजी (Strategy) अिसमें नही है? अुनके अिस साल के स्पीच में काफी रियलिझम (Realism) भी आया है।

निजाम साहब के २५ लाख रुपये का जो कट किया गया अुसका क्रेडिट (Credit) वे खुद को लेना चाहते हैं। अुन्होंने कहा की हमारी ही वजह से यह २५ लाख रुपये की कमी होगअी है, लेकिन अिसका क्रेडिट आप लेना चाहे तो लें, लेकिन यह कोअी आपका क्रेडिट नही है। मैं कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस यह अेक प्रोग्रेसिव्ह पार्टि (Progressive Party) है, और अुसके नेता पंडित नेहरू भी प्रोग्रेसिव्ह हैं। अुन ही की वजह से निजाम साहब ने २५ लाख रुपये छोडे हैं। आपको अुसका क्रेडिट नही है। यदि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भलेही लीजिये।

अब मैं अिस बजेट पर आता हूं। मेरे दोस्तों को अिस बजेट में निराशा मालूम हुअी, लेकिन मुझे तो यह बजेट प्रोग्रेसिव्ह (Progressive) ही मालूम होता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह बजेट बहुत ही प्रोग्रेसिव्ह है, लेकिन फिर भी बजेट निराशाजनक तो नहीं है अितना मैं कह सकता हूं।

बजेट पर चर्चा करते हुवे मैं दो तीन चीजों को पहले हाअुस के सामने रखना चाहता हूं। हमारा यह जो बजेट है वह अेक स्टेट बजेट है और कांस्टिटयुशन ऑफ अिंडिया के लिहाज से हमारे पास जो आमदनी के रिसोर्सेस (Resources) दिये गये हैं, अुससे हमें ज्यादा आमदनी नहीं हो सकती। जो ज्यादा आमदनी के जरिये हैं वे सेंट्रल नें अपने पास रखे हैं। यह बात हमें ख्याल में रखनी चाहिये। अभी अेक टॅक्स अिनक्वायरी कमिशन बैठा है। अुसके सामने हमें अिस चीज को रखना चाहिये कि आजकल डेव्हलपमेंट स्कीमस्पर स्टेट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पडता है, लेकिन अुनके आमदनी के रिसोर्सेस बहुत कम हैं। अुनके पास जो मद रखे गये हैं, अुनसे आमदनी बहुत कम होती हैं। अिस लिये स्टेट के पास ज्यादा आमदनी के मद को भी रखा जाना चाहिये।

हमारा देश अेक गरीब देश है। और जो देश गरीब होता है अुसकी सरकार भी गरीब होती है। सरकार अमीर रहे और देश गरीब रहे अैसा नहीं हो सकता। सरकार यह तो जनता का या देश का अेक पिक्चर है। सरकार यह तो मिरर (Mirror) यानी अैना है। जैसी जनता होती है वैसे ही अुसकी सरकार भी। जहां जनता गरीब है वहां अुसकी सरकार के पास भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हमारे स्टेट का बजेट ३० करोड का है और हमारी जनता दो करोड की है, यानी हर आदमी जो अिस स्टेट में रहता है वह सिर्फ १५ रुपये सरकार के खजाने में डालता है। अिससे जाहिर है कि हमारा देश कितना गरीब है। तब हमारा बजेट भी कमी का ही रहेगा। अैसा होना लाजमी है। जब हम अिसकी पॉवरटी (Poverty) कम करेंगे तो अिसकी टॅक्स पेअिंग कपॉसिटी (Tax paying capacity) बढ सकती है और हमारे स्टेट बजेट में ज्यादा पैसा आ सकता है। हमारे दोस्त यदि अिस साल के तमाम स्टेटों का बजेट देखें तो अुन्हे मालूम होगा कि ज्यादा तर रियासतों का डिफिशियेट (Deficit) बजेट है। आंध्र स्टेट के बजेट में साढेतीन चार करोड का डिफिसियेट, है, तो मद्रास के बजेट में ४ करोड का डिफिसियेट है। डिफिसियेट बजेट आता है अिस लिये घबराने की जरूरत नही हैं। आप यदि गये ५ सालों में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा कारोबार बढा है। हमारे रेव्हिन्यु में तथा खर्चे में ज्यादा बढाअी दिखेगी। हम यदि सन ५०-५१ के फिगर्स देखें तो मालूम होगा कि रेव्हिन्यू अेक्सपिंडिचर २६ करोड का और कॅपिटिल अेक्सपिंडिचर ५ करोड का है, अिस तरह ३१ करोड का खर्चा था। सन ५१-५२ में कॅपिटिल अेक्सपिंडिचर ६ करोड और रेव्हिन्यू अेक्सपिंडिचर २९ करोड सन ५२-५३ में ३२ करोड

५३-५४ मे २५ करोड ५४-५५ में ३७ करोड। अिस को देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे स्टेट के खर्चमें ५ करोड रुपये की वृद्धि हुअी है। अुसकी वजुहात दो तीन हैं। अेक तो यह है कि हमारे यहां सोशल वेल्फेयर स्टेट का ध्येय रहा है। अिस लिये यह खर्चा बढता जायेगा। दुसरे जो पंच साला प्लॅन है अुसको भी अिंप्लिमेंट (Implement) करने की जिम्मेदारी स्टेट पर ही आअी है। अिस लिये यह ५ करोड रुपये का बढावा हुवा है।

फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अिस बजेटका ब्याकग्राअुंड (Background) बनाते हुअे अेक अच्छा पिक्चर हमारे सामने लाया है। अिस साल हमारा अॅग्रिकल्चरल प्रोडक्शन (Agricultural production) बढा है। हम अन अेम्प्लायमेंट (Unemployment) को पूरी तरह से चेक तो नही कर सकें है, लेकिन फिर भी अुसे कम करने की हमने पूरी कोशिश की है। प्राअिसेस भी अब ठीक हो रहे है, और अुनका रूझान कम होने की तरफ है। अिंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (Industrial production) में भी वृद्धि हुअी है।

यह जो बजेट हमारे सामने आया है अुसमें सिर्फ १ करोड का डेफिशियट नहीं है। १ करोड का ही डिफिशियट है यह कहना सही न होगा। रेविन्यु का १ करोड ५ लाख और कॅपिटिल का अेक करोड कुछ लाख अिस तरह करीब करीब २ करोड ७९ लाख का डिफिसियट है। मैंने तो पहले ही कहा कि हमारा बजेट डिफिसियट है, अिस लिये घवराने की जरूरत नही है। अब हमारे प्लॅनस पूरे होने के लिये दो साल बाकी है और अुनको पूरा करने के लिये ज्यादा खर्चा आ रहा है अिस लिये घाटा नजर आ रहा है। यह घाटा कैसे मिलायेंगे ? यह घाटे को कम करने के लिये फायनान्स मिनिस्टर साहब सिर्फ दो टॅक्स बिठानेवाले है। अुनमें से अेक मोटर विहिकल्स टॅक्स है और दूसरा शुगरकेन टॅक्स है। मैं कहना चाहता हूं कि गव्हर्नमेंट को और भी टॅक्स के जरिये टॅप (Tap)करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा पैसा मिल सकें। पेट्रोल का जो टॅक्स है अुसे बढाने की जरूरत है। बॉम्बे में यह टॅक्स ६ आना है हमारे पास यह टॅक्स कम है। अुसमें बढाने की गुंजायश है। अिस टॅक्स को भी टॅप करना चाहिये। स्कूल व कालेज फीस भी हमारे यहां दूसरे स्टेट के मुकाबलें में कम है। अुसे भी हम बढा सकते हैं। प्रेशस स्टोन्स (Precious stones) और सोनें चांदी के गहनों पर ज्यादा सेल्स टॅक्स लगाया जा सकता है। हम रेविन्यु और अेक्सपेंडिचर को देखें तो मालूम होगा कि हमारा खर्चा अब नेशन बिल्डिग पर ज्यादा हो रहा है। हम यदि अिस बजेट में देखेंगे तो मालूम होगा कि पहले जो ३८.९ परेसेंट खर्चा नॅशनल डेव्हलपमेंट पर किया जाता था वह आज ४१.३७ तक बढा है, रेव्हिन्यु और कॅपिटिल अकाअुंट मे २० करोड तक खर्चा बढा है। जैसे अिरिगेशन बढा है। अेज्युकेशन, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल, अॅग्रिकल्चर, व्हेटरनरी, कोऑपरेशन, अिंडस्टीज, सिविल सप्लाअिज अिस तरह से करीब २० करोड रुपये नेशन बिल्डिग पर खर्च किये जा रहे हैं।

कुछ चीजें अैसी हैं जिन पर गव्हर्नमेंट फक्र करती है। अेज्युकेशन का बजेट देखेंगे तो आपको मालूम होगा, और फायनान्स मिनिस्टर ने भी अपने बजेट स्पीच में कहा है कि ४७-४८ में २९२ लाख खर्चा अेज्युकेशन पर किया जाता था, और आज अेज्युकेशन पर ५१० लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। बजेट का १७.४७% अेज्युकेशन पर खर्च किया जा रहा है। पहले पुलिस पर ज्यादा खर्चा किया जाता था लेकिन आज यह खर्चा अेज्युकेशन पर ज्यादा हो रहा है। बेसिक अेज्युकेशन के बारें में बहुत कुछ कहा गया। मै अब अिस वक्त अस डिटेल (Detail) में नही जात

हूं लेकिन बेसिक अेज्युकेशन यह हमारी अेक पॉलिसी है। कॉंग्रेस गव्हर्नमेंट अुसको मानती है और अुसको देहातों मे चलाना चाहती हैं। देहातों में सही अेज्युकेशन का तरीका यही है। खाली दीमागी शिक्षा से काम नही चलता। विद्यार्थियों को हाथ से भी काम करना चाहिये। आप कहते हैं कि आपके कहने के मुताबिक सरकार नही चलती है लेकिन अिस बारें में हमारा अेक कनविकशन (Conviction) है अुसे आप फॅड (Fad) कहे या कुछ भी कहे लेकिन हम तो बेसिक अेज्युकेशन चलानेवाले हे। हमारे पॉलिसी के लिहाज से गव्हर्नमेंट अपनी अिस बेसिक अेज्युकेशन की पॉलिसी को नही छोडेगी।

कहा गया कि कंपलसरी अेज्युकेशन पर हमारी गव्हर्नमेंट कम खर्च कर रही है। कहा गया कि कंपलसरी अेज्युकेशन पूरे स्टेट में नही है। अेक भी जिले में स्कूल नहीं खोले गये और यही कहा गया कि जिले में २० स्कूल खोले गये हैं।

श्री. वि. के. कोरटकर :—यह कहा गया कि पूरे स्टेट में २० स्कूल्स खोले गये हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अभी मुझे यह कहा गया कि अुस तरफ से यह कहा गया कि सारे स्टेट में २० स्कूल खोले गये हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि प्रॉजेक्ट अेरियामे ५०, ६० देहातों मे खोले गये हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में २० स्कूल्स हैं। हमारे स्टेट में प्रायमरि अेज्युकेशन मै जो प्रगति की गअी है वह दिगर बी. पार्ट स्टेटोंमे नही की गअी है। गव्हर्नमेंट आज प्रायमरी अेज्युकेशन के बारें में जो काम कर रही है वह काफी है, अभीमानास्पद है।

मेडीकल और हेल्थ के बारे में भी गव्हर्नमेंट कुछ खर्च कर रही है। फाअिव अिअर प्लॉन (Five-Year Plan) का प्रोग्रेस भी कुछ निराशाजनक नहीं है। अुसमें भी कअी चीजें हैं। हरिजन वेलफेअर के बारे में १० लाख रुपये शेडूल्डकॉस्ट ट्रस्ट फंड में गव्हर्नमेंट डाल रही है। ६ लाख रुपये हरिजन वेलफेअर स्कीम्स के लिये अिस साल खर्च किये गये हैं। मेरे मित्र ने कहा कि हमारे स्टेट में हरिजनों की आबादी ३०-३२ लाख है, अुनमें अगर यह रक्कम बांटी जाय तो हर अेक के लिये आठ आने आ जायेंगे। अिस तरह से अगर रुपया हम बांटते फिरेंगे तो यह सवाल हल होनेवाला नहीं है और न अिस तरह से कभी हिसाब लगाया जा सकता है। अिसमें और भी रुपया खर्च किया जाय तो भी पूरे स्टेट के हरिजनों की दिक्कतें अेकदम से दूर नहीं की जा सकतीं। सिर्फ रुपये बांटनेसे या अुनको डिव्हाअिड (Divide) करने से यह मसला हल नहीं होगा। कम्युनिटी प्रोजेक्ट(Community Project)के तहत लोकल डेव्हलपमेंट स्कीम्स में भी गव्हर्नअेंट ने काफी प्रोग्रेस किया है। साथ साथ अिस साल में.——

مسٹر چیرمن : - آنریبل ممبر ذرا وقت کا خیال رکھیں -

श्री रतनलाल कोटेचा :—दूसरे वक्ताओं को मैं समझता हूं कि अेक या डेढ घंटे तक का समय दिया गया है। मैं अिसका स्टडी (Study) करके आया हूं मुझे ज्यादा वक्त मिलना चाहिये, नहीं तो मुझे बैठना पडेगा।——

Chairman: Order, order. Five minutes more.

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अिस बजेट में आप देखेंगे किपुलिस का खर्चा भी बहुत कम हुआ है। पहले १७ या २० परसेंट तक था असको घटाते घटाते अब ११ परसेंट तक लाया गया है। अिसके लिये

मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन मै अुनसे यह भी कहना चाहूंगा कि वे काम्प्लेसंट (Complacent) न रहे क्योंकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पालिसी में बदल नहीं किया है। अभी अुनकी जो मदुराअी में कान्फरन्स हुअी अुसके रेजोल्यूशन्स को वह देखें। साथ साथ कलकत्ते में जो चीजें हुअी है अुनको भी हमें देखना चाहिये। हमारा धोका अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। अिस लिहाज से हमको ज्यादा सोंचकर चलना चाहिये। कॉंग्रेस गव्हर्नमेंट को हमारे अेक मित्र ने अुपदेश दिया है कि आप अिस खर्च को घटाअिये। कॉंग्रेस गव्हर्नमेंट को अिस तरह के अुपदेश की जरूरत नहीं है क्यों कि हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतता की पालिसी को चाहनेवाले है और पाकिस्तान का जो संकट हमारे सामने है वह होते हुअे भी जहां सेंट्रल गव्हर्नमेंट ने अपनी मिलटरी का खर्चा नही बढाया तब हम यहां कैसे बढायेंगे। लेकिन यह खर्चा न बढे अिसकी ज्यादा जिम्मेदारी हमारे दोस्तों पर है। हमारे कॅश बॅलन्सेस (Cash balances) के बारे में हमारे दोस्त ने जो बातें कही अुनमें बहुत सी सत्यता है अिसको हमें मानना पडेगा अिसके बारे में हमारी गव्हर्नमेंट को संजीदगी से सोचना पडेगा कि यह रवकम दिन प्रति दिन घटती जा रही है। कॅश बॅलन्सेस अेक तरह से हमारी गव्हर्नमेंट मशीनरीका ब्लड (Blood) है। व्यापारी के पास कॅश-बैलन्स न हो और दूसरे तरीके से कितना ही ज्यायदाद हो अुसका कुछ फायदा नहीं। अुसी तरीके से हुकूमत के पास कॅश-बैलन्सेस काफी मेकदार में न हों तो फायदा नहीं होगा क्योकि कॅश-बॅलन्सेस हमारे पास हों तो ही हम कुछ काम कर सकते है। अिसमें मैने अेक बात और देखी कि १० करोड में से ५ करोड रुपये स्टेट बॅक को विधान सभा की बिना अनुमति दिये गये हैं। यह कान्स्टीटयूशन (Constitution) के खिलाफ बात है। स्टेट बॅक को यह रवकम बिना व्याज के दी गअी है या व्याज से दी गअी है और कितने व्याज से दी गअी है अिसके बारे में फायनान्स मिनिस्टर को जवाब देना पडेगा। अिसी तरह से जैसा कि अपोजीशन के लीडर साहबने बताया हमारे रिजर्व्हज भी कैसी जगहों पर लगाये गये हैं जो जल्द लिक्विडेट तो नहीं होंगे। अिसका भी हमको ख्याल करना पडेगा।

अिसके बाद दो तीन बातों की तरफ मैं हाअुस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर मैं पांच दस मिनट और लूं तो मुझे आशा है स्पीकर साहब माफ करेंगे। सेल्स टॅक्स का अेक बडा आयटम है। गये साल भी बजट के वक्त मैंनें सूचना दी थी लेकिन गव्हर्नमेंट ने अुस पर जितना सोंचना चाहिये था अुतना नहीं सोंचा। यह अेक बडा आयटम है जिसके जरिये से हम अपनी आमदनी बढा सकते हैं। बंबअी में १८ करोड और मद्रास में १६ या १७ करोड की आमदनी सेल्स टॅक्स से होती है। हमारे यहां सिर्फ दो करोड की आमदनी होती है। दूसरे प्रांतों में यह आमदनी बढती है लेकिन हमारे यहां यह नहीं बढती। अिसकी वजह यह है कि कस्टम्स की वजह से हमारी गव्हर्नमेंट अिसकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज का सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट का अॅडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों के हाथ में है मुझे माफ किया जाय वे अेफिशिअंट (Efficient) नहीं है अैसा मालूम होता है, क्योंकि बाकी रियासतों में अिसका अिनकम बढता जा रहा है लेकिन हमारे यहां वह नहीं बढता अैसा क्यों होता है? यह अिनकम हमारे यहां ५-६ करोड तक बढना चाहिये। अेग्रीकल्चरल अिनकमटॅक्स (Agricultural Income Tax) के बारे में हमारे अेक दोस्त ने कहा अुससे मै सहमत हूं। अिस साल आर. टी. डी. (R.T.D.) का भी बजट हमारे सामने आया है यह खुशी की बात है, लेकिन अिसमें भी हमें कम अुत्पन्न होता है। मुझे मालूम नही हो सकता कि

हमारे यहां ही अिसका भी अुत्पन्न कम क्यों है । बंबअी में गुडस सर्विसेस का दिन ब दिन अेक्सटेन्शन (Extension) होता जा रहा है और हमारे यहां वह कम होता जा रहा है । पहले जो गुडस सर्विस से ९ लाख का अुत्पन्न होता था वह आज ४ लाख तक आ गया है । अिसका मतलब यह है कि आर. टी. डी. का अॅडमिनिस्ट्रेशन ठीक नही है । बीड जिले में मैं ने देखा कि वहां का बसेस का अॅडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज (Loose) है और अिसकी वजह से गव्हर्नमेंट को नुकसान होता है । फूड सबसिडी के तौर पर अिस बस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को ६ लाख रुपये दिये जाते हैं, लेकिन अब कंट्रोल निकाल देने के बाद यह देने की जरूरत नही है अैसा मैं समझता हूं । साथ साथ अिस बस डिपार्टमेंट के बजट में पैसेजरों की सुविधाओं का कोअी ख्याल नही किया गया है । यह कोअी पैसा कमाने का कन्सर्न नही है। यह अेक तरह से नेशनल कन्सर्न (National concern) है बंबअी में चार साल कबल बस डिपार्टमेंट कायम हुआ है और अब तक पैसेंजरों को कअी तरह की अमेनिटीज (Amenities) मिली हैं, लेकिन हमारे यहां पुराना ही तरीका चल रहा है । बस में घुसना हो तो अभी भी धक्के खाने पडते हैं । अिसलिये मै होम मिनिस्टर साहब से विनंती करूंगा कि वे अिस पर सोचें । यह अेक मामूली सी चीज है लेकिन अुस पर भी नहीं सोंचा जाता ।

अिसके बाद फायनान्स मिनिस्टर के नजर में मैं अेक चीज दुख के साथ लाना चाहता हूं । वह यह है कि मराठवाडे के डेव्हलपमेंट के बारे में अिस बजट में कोअी खास प्रोवीजन (Provision) नहीं किया गया है । चीफ मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को अेक नोट दिया था जिसमें बताया गया था कि तीन करोड में से दो तिहाअी रुपया मराठवाडे के लिये रिजर्व्ह रखेंगे, लेकिन अब दु:ख के साथ कहना पडता है कि अिसमें फीगर्स देखें तो अेक करोड से ज्यादा रक्कम नहीं रखी गअी है । ८० लाख रुपये अिरीगेशन के लिये और २५ या २६ लाख रुपये बंडिंग के लिये रखे गये हैं। यह रक्कम भी तीन साल के लिये प्रोवाअिड (Provide) की गअी है । मैं गव्हर्नमेंट को वार्न (Warn) करना चाहता हूं कि मराठवाडे के कॉंग्रेस अेम. अेल. अेज. अिसके बारे में काफी बेचैन हैं । यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह सवाल कोटेचा का गोपालशास्त्री देव का या मोरे का नहीं है बल्कि यह मराठवाडे के लाखों लोगों का जो भूखे और नंगे हैं अुनका सवाल है । अुनके जीवन का यह सवाल है । वहां की हालत खराब हो गअी है । मैंने खुद अपनी कान्स्टीटयूअन्सी (Constituency) पाटोदा में देखा कि तकरीबन २०-२५ हजार लोग छ: छ: महीने अपना घरबार छोड कर पैसे कमाने के लिये बाहर जाते हैं पैदावार बढाने के कोअी सोर्सेस (Sources) ही वहां नहीं है, कोअी अनीकट (Anicut) नहीं हैं, कोअी डैम्स (Dams) नहीं है.

श्री. रतनलाल कोटेचा :—पेटभरने के लिये वही मतलब है । मराठवाडे की तरफ से दो तीन मांगें हैं । वहां अिरीगेशन सोर्सेस का अब तक अिन्व्हेस्टीगेशन (Investigation) तक नहीं हुआ है । मैंने अपने दौरे में देखा कि कअी अैसी जगेंहें मराठवाडे में हैं जहां अनीकटस और डॅम्स हो सकते हैं लेकिन अभी तक वहां कोअी सर्वे पार्टी तक नहीं आअी है । अिस सिलसिले में मैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मिला था । अुन्होंने वायदा किया था कि बजट में सर्वे के लिये गुंजाअिश रखी जायगी, लेकिन अिस बजट में हम देखते हैं कि वह भी नहीं रखी गअी है ।

आयंदा दो साल मे अिरीगेशन रिसोर्सेस का सर्व्हे नही हुआ तो अगली पंच वार्षिक योजना मे अिनको शामिल नहीं किया जायगा और आज हम जिस तरह नगे है वैसे ही बाद में भी रहेंगे। मराठवाडे के लिये तीन चीजें करनी चाहिये ।पहली यह की पूर्णा प्रोजेक्ट को पंचवार्षिक योजना में शामिल करना पडेगा। मराठवाडे के लिहाज से अिरीगेशन रीसोर्सेस (Irrigation resources) का सर्वे किया जाना चाहिये और मायनर अिरीगेशन(Minor irrigation) के लिये जो तीन करोड रुपया सेंट्रल गव्हर्नमेंट से आया है और जो ब्रीच्ड टँक्स (Breached Tanks) के लिये तकरीबन खर्च किया जाता है अुसमें से कुछ हिस्सा मराठवाडे के मायनर अिरीगेशन के लिये खर्च किया जाना चाहिये। यह हम काँग्रेस अेम. अेल. अेज. की तरफ से माग है और गव्हर्नमेंट को अिसके बारे में संजीदगीसे सोचना चाहिये।

अिस बजट को पढने से मुझे अेक और मायूसी हुअी। अिस ३२ करोड के बजट में देहातों की मेडीकल अेड (Medical aid) के लिये सिर्फ डेढ लाख रुपया रखा गया है, जो आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज पर खर्च होनेवाला है। यह कोअी ठीक बात नही है। बंबअी प्रांतमें हर पंधरा बीस गावों के लिये अेक आयुर्वेदिक डिसपेन्सरी होती है। हमारे तालुके में क्या है? पाटोदा तालुके में तो अेक भी डिसपेन्सरी नहीं है। बंबअी के हर तालुके में तकरीबन ६-७ आयुर्वेदिक डिसपेन्सरीज हैं। अिसके लिये ज्यादा खर्च भी नही लगता। हर तालुके में तीन चार डिसपेन्सरीज रखी जायें तो ज्यादा खर्च नहीं होनेवाला है। बंबअी में अिसका हिसाब देखें तो ८ लाख का खर्च आता है। हमारे देहातों के लोग अल्पसंतुष्ट है। शहरों के लोग अितने अल्पसंतुष्ट नहीं हैं। अिसलिये मैं कहूंगा कि हुकूमत को रूरल अेरियाज के लिये टाप प्रयॉरिटी देनी पडेगी और हैदराबाद जैसे शहरों में जो लोग रहते हैं अुनकी तरफ कम ध्यान देकर देहातों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। काँग्रेस देहातियों को ख्याल करने के लिये ही बनी है और अुनकी तरक्की करना ही काँग्रेस का पहला ध्येय है। महात्मा गांधी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें देहातियों की तरफ सब से पहले ध्यान देना चाहिये क्यों कि वे ही भूखे है और नंगे हैं। मैं आशा करता हूं कि हुकूमत अिन चीजों की तरफ ध्यान देगी।

श्री. नागोराव विश्वनाथराव पाठक (सिल्लोड):—अध्यक्ष महाराज, आज १९५४-५५ सालचे बजेट असेंब्ली समोर आहे. या बाबत बऱ्याच ऑनरेबल मेंबर्सनी निरनिराळ्या प्रकारे टीका प्रतिटीका केली. मला अेवढेंच सांगावयाचे आहे कीं मागच्या दोन वर्षांच्या बजेट पेक्षां हे बजेट ठीक आहे. कारण या मध्यें शिक्षणा करिता आणि अितर लोकोपयोगी कामा करिता बराचसा खर्च गव्हर्नमेंट करणार आहे.

आतांच अेका माननीय सभासदाने सांगितले कीं जरी हें बजेट, चांगलें आहे, यांत सरकारने कांहीं कामें चांगलीं केलीं आहेत तरी यांत अेक गोष्ट मात्र निश्चित आहे कीं मराठवाड्याकडे यांत दुर्लक्ष केलें आहे. रजाकरांच्या काळांत किंवा निजामाच्या काळांत मराठवाड्याची जशी अवहेलना होत असे, त्यांत याही सरकारच्या काळांत कमीपणा नाहीं. मला या सरकारला विचारावयाचें आहे कीं तुम्ही मराठवाड्याची अशा प्रकारे अवहेलना किती दिवस करणार आहांत आणि मराठवाड्यांतील लोक व त्यांचे प्रतिनिधी किती दिवस चूप बसून राहणार आहेत? ज्यावेळेस आम्हाला लोकांनी निवडून दिले, आपले प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला येथें पाठविले, तेव्हां पासून लोकांचे म्हणणे काय आहे, हें सरकारपुढे मांडण्याचा आमचा अधिकार आहे, आणि तें आमचें कर्तव्यहि आहे. अुदाहरणादाखल मला अेक गोष्ट सांगावयाची आहे. मागें मुख्य मंत्र्यांनी अेक स्टेटमेंट दिलें होतें

माकीं, मराठवाड्यामध्यें मोठमोठ्या धरण योजना होअूं शकत नाहीत, कारण तेथील परिस्थिति तशी नाही, तरीहि आम्हीं तेथे नव्या योजना घेतल्या आहेत. परंतु मला मोठ्या खेदाने म्हणावें लागते कीं औरंगाबाद जिल्ह्यामध्यें पांच योजना असून त्या पैकीं अजून अेकहि सुरूं झाली नाहीं.

वर्षा दीड वर्षापूर्वी श्री. राममूर्ती, आणि माननीय फायनान्स मिनिस्टर यांनी औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्याचा दौरा केला होता, व त्यांनी सांगितलें होतें कीं मराठवाड्यामध्यें मोठ्या योजना जरी निघूं शकल्या नाहीत तरी लहानलहान योजना निघूं शकतात, व या भागाची परिस्थिती सुधरूं शकते. तेव्हां कुठे आमचे मंत्री मराठवाड्यामध्यें लहान योजना होअूं शकतात हे कबूल करावयास लागले.

आपण म्हणाल कीं मराठवाड्याच्या लोकांत प्रांतियवाद वाढला आहे. मला त्यांना सांगावयाचे आहे कीं हा प्रांतीयवाद नव्हे. आतां पर्यंत मराठवाड्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलें त्यामुळें आम्हाला असें बोलावें लागते. मराठवाड्यामध्यें लहानलहान योजना सुद्धां केल्या जात नाहींत. मला सरकारला असें सुचवावयाचे आहे कीं आपण जसा ग्रो मोअर फुड (Grow More Food) वगैरे सारख्या अितर चांगल्या गोष्टीवर खर्च करता, तसाच मराठवाड्यांतील लहान लहान योजनांवरही करा. तुम्ही जर मराठवाड्यांतील परिस्थिती पाहिली, आणि तिचे सरकारी रिपोर्टवरून व तज्ञांच्या मतावरून अवलोकन केलें तर, आपणास असें दिसून येअील कीं बहुतेक वर्षी तिथे दुष्काळ पडतो. तेथे पिण्याचें पाणी पूरेसे नाही. म्हणून माझी फायनान्स मिनिस्टरना अशी विनंती आहे कीं कमीतकमी पूर्णा प्राजेक्ट तरी या पंचवार्षिक योजनेमध्यें पूर्ण करा, आणि नंतर ज्या कांहीं लहान लहान योजना आहेत त्यांना सुरवात करा.

आतांच अेका सन्माननीय सभासदाने सांगितले कीं मराठवाड्याची प्रगती झाली पाहिजे, आणि त्या करितां सरकारने सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याखेरीज आम्ही अितर प्रांतांच्या बरोबर येअूं शकणार नाहींत. मला कोणाचे हेवेदावे करावयाचे नाहींत. पण मराठवाड्याची प्रगति व्हावी, हीच आमची अिच्छा आहे. मला आशा आहे कीं फायनान्स, मिनिस्टर मी केलेल्या सूचनाकडे काळजी पूर्वक लक्ष देतील अेवढे बोलून मी आपले भाषण संपवितों.

श्री. गोपिडी गंगारेड्डी :— मैं दो और दो चार विषयों पर बोलना चाहता हूं । मुझको यदि कल मौका दिया जायेगा तो मैं कल शुरू में बोलूंगा ।

శ్రీ గోపిడి గంగారెడ్డి : (నిర్మల్—జనరల్)
అధ్యక్ష మహాశయా !

ఇప్పుడు బడ్జెటుమీద చాలా చర్చ జరుగుచున్నది. ఇది రెండు సంవత్సరములు గడిచి మూడవ సంవత్సరము ప్రారంభమైనది. ప్రధమ సంవత్సరము మేమనుకొన్నదేమంటే ఈ ప్రభుత్వము యింకా బాల్యావస్థలో వున్నది, యింకొక సంవత్సరము పోతే తెలివికలిగి వుండవచ్చును అనుకున్నాము. కాని వయస్సు వచ్చినంతనే ముసలితనము కూడా ప్రారంభమవుతుంది.

[Shri Rami Reddi (Chairman) in the Chair]

యింతవరకు మూడు సంవత్సరములలో ఏమిచేయకేం; యింకా ముందు రెండు సంవత్సరములలోపల

ఏమీచేయగలుగుతుంది అని నాకు అనుమానముగా వున్నది. నాకు ఒక్కనికేకాదు. హైదరాబాదు స్టేటులోని జనులందరికి చాలా విచిత్రకరంగా వున్నది. ఇక్కడ లోకశాయి ప్రభుత్వమేర్పడిన తరువాత ఏ విధముగా బడ్జెటు తయారు చేయబడుతోంది. దానిలో ఖర్చు ఏ విధముగా వున్నది? ఇక్కడమేము చూస్తున్నదేమంటే యింతకు పూర్వమున్న ప్రభుత్వములో ఏ రీతిగా, జరిగెనో అదే విధముగా యీ లోకశాయీ ప్రభుత్వములోను జరుగు చున్నది. చిల్లిబడ్డ కుండ, చీకి పోయిన త్రాడుతో నీరునింపేవని చేసిన ఎన్నటికి ఆ కుండ నిండదు. ఎటువంటి పుణ్యాత్ములుగాని, ఎంతటి మహాత్ములుగాని ఎవరైనాగాని ఆ కుండను ఎప్పటికి నింపలేరు. అందుచేత ప్రభుత్వము మారినా, లోపలవున్న గుణము మారనిదే ప్రయోజనములేదు. మేము గాంధిగారి శిష్యులము, శుద్ధ ఖద్దరు ధారులము—అని చెబితే లాభములేదు. కుండచిల్లిపడింది. ఆ చిల్లులన్నింటిని మూసివేయాలి లేదా కొత్తకుండనైనా చేయాలి. అంతేకాని చిల్లిపడ్డ కుండను ఎంతటి ప్రజ్ఞావంతుడైనా నింప లేడు. కాని ఈ ప్రభుత్వానికి చుట్టము మీద ఆశ, బియ్యము మీద ఆశవుంది. జమీందారులు జాగీర్దారులు వుండాలి, డబ్బు కావాలి, బీదలకు సహాయము చేయాలి, ఆ విధంగా చుట్టము మీద ఆశ, బియ్యము మీద ఆశ కూడా వుండాలంటే దానివలనలాభములేదు. ఇక్కడ మూడు సంవత్సరముల నుంచి చూస్తున్నాము. ఈ శాసన సభలో కనీసము అర్ధభాగము అంగ్రేజీ రాని వారున్నారు. అటువంటి వాళ్లకు ఈ బడ్జెటు పుస్తకాలు ప్రాంతీయభాషలలోనికి తర్జుమాచేసి యివ్వమని కోరితే యివ్వలేదు. శక్తిలేదు అంటారు. కాని ౧౬ మంత్రులను పెట్టడానికి డబ్బు వున్నది. తర్జుమాచేయించి యివ్వడానికి డబ్బులేదంటారు. ఈ బడ్జెటులో ఖర్చుచూస్తే నూటికి ౬౦ వంతులు ఉద్యోగుల ఉదర పోషనానికే వున్నది. కాని దేశము ఎట్లాబాగు పడుతుంది, దానికి ఏ విధముగా బడ్జెటు తయారుచేయాలి అనే విషయం ఆలోచించుటలేదు. ఉద్యోగులకు ధనికులకు సౌకర్యాలు తక్కువని చూస్తున్నారు. ధనవంతుల విస్తరాకులలో అంచున నంచుకునే కూరలు తక్కువవుతాయని చూస్తున్నారు. కుండలో బియ్యము కుండలో వుండాలి, చుట్టాలు కడుపునిండాతిని విస్తళ్లు బయటపారేయాలంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? ముందు మేముకూడా కాంగ్రెసులో వున్నప్పుడు, అప్పుడు మీరు చెప్పిన నీతులు, చేసిన వాగ్దానాలు, అవి అన్నికూడా మరిచిపోయినారు.

అల్పుడైనవాని కధికభాగ్యముగల్గ దొడ్డవారినెల్లదొలగ గొట్టు,
చెప్పుతిన్న కుక్క చెరుకు తీపెరుగునా,
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ.

అని యీమొస్తరుగా ఈ పద్యములో చెప్పబడిన లోకోక్తి అబద్ధముకాదు. ఇదీవరకుండే ప్రభుత్వములో జరిగిన వరిపాలన మనకందరకు తెలుసును. ప్రపంచములోపల వున్నదొంగతనాలు లంజరికాలు, లంచగొండితనాలు యివన్నీ పోవాలంటే, కావాలని మద్యము తయారుచేసి, వాటి నన్నింటిని అణచాలంటే ఎట్లా? మద్యపానము వున్నందువలన మనము ఫలితములు చూస్తున్నా ము. ఖతల్ చేసేవారు నూటికి ౯౦ వంతుల సారా, కల్లు త్రాగనిది వుండరు. దాని ఫలితకు దొంగతనాలు మొదలైనవి. ఈ విధముగా వుంటే మనదేశము ఏ విధముగా బాగు పడుతుంది? గాంధీ మహాత్ముడు ఏమి చెప్పినాడు? మనకు రామరాజ్యము కావాలంటే యిటువంటిదొంగ లక్ష్యాలు వుండకూడదు. ఏదైతే తమరు అబ్కారీ శాఖ అంటున్నారో, దానిని నేను అపకారిశాఖ అని అంటాను. దానివలన ప్రజలకు మేలులేదు. ఈ విధముగా వుంటే లోక కల్యాణము

ఎట్లాజరుగుతుంది ? ఇక్కడ ఏదైనా బిల్లు తెచ్చినప్పుడు బొంబాయిలో అట్లావున్నది, మద్రాసులో యిట్లా వున్నది అని చెబుతారు. కాని ఈ మద్యము విషయములో అక్కడనిషేధము వున్నట్లు ఇక్కడ ఎందుకు చేయరు ? ఏదైనా యితర రాష్ట్రములనుంచి ఉదహారణ తీసుకుంటే మంచి విషయాలు తీసుకోవాలిగాని చెడ్డవిషయాలు తీసుకోరాదు. దానివలన లాభములేదు. దేశము బాగు పడాలంటే దానికి కష్టపడాలి. ఇదివరకు ప్రభుత్వములోని ఉద్యోగులే యిప్పుడు వున్నారు. పోలీసుయాక్షను తరువాత ఏమైనా మార్పు వచ్చినదా ? ఈ ప్రజాతంత్ర పరిపాలనలో ప్రజలకు సుఖము కలుగుతోందా అంటే ఏమిలేదు. దినదినము మనము చూస్తున్నాము లంచగొండితనము మిక్కిలి అధికమౌతోంది. మేము పల్లెలలో చూస్తున్నాము. గిర్దావర నడిగితే ఈ లంచగొండితనము మీదనుంచి వుందని చెబుతాడు. దీపము క్రింద చీకటి లేదు. దీపము పైన చీకటి వున్నది. మీద నుంచికూడా లంచగొండితనము వస్తోంది. పోలీసుయాక్షనుకు ముందు మిర్జా ఇస్మాయిల్ ముఖ్యమంత్రిగా వుండేవారు. ప్రతి పల్లెలోను పటేలు పట్వారీలుకూడా భయపడేవారు. ఉద్యోగస్తులందరికీ తెలుసు. లంచము అంటే భయముగావుండేది ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ప్రజలచే ఎన్నుకొనబడివచ్చిన ఘన మంత్రులైనారు. కాని పరిపాలన ఏవిధముగా సాగుచున్నది ? మా హాల్కాలో ఒక కేసు వున్నది. అక్కడ ముంతజం, ఎవరైతే చంపబడెనో వాని భార్యనుంచి వెయ్యి రూపాయలు లంచము తీసుకున్నాడు. అ కేసు ట్రిబునల్ వేయబడి నడుస్తున్నది. ఇటువంటి లంచగొండితనం విషయమై గౌరవమంత్రులందరికీ తెలుసు. ఇందులో ఎవరికి తెలియనిది లేదు. లంచగొండి తనాన్ని నిజంగా అణచాలని మీరు తలచుకుంటే ఒక వారము లోపల అణిగి పోతుంది. కాని యిష్టము లేదు. నేను ముమ్మాటికి చెబుతున్నాను. మీరు యిష్టపడరు. ఇక్కడ ౧౩ మంత్రులను ౧౦ చేసి, ౧౦ మందిని ౧౬ చేసే శక్తిమీకుంది. లంచగొండితనమును కూడా ఆపివేయదలచుకుంటే ఒక వారము రోజులలోపల ఆగిపోతుంది. మీరు గట్టిగా గాంధీమహాత్ముని పేరుచెప్పి, ఛాతీమీద చేయివేసుకొని చెప్పండి. మీరు ఈ లంచగొండితన్నాన్ని అణచదలచుకుంటే ఒక-వారము రోజులలో అణచివేయవచ్చును. కాని మీరు చేయదలచుకోలేదు. ప్రజలకు చెప్పినదంతా సీటుమీద వచ్చి కూర్చున్నతరువాత మరచిపోయారు. ఒకసారి వెనక్కు తిరిగి చూసుకోండి. ప్రజాపరిపాలన వచ్చి ఏమిమేలుచేసింది ? దేశము బాగు పడాలంటే ఎన్నోపనులు చేయవలసియున్నది. మంచి పరిపాలన చేసి ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయవచ్చును. మిగతా రాష్ట్రములకు మనము మార్గదర్శకులము కావచ్చును. మనపేరు ఇతిహాసములో వుంటుంది. కాని అది చేయదలచుకోలేదు. ఇంకా ఇక్కడమేము చూస్తున్నాము, ఎటువంటి చిత్తమో అటువంటి లక్ష్యము వుంటుంది. ఎటువంటి లక్ష్యమో అటువంటి గుణము వుంటుంది. కాంగ్రెసువారికి మహాత్మాగాంధి చెప్పినదేమిటి ? వారినినాదాలేమిటి ? దున్నే వానికే భూమి అని చెప్పి ఈనాడు వాళ్ళకు క్షేమకరంగా చేసిన దేమున్నది ? ఏమీలేదు. వాళ్ళకు ఖాస్రా ఫారముల విషయములో ఏమౌతున్నదో చూడండి. గొంగలి కప్పుకుపోయి చూడండి. మనకు రామరాజ్యము కావాలంటాము. రామరాజ్యములో రాముడు ఏమిచేసినాడు ? ప్రజల కష్టసుఖములు తెలుసుకొనేందుకు గొంగళికప్పుకొని వీధివీధి తిరిగేవారు. అన్నివిషయాలు తెలుసుకొనేవారు. ఈ మంత్రులు టూరుకు పోయేముందు కలెక్టర్లకు తెలుపుతారు. ఫలానీ తేదీన మంత్రివస్తున్నారు, ఫలాని చోట పర్యటనము చేస్తారు, ఫలాని చోట భోజనము చేస్తారు, ఫలాని చోట బహిర్దేశానికి వెళతారు అని తెలియ పరచడం జరుగుతోంది. కాని ఉద్యోగులకు తెలియకుండా, కంబళ్ళు కప్పుకొనిపోయి చూడండి. ఖాస్రాఫారముల విషయములో లంచగొండి

తనము ఎంతజరుగుతున్నదో చూడండి. ఒక్క సర్వే నెంబరులో ౬౦ మంది పొతున్నవారున్నారు. వారందరికి ఒకటే ఫారము. ౬౦ ఫారములులేవు. డబ్బులు యిస్తే రిజిస్టరు చేసి దానికన్న ఎక్కువ విలువగా భర్తీ చేస్తున్నారు. ప్రజలకు లాభము కలుగజేస్తున్నమనుకుంటున్నారు. కాని అక్కడ పరి పాలనలో అ విధముగా నడుస్తోంది. బస్సుల విషయములో చూడండి. అదికూడా చాలా అన్యాయముగా వున్నది. మేమందరము బస్సులలోనే పోతాము. ఇప్పుడున్న మంత్రులు బస్సులుఎక్కరు. మేము పూర్వము రీతిగానే ఎక్కుతున్నాము. కాని వాటిల్లో ఏమీ మార్పు రాలేదు. పూర్వము మాదిరిగానే పరిపాలన నడుస్తోంది. కాని మీరు చేయదలచుకుంటే మార్పు తీసుకురావచ్చును, కాని ఏమీ చేయుటలేదు, జంగ్లాత్ విషయములో చూస్తున్నాము. కాగితాలమీద ఒకటి, అనుభవములో ఒకటి జరుగుచున్నది. అధికారము వున్నవారికి అనుభవములేదు. అనుభవమున్నవారికి అధికారములేదు. ఎద్దు వున్నవానికి బుద్ధిలేదు. బుద్ధి వున్న వానికి ఎద్దులేదు; అని లోకోక్తి వున్నది. జంగ్లాత్ విషయములో చూస్తే, చౌకీదార్ల విషయము చెబుతాను. ఒకసారి గౌరవనీయమంత్రి గారు నిర్మల్ తాలుకాకు వచ్చినప్పుడు దాని ప్రక్కన ౬ మైళ్లదూరములో వున్నప్రాంతము చూద్దామంటే "లేదండి, మాకు కమిటీ ఉన్నది" అన్నారు. అయితే జంగ్లాత్ లోపల ఎన్ని చెట్లు వున్నవి? ఎన్ని కొట్టబడుచున్నవి, అక్కడ మేకలు అవ్వీ ఎక్కడ మేస్తున్నవి? మేము చూస్తున్నాము అక్కడ చౌకీదారు పైన సహెరాదారుంటారు, అమీన్‌సాబ్ వుంటాడు, పైన మదద్‌గార్ వుంటాడు, అక్కడ కిందనుంచి మీదదాకా లంచగొండితనంవుంది. అడవి ప్రాంతాల్లో, పక్కన వుండే గ్రామాల్లోని మేకలు ఎక్కడ మేస్తున్నాయి? ఆకాశములో మేస్తున్నాయా? మన వద్ద సి. ఐ. డి. గుప్త రహస్య భటులున్నారు, వారు ఏమిచేస్తున్నారు? ఎక్కడ మేస్తున్నారు? ఏమి తెలియదు. మన చేతుల్లోకి ప్రజారాజ్యము రాక పూర్వము మనకున్న ఉల్లాసము, ఊహ గనుక యిప్పుడుంటే ఎంతో మేలు జరిగేది. కాని అదేమీ యిప్పుడు కనబడటం లేదు. అక్కడ ఒక్కొక్క మేకకు నాలుగు రూపాయల చొప్పున యిచ్చి అడవిలో మేపుకుంటున్నారు. ఇది మదద్‌గారుకు తెలును. అక్కడ పిల్లచౌకీదారులుంటారు. మేము ప్రశ్న వేస్తే "మాకు ఆర్డర్లు వున్నాయి" అని చెప్పారు. అక్కడ అందరికీ తెలుసు, అడవి అంతా సత్యానాశ్ అవుతోందని తెలుసు. కాని ఈ ప్రభుత్వము వచ్చిన తరువాత కూడా ఏమీ అక్కడమార్పులేదు. పూర్వపు రీతిగానే నడుస్తోంది పూర్వము ప్రభుత్వములో వున్నవారు యిప్పుడు వున్నారు. వారి అధికారము పోయినదని చెప్పి హృదయములోపల కపటములేకుండా ... ...

శ్రీ రామిరెడ్డి: అసలు విషయమును గురించి మాట్లాడండి.

శ్రీ గంగారెడ్డి:—జంగ్లాత్ విషయం బడ్జెటులో వుంది. దానిని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. పోలీసులు వున్నా వారివలన మేలు ఏమంటే యిప్పుడు చూస్తున్నాము, ఎన్నోఖతల్‌లు అవుతున్నాయి. మేము ప్రభుత్వములో ఖతల్‌లు కానివ్వకుండా చూడమని చెబుతున్నాము. మధోల్ తాలూకాలో ౪౦ ఖతల్‌లు అయినాయి. అవి ఎందుకు అవుతున్నాయి? గొడ్డలిపెట్టి కొనుకొనే ఖతల్ రోగము వుట్టినదా? ఆ హత్యలు, జులుమ్ ఆపుచేయమని దరఖాస్తుపెడితే ఏమీ చర్య తీసుకోలేదు, మేము కూడా విసుగు చెందాము.

ఇప్పుడు విద్యాశాఖను గురించి చెబుతాను. దీనిని గురించి ఇదివరకు అనేకసార్లు చెప్పాను. ఒక ఉపాధ్యాయున్ని ౫౦ ఏండ్లనుంచి ఒకచోటనే ఉంచుతున్నారు. ఇంకోచోట, పంతుళ్ళను రెండు మూడు మాసాల కొకసారి, అక్కడనుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడినుంచి అక్కడికి వేస్తారు. దీనిని గురించి

నేను అనేకసార్లు ప్రశ్నలు వేశాను. ప్రభుత్వము బదనామి కాకుండా ఉండాలంటే మేం అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి సరైన సమాధానాలు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పద్ధతి చూస్తే, " పిల్లి కళ్లు మూసుకొని పాలు త్రాగుతు, తనను ఎవరూ చూడటం లేదని అనుకొన్నట్లు " ఉన్నది. పిల్లి కళ్లు మూసుకొనే పాలు త్రాగుతుంది. కాని పాలన్నీ అయిపోతాయి. ఓరాయిత్ విషయం బీదల విషయం మన ప్రభుత్వము ఆలోచించడంలేదు. మనుష్యులకు వైద్యము చేసేటటువంటి వాళ్లే లేరుగాని ఇక, పశువులకు చెట్లకు ఇంజక్షన్సు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పశువుల ఆరోగ్యం విషయం ఎవరు చూసున్నారు? కాని ఎలక్షన్స్ వచ్చినపుడు మాత్రం ఎద్దుబొమ్మ పెట్టుకొంటే సరిపోతుంది. అంతేగాని, పశువులకు వైద్యం చేసేందుకు పశువుల వైద్యశాలలుగాని, పశువులకు బలం శక్తి కలగచేసే విషయమైగాని అందుకొరకు ప్రభుత్వము ఏమీ ప్రయత్నించడం లేదు. పూర్వపు పరిపాలన ఎట్లా ఉన్నదో, ఇప్పుడు యీ కాంగ్రెసు పరిపాలన అట్లాగే ఉన్నది. పూర్వము రాజు వుంటే, ఇప్పుడు ఆ రాజు రాజప్రముఖ్ అయినాడు. అదే పొలము, అదే చెట్టు చెట్టు అదే వుంటే పండ్లు వేరే ఎట్లా వస్తాయి? అదే చెట్లకు మంచిఎరువులు వేసినా వేరే మంచి పండ్లు ఎలా పండుతాయి? పూర్వం ప్రభుత్వము ఎవరి క్రిందనైతే ఉన్నదో, ఇప్పుడు వారిక్రిందనే ఉన్నది. పూర్వము రాజు క్రిందనే యీ ప్రభుత్వము ఉండబట్టి దీని నీతి కూడ అలాగే ఉన్నది.

ఇక, ఔషధాల విషయం చూస్తే, వైద్యులకు సనదు ఉంటాయి. సనదు లేనివారు కూడా వైద్యము నేర్చుకొని చేస్తున్నారు. పోలీసుశాఖను చూస్తున్నాము. ఈ శాఖ కానూన్‌లను ఎలా అమలు జరుపుతోందో చూడవలసిఉన్నది. బాల్యవివాహ నిషేధము కానూన్ మన స్టేటు లోపలగూడ పెట్టారు. ఇప్పుడు యీ బాల్య వివాహ నిషేధము కానూన్ ప్రకారము యీ స్టేటు లోని ఎన్ని కేసులను పట్టుకొన్నారు?—అనేది చూస్తే ప్రభుత్వము ఏమీ కేసులను పట్టుకోలేదు. కాని గ్రామాలలోపల ఎన్నో కేసులు జరుగుతున్నాయి. గ్రామాలలోపల కొన్ని వేల బాల్యవివాహాలు జరుగు తున్నాయి. వీటిని గురించి ప్రభుత్వము ఏమి చేసింది? ఈ స్టేటులో కూడా ఆ కానూన్ పెట్టించాము, కాని లాభం ఏమిటి? మనం ఏన్నో కానూన్‌లు తెచ్చాం, అవి ఏవీ సరిగా అమలు జరగడంలేదు. అవన్నీ పూర్వం లాగానే ఉన్నవి. కానూన్‌లను సక్రమంగా అమలుపర్చడం కోసం ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం వచ్చింది. కాని యీ ప్రభుత్వములో కూడా కానూన్‌లు సరిగా అమలుజరగడంలేదు. అట్లాగే బాల్యవివాహనిషేధం కానూన్ అమలు జరగడం లేదు. ఈ కానూన్‌గురించి గ్రామాలలో దండోరా వేస్తే అందరికి దీనినిగురించి తెలుస్తుంది.

హరిజనుల విషయమై మేలు చేశామని చెప్పారు, హరిజనులకు ఏమి మేలు చేశారు? బ్రాహ్మణుడు బయటి స్టేటునుంచి వచ్చి, తాను హరిజనుడనని చెప్పుకొంటే, ఆ బ్రాహ్మడికి హరి జనుడని చెప్పి ఒక పదవి కట్టబెడుతోంది. అంతేగాని అసలైన మాలవానికి ఏమి చేసింది? మాలమాదిగలకు సర్కార్‌వారు ఏమీ సౌకర్యాలు చేయడంలేదు. ఖారీజ్ కాతా భూములు, పోరంబోకు భూములను ఎంతో కాలం జాగీరుదార్లు పీల్చిపిప్పిచేసిన భూములను హరిజనులకు కట్టబెట్టారు. ఖారీజ్‌కాతా భూములలోని సారము అంతా పీల్చేసిన తరువాత సారము లేని భూమిని తిని పారేసిన విస్తరి ఇచ్చినట్లుగా హరిజనులకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూస్తున్నాము, దేశంలో ధనవంతులు ఒక కన్ను, బీదవాళ్లు ఒక కన్ను, ఈ రెండు కళ్ళను సమానంగా చూడాలి. [illegible] లో " हिंदू मुस्लीमों के लिये दोनों मेरी " आखें अेक है।

అన్నట్లుగా ఉంది. ఈ విధముగా హారిజనులకు తిని పారేసిన విస్తరి లాంటి భూములు ఇచ్చినందున, ఆ తిని పారేసిన విస్తరిలోని పుల్లలు వారి నోట్లో గుచ్చికొని ఎంతోమంది మరణించారు. ఈ విధముగా ఉన్నది. ఖారిజ్‌కాతా భూములను హారిజనులకు ఇవ్వడంలో ఆలస్యం అవుతోంది, వీరికి భూములు ఇవ్వడంలో చివరకు, రెవిన్యూబోర్డుదాకా పోవాలి. ౮౦ ఎకరాల భూమిని ఒక గ్రామంలోని మాలమాదిగలు చేసుకొంటే, ఆ గ్రామంలోని కాపు వారినుంచి భూమిని లాక్కొని ఆ భూమినుంచి వెళ్లగొట్టటానికి గుంజాయిష్ లేకుండా ఉంది. ప్రభుత్వం చెప్పేది ఒకటి; చేసేది ఒకటి. ఈ విధముగా ఉంది. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏ విధముగా పోయి ప్రజలకు చెప్పివచ్చాము?—అనేది చూడాలి.

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

ఇక, విద్యావిషయం చూస్తే చదువు విషయమై ప్రభుత్వమువారు చాలా శ్రమపడుతున్నారని అంటున్నారు. ఒక సంగతి చెబుతాను. మా గ్రామం సంగతి చూస్తే విచిత్రంగా ఉంది. మా ఊళ్లో బడి నిర్మాణం చేస్తున్నారు. కట్టడానికి కంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు. కొన్నిచోట్ల రూపాయికి పావలా, రూపాయికి ఎనిమిది గండాలు కంట్రిబ్యూషన్ చేయమనిచెప్పారు. మా గ్రామానికి చదువుకొనేందుకు ౮౦ మంది పిల్లలు వస్తున్నారు. కాని, వారికి చదువు చెప్పడానికి ౫ మాసాల నుంచి పంతుళ్లు లేరు. మెహజరు పెట్టుకొంటే ఇద్దరు పంతుళ్లను తోలారు. వారికి వుండటానికి ఇళ్లు లేవు. వారికి ఏమి సౌకర్యాలు లేవు.

ఆహారం విషయం చూడండి. అన్నంతినేచోట జొన్నలు పంపుతున్నారు. జొన్నలు తినేచోట బియ్యం పంపుతున్నారు. విద్యావిషయంలోగాని, మంత్రులు దౌరా విషయంలోగాని మార్పు రావాలి.

ఈ గ్రెయిన్‌బ్యాంక్ రజాకార్ల ప్రభుత్వములో ఎలా ఉందో యీ ప్రభుత్వములోనూ అలాగే ఉంది. దీని విషయం ఆలోచించడములేదు. మన ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చినాక కూడా........

مسٹر ڈپٹی اسپیکر- آپ اور کتنا وقت لینگے ؟

مسٹر ڈپٹی اسپیکر مجھے اب کچھ اناؤنس (Announce) کرنا ہے - کس منسٹر کے ڈیمانڈس فار گرانٹس (Demands for grants) کس تاریخ کو پیش کئے جائینگے وہ میں سلسلہ وار سنانا چاہتا ہوں -

श्री. गोपिडी गंगा रेडी : —मैतो और दो चार विषयों पर बोलना चाहता हूं । मुझको यदि कलमौका दिया जायेगा तो मैकल शुरुमें बोलुगा ।

[Statement.

The order in which the Demands for Grants will be taken up for discussion.

DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1954-55.

	Timings of the House	Minister-in-charge	Demand Numbers	Day and date on which the Demands will be taken up for discussion	Date and time of giving notice of motion for reduction
1.	2-30 to 8 p.m.	Chief Minister	14,47,48,54,55,56,62, 68 and 74.	Thursday, the 11th and Friday, the 12th March 1954.	9th March, 1954 5 p.m.
2.	2-30 to 8 p.m.	Minister for Home, Law and Rehabilitation.	8,16,18,19,20,61,75, 79,80,81 and 93.	Monday, the 15th and Tuesday, the 16th March 1954.	13th March, 1954 4-30 p.m.
3.	2-30 to 8 p.m.	Minister for Agriculture, Supply, Development and Planning.	32,44,49,70,78,83 and 95.	Monday, the 22nd March 1954	17th March, 1954 4-30 p.m.
4.	2-30 to 8 p.m.	Minister for Public Health, Medical and Rural Reconstruction.	26,27,33,34,35 and 37	Tuesday, the 23rd March, 1954.	17th March, 1954 4-30 p.m.
5.	2-30 to 8 p.m.	Minister for Education and Local Government.	15,22,24,25,30,31,41, 42,53,57,69,72,85 and 90.	Wednesday, the 24th March, 1954	22nd March, 1954 4-30 p.m.
6.	2-30 to 8 p.m.	Minister for Excise, Forests and Revenue.	2,3,4,6,7,58,71,73 and 76.	Thursday, the 25th March, 1954	23rd March, 1954 4-30 p.m.
7.	9 a.m. to 12 Noon & 4 p.m. to 8 p.m.	Minister for Public Works and Labour.	11,12,13,23,28,29,38, 39,43,46,52,59,60, 67,84,86,87,88,89,91 and 92.	Friday, the 26th March, 1954.	24th March, 1954 4-30 p.m.
8.	9 a.m. to 12 Noon & 4 p.m. to 8 p.m.	Minister for Finance, Statistics, Customs, Commerce & Industries.	1,5,9,10,17,21,36,40, 45,50,51,63,64,65,66 77,82,94,96 and 97.	Monday, the 29th March 1954.	26th March, 1954 4-30 p.m.

The House then adjourned till Half Past Two of the Clock on Tuesday, the 9*th March,* 1954.
